



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

No. 115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2006/ज्येष्ठ 12, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2006/JYAISTHA 12, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2006

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया और ई यू (फ्रांस को छोड़कर), के मूल से अथवा वहां से निर्यातित कार्बोस्टिक सोडा के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच (मध्यावधि समीक्षा)

सं. 15/5/2005-डीजीएडी.—जबकि, 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल से अथवा वहां से निर्यातित कार्बोस्टिक सोडा (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश की है। प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 8 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 14-39-2002-डीजीएडी में प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 27-3-2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार संबद्ध वस्तुओं पर अनंतिम शुल्क लगाया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 01-10-2003 को अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया था और दिनांक 14-11-2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. और जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को मै. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से एक याचिका प्राप्त हुई थी, जिसमें पाटन एवं क्षति के कारण स्थिति में परिवर्तन आने के कारण, परिवर्तित स्थिति में समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातक की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर, दिनांक 03-06-2006 को उपर्युक्त देशों पर लगाए गए शुल्कों के संबंध में पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच प्रारंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए दिनांक 27-3-2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना में अधिसूचित शुल्क का निरंतर अधिरोपण आवश्यक होगा, और यदि शुल्क को समाप्त किया जाता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है तो क्या क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

3. अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जरिए मै. इंडियन प्रोड्यूसर द्वारा दायर याचिका के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से कॉस्टिक सोडा के आयातों में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों की मौजूदगी के विषय में एक जांच की थी और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के सकारात्मक निर्धारण के आधार पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं. 14/39/2002-डीजीएडी के अनुसार अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया है। प्राधिकारी ने जांच परिणामों के अनुसार कार्यवाही करते हुए केंद्र सरकार ने दिनांक 14.11.2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था। वर्तमान जांच मै. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मुंबई द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर शुल्क के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने हेतु दिनांक 03/06/2005 को शुरू की गई है।

ख. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा जाएगा) को उपर्युक्त नियमों के तहत, मै. हिंदुस्तान लीवर लि. से एक याचिका प्राप्त हुई जिसमें, परिवर्तित परिस्थितियों का हवाला दिया गया है और चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉस्टिक सोडा (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे कि पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने दिनांक 03.06.2005 को भारत के राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई कि चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया और फ्रांस को छोड़कर यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या मौजूदा शुल्कों के अधिरोपण को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और क्या उन्हें समाप्त किया जा सकता है, पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की है।

(iii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और/अथवा निर्यातकों को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तिथि से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:

(iv) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों और/अथवा उपयोक्ताओं को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तिथि से

चालीस दिनों के भीतर संगत सूचना उपलब्ध कराने और अपने विचारों से अवगत कराने का सुझाव दिया ।

(v) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता से जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भारत द्वारा संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

(vi) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावासों/क्षेत्रों को याचिका के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध कराई थी । अगोपनीय याचिका की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध पर उपलब्ध कराई गई थी ।

(vii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों सहित संबद्ध देशों की सरकारों को संगत सूचना प्राप्त करने हेतु एक प्रश्नावली भेजी थी । चीनी टाईपेई के एक निर्यातक, मै. फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉरपोरेशन, ताईवान ने उचित रूप से बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली में अपना उत्तर प्रस्तुत किया था ।

(viii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थी । निम्नलिखित पक्षकारों ने अपना उत्तर दायर किया है :-

क. मै. नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि.,

प्राधिकारी ने जांचाधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और ज्ञात प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों को पाटन, क्षति और, उसके कारणों के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने हेतु अवसर प्रदान किया था ।

(ix) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु 29 नवंबर, 2005 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया था, जिसमें याचिकाकर्ता, घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि, फॉर्मोसा प्लास्टिक्स और अन्य हितबद्ध पार्टियां उपस्थित थीं । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पार्टियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों और सूचनाओं के बारे में लिखित निवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया था । हितबद्ध पार्टियों का अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों/सूचनाओं का खंडन करते हुए तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राप्त लिखित निवेदनों पर विचार किया है ।

(x) जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क और सूचना/साक्ष्य, यदि प्रमाणों द्वारा समर्थित हैं और उन्हें वर्तमान जांच के लिए संगत समझा गया है तो वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा उन पर उचित रूप से विचार किया गया है ।

(xi) जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना जिन पर ये जांच परिणाम आधारित हैं की सतर्कता के विषय में पूरी जांच कर ली थी । इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक विदेशी उत्पादक, घरेलू उत्पादक और उपभोक्ताओं का मौके पर सत्यापन किया है । क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग से अतिरिक्त ब्यौरे मंगवाए गए थे, जो प्राप्त हो गए थे ।

(xii) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अगोपनीय प्रति को प्राधिकारी द्वारा रखी जाने वाली एक सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

(xiii) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में उत्पादन की इष्टतम लागत और संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बेचने का लागत का निर्धारण करने के लिए लागत जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से कम होता है तो यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(xiv) उपर्युक्त नियम 16 के अनुसार, इन जांचों के लिए आवश्यक तथ्य/आधार को दिनांक 2/05/2006 को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और प्राप्त टिप्पणियों पर इस जांच में उचित रूप से विचार किया गया है;

(xv) 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2004 (12 महीने) तक जांच की गई थी और इसे जांच अवधि (पीओआई) कहा गया है । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच अप्रैल, 2001-मार्च, 2002, अप्रैल 2002-मार्च, 2003 और अप्रैल, 2003-मार्च, 2004 तथा पीओआई की अवधियों में की गई थी ।

(xvi) **** यह चिन्ह इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का द्योतक है और इसलिए इस पर प्राधिकारी द्वारा योग्यता संबंधी नियम के अंतर्गत विचार किया गया है । विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के संबंध में उनके दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर की गई थी । संतुष्टि होने पर प्राधिकारी ने, जहां आवश्यक हो, गोपनीयता प्रदान की है, और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया है तथा दूसरी हितबद्ध पार्टियों पर प्रकट नहीं किया गया है । जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाली पार्टियों को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की पर्याप्त अगोपनीय प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । वर्तमान जांच के दौरान हितबद्ध पार्टी ने जहां भी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से मना किया है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, तो प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किया है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु:

ख.1 हितबद्ध पार्टियों के विचार

5. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि:

क. वर्तमान समीक्षा जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच है। मूल जांच और वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है जिसे सामान्यतः कॉस्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। रासायनिक तौर पर कॉस्टिक सोडा एनएओएच के रूप में जाना जाता है। यह एक अकार्बनिक रसायन है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 में वर्गीकृत है। कॉस्टिक सोडा साबुन जैसा, अत्यधिक क्षारीय, गंधहीन तरल है जिसका विविध औद्योगिक क्षेत्रों में, कच्ची सामग्री अथवा एक अनुषंगी रसायन की तरह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः लुग्दी और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमीनियम, कपास, वस्त्र, प्रसाधन और कपड़े धोने के साबुनों, प्रक्षालकों, रंजक सामग्री, औषध एवं भेषज, वनस्पति, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि में किया जाता है। कॉस्टिक सोडा का उत्पादन दो स्वरूपों में किया जाता है- लाई और ठोस पदार्थ। ठोस कॉस्टिक सोडा, पपड़ी, प्रिल, दोनों अथवा अन्य किसी स्वरूप में हो सकता है। कॉस्टिक सोडा के सभी स्वरूप वर्तमान याचिका की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। विचाराधीन उत्पाद और समान उत्पादों से संबंधित मुद्दों की जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में विस्तारपूर्वक की गई थी और इसकी पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल में कहा था कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्यक्षेत्र की समीक्षा, एक समीक्षा मामले में किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय उत्पादकों ने निवेदन किया है कि इस स्तर पर विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्यक्षेत्र की जांच की आवश्यकता नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का आयात लाई और ठोस, दोनों स्वरूपों में किया जाता है। लाई स्वरूप के आयात का नौवहन आकार कम से कम 500 मी.टन अथवा उसका गुणज होता है। भारतीय उत्पादकों ने निवेदन किया है कि लाई और ठोस स्वरूपों की संबद्ध लागतों और कीमतों में अंतर होता है। चूंकि जांच अवधि के दोनों कॉस्टिक सोडा के दोनों स्वरूपों का आयात किया गया है, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी तदनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण कर सकते हैं।

ख.2 याचिकाकर्ता, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार:

6. याचिकाकर्ता, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टियों ने निवेदन किया है कि:

क. मै. नाल्को ने निवेदन किया है कि कॉस्टिक सोडा लाई और ठोस/पपड़ी अलग उत्पाद है और वर्तमान जांच के लिए उन्हें समान उत्पाद नहीं माना जा सकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि कॉस्टिक सोडा के लाई स्वरूप का उपयोग विश्व भर के एल्यूमीनियम उद्योग में एल्यूमिना के उत्पादन हेतु किया जाता है; अतः ठोस/पपड़ी, लाई कॉस्टिक सोडा के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। लाई और ठोस के बीच यह अंतर है कि लाई में कॉस्टिक सोडा का सांद्रण कम है जबकि ठोस स्वरूप में कॉस्टिक सोडा का सांद्रण बहुत

अधिक है । अतः यह निवेदन किया गया है कि ठोस/पपड़ी और लाइ कॉस्टिक सोडा को समान उत्पाद नहीं माना जा सकता । अतः कॉस्टिक सोडा लाइ को विचाराधीन उत्पाद माना जाना चाहिए । बाजार मूल्य, हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन इत्यादि के साथ उनके उपयोग में भी अंतर है ।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच:

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीनी ताइपेई, इंडोनेशिया और ईयू (फ्रांस को छोड़कर) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रॉक्साइड है (रासायनिक नाम एनएओएच) है, जिसे सामान्यतः कॉस्टिक सोडा कहा जाता है (वर्तमान जांच में कॉस्टिक सोडा कहा गया है)/जांचाधीन उत्पाद, वह उत्पाद है जिसे मूल जांच में भी जांचाधीन उत्पाद माना गया था । कॉस्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुन जैसा, अत्यधिक क्षारीय और गंधहीन रसायन है जिसका इस्तेमाल लुग्दी और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमीनियम, कपास, वस्त्र प्रसाधन और कपड़े धोने के साबुनों, प्रक्षालकों, रंजक सामग्री, औषध एवं भेषज, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि में होता है । कॉस्टिक सोडा का उत्पादन दो स्वरूपों अथवा लाइ एवं ठोस स्वरूपों में तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात् मरक्युरी सेल प्रक्रिया, डायाफ्राम प्रक्रिया और मेम्ब्रेन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है । प्रक्रियाओं में अंतर से उत्पाद की विशेषताओं में कोई अंतर नहीं आता है । कॉस्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 में सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत वर्गीकृत किया गया है । आईटीसी आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1110, 2815.1120 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत किया गया है । तथापि यह वर्गीकरण सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

8. यह नोट किया गया है कि कॉस्टिक सोडा का उत्पादन एवं बिक्री प्रारंभिक रूप से लाई के रूप में होती है । चूंकि इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, कम संघनन में होने के कारण उच्च परिवहन लागत का भुगतान करने के बाद भी लाई के रूप में परिवहन का परिणाम उपभोक्ता के लिए कम प्रभावी लागत के रूप में होता है जबकि फ्लेक में रूपांतर से प्रयोक्ता पर अतिरिक्त लागत का भार पड़ता है । कॉस्टिक सोडा के ठोस रूप का प्रयोग उसी प्रकार के कार्यों एवं प्रयोगों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए लाई रूप की आवश्यकता हो । यह नोट किया गया है कि कीमतों में अंतर संघनन में भिन्नता, परिवहन लागत और ठोस रूप के लिए अपेक्षित वृद्धिकारक रूपांतरण लागत के कारण है । कॉस्टिक सोडा के दो भिन्न रूपों में अंतर होने के कारण वे दो अलग-अलग उत्पाद नहीं बन जाते हैं अपितु उत्पाद आवश्यक रूप से समान उत्पाद विशेषताओं के साथ कॉस्टिक सोडा ही रहता है । तथापि, कीमतों में भिन्नता के मद्देनजर, निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य और गैर-क्षतिकारक कीमत के साथ पहुंच मूल्य की तुलना के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भौतिक रूपों में भिन्नताओं पर विचार किया है और दोनों रूपों की अलग-अलग तुलना की है । लाई तथा ठोस रूप के लिए पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण अलग-अलग सामान्य मूल्य तथा गैर-क्षतिकारक कीमतों का निर्धारण किया गया है । तथापि, नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने उचित तुलना को सुनिश्चित करने के पश्चात् पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन के भारित औसतों पर विश्वास किया है ।

9. यह निर्धारित करने के लिए क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित और/अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु मानी जा सकती है, प्राधिकारी ने भौतिक एवं तकनीकी विशेषताएं, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य एवं प्रयोग, कीमत, उपभोक्ता का ज्ञान आदि जैसे कई संगत मापदंडों पर विचार किया। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित और/अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। दोनों वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू तौर पर उत्पादित और आयातित वस्तुओं का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है और किया जा सकता है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए और आवश्यक उत्पाद विशेषताओं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु से संबद्ध देशों से नियोजित वस्तुओं की प्रतिस्थापनीयता तथा एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया है कि माननीय सेस्टेट ने समान वस्तु के संबंध में प्राधिकारी के निर्धारण को बरकरार रखा है और वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ग. घरेलू उद्योग:

ग.1 घरेलू उद्योगों के विचार:

10. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि:

क. वर्तमान प्रस्तुतीकरण भारतीय एल्कली विनिर्माता एसोसिएशन (ए एम ए आई) द्वारा और उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया है। भारत में कॉस्टिक सोडा के सभी उत्पादक एएमआई के सदस्य हैं। भारत में संबद्ध वस्तु के कई विनिर्माताओं ने लागत संबंधी सूचना सहित क्षति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। इस तर्क का कोई कानूनी और तथ्यात्मक आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग का संघटन वही बना रहना चाहिए जो मूल जांच तथा उसकी परवर्ती जांचों में था।

ग.2 आवेदक, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. हितबद्ध पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि इस निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग का संघटन ऐसे किसी परिवर्तन के लिए किसी कानूनी या तथ्यात्मक कारण के बिना बदल गया है। अतः, भागीदार कंपनियों द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में व्यवहार किया जा रहा है जबकि उनमें से अधिकतर क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच:

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग का अर्थ है घरेलू उत्पादक जो समान वस्तु के विनिर्माण में तथा उनसे जुड़े किसी कार्य-कलाप में लगे हों अथवा

वे जिनका कथित वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हो सिवाय इसके कि ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा वे स्वयं उनके आयातक हों, इस स्थिति में ऐसे उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं समझे जाएंगे ।"

13. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योग को क्षति (और उसकी सीमा) के निर्धारण के संगत पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई है :-

- क. मै. बिहार कॉस्टिक्स एंड केमिकल्स लि.,
- ख. मै. डीसीडब्ल्यू
- ग. मै. गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लि. (बड़ोदरा एवं दाहेज),
- घ. मै. भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि.,
- ङ. मै. जयश्री रसायन लि.,
- च. मै. पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स लि.,
- छ. मै. श्रीराम एल्कलीज एंड केमिकल्स लि.,
- ज. मै. स्टैंडर्ड एल्कलीज एंड केमिकल्स लि.,
- झ. मै. सिएल केमिकल कॉम्पलेक्स,
- ञ. मै. सोरारिस केमटेक लि.,

14. प्राधिकारी ने इस मध्यावधि समीक्षा जांच में जांच अवधि के दौरान भागीदार उत्पादकों का उत्पादन 911244 मी. टन निर्धारित किया है । अतः भागीदार उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उद्योगों द्वारा लिए गए उत्पादन के 50% से अधिक है । अतः प्राधिकारी मानते हैं कि ये कंपनियां नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं । जांच की प्रक्रिया के दौरान और प्रकटम विवरण संबंधी टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ऐसे किसी परिवर्तन के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक कारण दिए बिना वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग का संघटक परिवर्तित हो गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किसी समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग का संगठन/क्षेत्र मूल जांच के समान क्यों रहना चाहिए । यह भी नोट किया गया है कि ऐसी कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है कि मध्यावधि समीक्षा जांच और मूल जांच में घरेलू उद्योग का क्षेत्र और संगठन एक ही रहना चाहिए ।

घ. अन्य मुद्दे

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि:

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी को लागत लेखा रिकॉर्ड्स नियमावली के संगत प्रावधानों के साथ-साथ इस बात का निर्णय करते समय कि क्लोरीन कॉस्टिक सोडा का संयुक्त उत्पाद अथवा सह-उत्पाद है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्ववर्ती निर्धारण पर विचार करना चाहिए ।

(ख) वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में समीक्षा की अवधि में अधिकतर आर्थिक मापदंडों में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।

(ग) यह दावा कि यदि घरेलू उद्योग में सुधार हुआ है तो शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिए, को पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 11.3 और भारतीय पाटनरोधी कानूनों की धारा 9क(5) और नियम 23 में यथानिर्धारित मध्यावधि समीक्षाओं के प्रयोजन के संगत नहीं माना जा सकता है ।

(घ) मध्यावधि समीक्षा प्रारंभ करने का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि क्या शुल्क की समाप्ति अथवा उसमें परिवर्तन से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना है ।

(ङ) घरेलू उद्योग ने निर्धारित प्रपत्र में पाटन एवं क्षति से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है । घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंडों के विश्लेषण से यह स्थापित होता है कि कौस्टिक सोडा उद्योग में किए गए भारी निवेश को देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा वित्तीय स्थिरता और उचित आय प्राप्त करना अभी बाकी है ।

(च) संबद्ध देशों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना है ।

(छ) पिछले कई वर्षों से विभिन्न स्रोतों से कौस्टिक सोडा का अत्यधिक आयात जारी है और इससे यह स्थापित होता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क कभी भी आयातों के विरुद्ध नहीं थे बल्कि वे पाटित आयातों को रोकने के लिए थे । भारत ही एकमात्र देश नहीं है जिसने कौस्टिक सोडा के पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है ।

(ज) वर्ष 2004 में कौस्टिक सोडा के उत्पादन की विश्वव्यापी क्षमता 65.41 मिलियन मी.टन आंकी गई थी जबकि कौस्टिक सोडा की वैश्विक मांग केवल 52.8 मिलियन मी.टन थी । अतः 12.52 मिलियन मी.टन का अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध था जो क्षमता का लगभग 20% था । संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमता है जबकि उनके अपने देशों में उत्पाद की मांग बहुत कम है ।

(झ) पाटन के पुनः आरंभ होने की संभावना इस तथ्य से स्थापित हुई कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों में से एक से निर्यात बंद हो गए । संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अपनी घरेलू मांग से बहुत अधिक उत्पादन क्षमता बना ली है और इसका निर्माण निर्यात बाजारों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

(ञ) भारतीय बाजार में जिस कीमत पर उत्पाद को बेचा जा रहा है, वह अन्य देशों को सामग्री के निर्यात की कीमत से अधिक है । भारतीय बाजार में विद्यमान कीमतें कुछ अन्य बाजारों से अधिक हैं जहां विदेशी उत्पादकों द्वारा काफी अधिक मात्रा में बिक्री की जा रही है ।

(ट) किसी समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध की कोई संगतता नहीं है और जैसा कि डब्ल्यूटीओ द्वारा माना गया है, उसकी जांच करना अपेक्षित नहीं है। फिर भी, सूचना से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से क्षति के जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना है।

(ठ) एचएलएल के पास उसने जितनी मात्रा और कीमत पर भारतीय उत्पादकों से सामग्री खरीदी है, के संबंध में पूरी जानकारी है तो फिर कंपनी ने इस सूचना को छिपा कर एएमएआई पत्रिका में उल्लिखित कीमतों का सहारा क्यों लिया।

(ड) यदि औद्योगिक प्रयोक्ताओं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में मान्यता प्रदान करना और उनकी परिभाषा में शामिल करना था तो औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए अलग-अलग परिभाषा के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ढ) घरेलू उद्योग ने यह कभी नहीं कहा है कि एचएलएच जांच में भागीदारी नहीं कर सकता है। तथापि, जांच में भागीदारी और औद्योगिक प्रयोक्ता द्वारा समीक्षा जांच के लिए याचिका प्रस्तुत करना दो अलग-अलग मुद्दे हैं।

(ण) लागत संबंधी जानकारी के गोपनीय प्रवृत्ति के होने के कारण उसे अगोपनीय आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद कॉस्टिक सोडा है न कि क्लोरीन और इसलिए कॉस्टिक और क्लोरीन के बीच व्ययों के विभाजन के आधार को प्रकट करने का उत्तरदायित्व न तो भारतीय उत्पादकों और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी का है। घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना में व्यापार संवेदनशील सूचना शामिल है जिसका सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और इसलिए उसे अगोपनीय रूपांतर के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(त) कॉस्टिक सोडा लाई और ठोस समान वस्तुएं हैं। "समान उत्पाद" के लिए और न कि उत्पाद के प्रत्येक रूप के लिए अलग-अलग क्षति विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

(थ) भारतीय उत्पादक निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं है। भारतीय उत्पादकों ने लागू पाटनरोधी शुल्क के मध्यावधि समीक्षा की मांग नहीं की है। कानूनी प्रक्रियाओं में स्थापित सिद्धांत यह है कि जो दावा करता है उसे ही दावे को स्थापित करना पड़ता है। भारतीय उत्पादकों ने क्लोर एल्कली द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रकाशित सूचना का संदर्भ लिया है। कंपनी द्वारा अपने आंकड़ों के आधार पर यह स्थापित किया जाना है कि उनके निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं हैं (चाहे भारत की अथवा तीसरे देशों की) और पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में पाटन होने की संभावना नहीं है।

घ.2 आवेदक, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. आवेदक, आयातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि

(क) कॉस्टिक सोडा के उत्पादन का परिणाम इलेक्ट्रो केमिकल यूनिट (ईसीयू) के रूप में होता है जिसमें समान आर्थिक महत्व के दो उत्पाद अर्थात् कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन होते हैं। उत्पादन लागत का निर्धारण करते समय क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा विभाजन के समय दोनों के बीच लागत का विभाजन उचित एवं समतुल्य आधार पर किया जाना चाहिए। माननीय प्राधिकारी ने कोरिया तथा चीन से कॉस्टिक सोडा के आयात के मामले में पूर्व में पहले ही निर्धारित किया है कि ऐसे मामलों के लिए निवल बिक्री प्राप्ति पर आधारित प्रक्रिया उचित नहीं है और इसके लिए मात्रा आधारित संविभाजन का सहारा लिया जाना चाहिए।

(ख) क्लोर-एल्कली रिपोर्ट से प्राप्त तरल कॉस्टिक सोडा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से जांच की अवधि के दौरान 200% वृद्धि तक का परिवर्तन प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त, लक्षित बाजार में क्लोरीन की कीमतों में लगभग 100% तक की वृद्धि प्रदर्शित हो रही थी।

(ग) जांच अवधि के दौरान बाजार में ईसीयू की आय अकस्मात् 100%-200% तक बढ़ी है। माननीय प्राधिकारी ने बुद्धि के सही प्रयोग के बिना आरओसीई का निर्धारण किया है और आरओसीई के निर्धारण का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। आरओसीई का निर्धारण औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) को ध्यान में रखकर किया गया है परंतु वर्तमान उद्योग के तथ्यों पर डीपीसीओ लागू नहीं होता है और कानूनी रूप से तथा तथ्यों के संबंध में वह अप्रमाणित है।

(घ) कॉस्टिक सोडा, जो कि एल्युमिना के उत्पादन की मुख्य कच्ची सामग्री है, के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगने से नाल्को विश्व बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो रहा है। ईसी ने जापान से कुछेक बड़े इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमीनियम कैपेसिटर्स तथा कोरिया से ड्राम्स के मामले में यह माना है कि पाटनरोधी शुल्क के कारण गौण उद्योग के हित एक महत्वपूर्ण घटक हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान याचिका का समर्थन कर रहे भारतीय उत्पादकों में से केवल दो में पूर्व में नाल्को की अपेक्षा तुलना में पेशकश अथवा आपूर्ति की है। उनकी भौगोलिक स्थिति से उठने वाले लागत संबंधी सभार-तंत्र के कारण अधिकांश घरेलू उद्योग में नाल्को के टेंडरों में भागीदारी नहीं की है।

(ङ) जांच शुरुआत संबंधी याचिका के अगोपनीय अंश यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का सीमाशुल्क में 20% की कटौती के बावजूद ऐतिहासिक लाभ हो रहा है। एमएमआई की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कास्टिक सोडा के कथित पाटन के कारण कोई प्रभावी क्षति नहीं हो रही है। कॉस्टिक सोडा के उत्पादन में बिजली की अत्यधिक खपत होती है और वार्षिक रिपोर्ट में एएमआई ने स्वीकार किया है कि भारत में विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में बिजली की लागत अधिक है।

(च) नाल्को ने केवल निविदा के अंतर्गत लाई कॉस्टिक सोडा की खरीद की है इसलिए कॉस्टिक सोडा के ठोस रूप पर विचार करने से समान उत्पाद के मुद्दे के निर्धारण में विकृति उत्पन्न होगी। कॉस्टिक सोडा के तरल रूप में ठोस रूप से अधिक सांद्रण होता है, जिसके परिणामस्वरूप में इनके अलग-अलग उपयोग और बाजार दशाएं तथा विपणन प्रवृत्तियां होती

हैं । भारत में कौस्टिक सोडा के आयातों में लगभग 85% तरल कौस्टिक है जिसमें नालको द्वारा आयातित कौस्टिक शामिल है ।

(छ) हिंदुस्तान लीवर ने इसी और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए की गई अनेक जांचों का उल्लेख किया है कि हिंदुस्तान लीवर एक हितबद्ध पक्षकार है और वर्तमान जांच को शुरू करना सही था । हितबद्ध पक्षकारों को स्पष्ट रूप से पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अधिकार है । भारतीय उत्पादकों ने अपने इन तर्कों के समर्थन में कोई वास्तविक सामग्री प्रस्तुत नहीं की है कि हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है जो जांच से संगत हो ।

(ज) आवेदन ने सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है और इसके बाद सूचना उपलब्ध कराने का यह दायित्व घरेलू उद्योग का हो जाता है । यह भी कहा गया है कि एक अहस्ताक्षरित और बिना तारीख वाले प्रस्तुतीकरण को छोड़कर सार्वजनिक फोल्डर में भारतीय उत्पादकों का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है । लागत निर्धारण सूचना का अगोपनीय अंश अभी प्रस्तुत किया जाना है और सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया जाना है । इस प्रकार, निष्पादन में सुधार का दावा पर्याप्त है और इसे भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है ।

(झ) आयात आंकड़ों के लिए डीजीसीआईएंड एस, आईबीआईएस के आंकड़ों और आयात बीजकों पर भरोसा किया गया है । भारतीय उत्पादकों का इस दावे का सत्यापन प्राधिकरणों से सौदेवार आंकड़े प्राप्त करके किये जाने की आवश्यकता है कि डीजीसीआई एंड एस में बताई गई इंडोनेशियाई कीमतें सही हैं । याचिकाकर्ता ने भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के निर्धारणार्थ एएमएआई द्वारा प्रकाशित मासिक समाचारों पर विश्वास किया है । एएमएआई द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार बुलेटिन भारतीय उद्योग का तथ्यपूर्ण दस्तावेज है ।

(ञ) घरेलू उद्योग ने क्लोरीन की उत्पादन प्रणाली को गोपनीय रखा है । सूचीबद्ध रूप में लागत निर्धारण संबंधी सूचना निर्यातक को एनआईपी का आधार निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है । उप-उत्पाद क्लोरीन की उत्पादन प्रणाली का आकलन भी नहीं किया गया है । विश्व भर में कौस्टिक सोडा और क्लोरीन को सह-उत्पाद माना जाता है । कौस्टिक सोडा और क्लोरीन के लागत/कीमत निर्धारण में गहरा संबंध है और इन्हें किसी इसीयू को संकल्पना में मापा जाता है । कौस्टिक सोडा संबंधी पाटनरोधी शुल्क का मैक्सिकन उद्योग का केवल एक मामला 1995 में हुआ था । इस दावे से कि 11 देशों के विरुद्ध संबद्ध वस्तुओं संबंधी शुल्कों के मामले हैं यह प्रश्न उठता है कि भारत को वैश्विक विनिर्माताओं द्वारा पाटन के लिए सबसे अलग क्यों रखा गया है ।

(ट) ताइपेई इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण लगाई गई पूंजी पर 22% की दर से आय के आधार पर तर्कसंगत लाभ मार्जिन रखते हुए किया गया है जो चीनी ताइपेई के अल्कली उद्योग द्वारा बताए गए अनुसार काफी अधिक है । यह भी तर्क दिया गया है कि मूल जांच में क्षति रहित कीमत के लिए लाभ मार्जिन 16% था जो इस तरह के उद्योग के लिए तर्कसंगत नहीं है ।

(ठ) उन्होंने स्मरण किया है कि यह मामला डब्ल्यूटीओ कार्य ढांचे के तहत किए गए विचार विमर्शों में शामिल है और विवाद निपटान का निर्णय इस समीक्षा के परिणाम पर निर्भर है। पाटनरोधी मामले तथा लंबित विवाद निपटान का परस्पर संतोषजनक ढंग से समाधान निकालने की दृष्टि से समीक्षा के निष्कर्षों पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया गया है।

(ड) व्यापार मंत्रालय, इंडोनेशिया गणराज्य ने बताया है कि मै. पी टी कियानी केरदास, मै. पी.टी. मुसी पल्प मिल्स और मै. असाहीमास सुब्रेत्रा कैमिकल उत्पादन तथा भारत को निर्यात नहीं करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इंडोनेशिया से आयातों में जांच अवधि के दौरान कमी हुई है। जबकि इसी अवधि में अन्य स्रोतों से आयातों में वृद्धि हुई है। प्रकटन विवरण में क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की दृष्टि से इंडोनेशिया की सरकार ने अनुरोध किया है कि निवेश पर आय और रोजगार के छोड़कर अधिकांश मानदंड ऋणात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। उन्होंने जांच समाप्त करने और निर्यात न किए जाने को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त निर्यातकों/उत्पादकों को जांच से बाहर रखने का अनुरोध किया है।

(ढ) निर्यातक का यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने क्लोरीन की उत्पादन प्रणाली का प्रकटन नहीं किया और सूचीबद्ध आंकड़ों सहित लागत निर्धारण का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने में वह असफल रहा। सूचना के अभाव में हम घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत के निर्धारण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ण) निर्यातक का यह अनुरोध है कि विश्वभर में कॉस्टिक सोडा विनिर्माता कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन को सह-उत्पाद मानते हैं। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया का मामला है जिसमें आवश्यक रूप से कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन होता है और कॉस्टिक सोडा तथा क्लोरीन की लागत/कीमत निर्धारण में गहरा संबंध है और इन्हें ईसीयू की संकल्पना में मापा जाता है।

(त) निर्यातक ने दावा किया है कि औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत किए गए निर्धारण के आधार पर लगाई गई पूंजी पर 22% आय वर्तमान उद्योग के लिए संगत नहीं है और यह अत्यधिक है। आर.ओ सी ई के निर्धारण का घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधी निष्कर्ष पर वास्तविक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस उद्योग के लिए आरओसीई की पुनः गणना की जानी चाहिए और तदनुसार क्षति संबंधी मानदंडों का आकलन किया जाना चाहिए।

(थ) मै. पी.टी. असाहिमास कैमिकल्स ने अनुरोध किया है कि उन्होंने 2003 के बाद से भारत को तरल कॉस्टिक सोडा का निर्यात नहीं किया है, इसलिए उन्हें निर्यातक प्रश्नावली भरने से छूट मिलनी चाहिए और उन पर शुल्क नहीं लगाया जाए।

(द) आईसीएमए (भारतीय रसायन विनिर्माता एसोसिएशन) ने अनुरोध किया है कि कॉस्टिक सोडा की कीमतों में जनवरी से जून, 2005 के बीच 60% की वृद्धि हुई है, इसलिए समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि को मई, 2004 से जून, 2005 तक माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि 258.46 से 271.46 अमरीकी डॉलर/डीएमटी का वर्तमान बेंचमार्क अनावश्यक है क्योंकि वर्तमान आयात कीमत 325 अमरीकी डॉलर से 375 अमरीकी डॉलर/डीएमटी के बीच है इसलिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई

आवश्यकता नहीं है । यह कहा गया है कि कॉस्टिक सोडा अपने व्यापक प्रयोग और पूंजी प्रधान प्रवृत्ति तथा उद्योग के प्राफिट मार्जिन को देखते हुए एक महत्वपूर्ण वस्तु है और प्राधिकारी को प्रयोक्ता उद्योग की चिन्ताओं पर ध्यान देना चाहिए ।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. हितबद्ध पक्षकर द्वारा यह तर्क दिया गया था कि क्लोरीन को कॉस्टिक सोडा के उत्पादन में संयुक्त उत्पाद माना जाना चाहिए क्योंकि विश्व भर में अधिकांश उत्पादक क्लोर उद्योग में क्लोरीन को संयुक्त उत्पाद मानते हैं । प्राधिकारी ने सामान्यतः स्वीकृति लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित और जांच अवधि के दौरान अनुप्रयोज्य) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 और पाटनरोध से संबंधित डब्ल्यूटीओ करार जिसमें जांचाधीन कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर लागत के निर्धारण की अपेक्षा है, को ध्यान में रखते हुए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है बशर्ते कि ऐसे रिकार्ड जीएएपी के अनुपालन में हों और यह रिकार्ड विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के साथ संबंधित लागत को तर्कसंगत ढंग से प्रदर्शित करते हैं । प्राधिकारी ने लागत के उचित आवंटन के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया है जिन्हें भागीदार घरेलू तथा विदेशी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराया गया था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्णय कि क्या क्लोरीन को सह-उत्पाद या उप-उत्पाद माना जाए, एक वैश्विक निर्णय नहीं हो सकता है जो सभी समय में अनुप्रयोज्य तथा प्रासंगिक हो । यह किसी मामला विशेष के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाला निर्धारण है । यह नोट किया जाता है कि संपूर्ण क्लोर अल्कली उद्योग के संबंध में क्लोरीन को संयुक्त उत्पाद या उप उत्पाद मानना उचित नहीं होगा, बल्कि यह तर्कसंगत एवं उचित होगा कि कंपनी तथा संबंधित लागत लेखा परीक्षकों के द्वारा लागत रिकार्डों समेत लेखांकन पुस्तकों में क्लोरीन की उत्पादन प्रणाली को अपनाए जाने के बाद कॉस्टिक सोडा के उत्पादन की लागत के निर्धारण किया जाए । प्राधिकारी लागत लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत ढंग से सत्यापित/प्रमाणित कंपनियों द्वारा अपनाए गए रिकार्डों के आधार को स्वीकार एवं अपनाना उचित समझते हैं । इस मध्यावधि समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने तदनुसार घरेलू उद्योग के मामले में क्लोरीन पर विचार एवं उसकी उत्पादन प्रणाली पर विचार किया है । यह भी नोट किया जाता है कि संबंधित कंपनियों द्वारा बताई गई उत्पादन प्रणाली के विरुद्ध लागत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है ।

18. संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक उत्पादन लागत का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संगत दृष्टिकोण के अनुसार जीएएपी के आधार पर ईष्टतम उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है । घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों की लागत, उनकी खपत, सुविधाओं की लागत अर्थात् बिजली, भाप, पानी आदि ब्याज लागत श्रम लागत, मूल्य-हास लागत एवं बिक्री तथा प्रशासनिक (एसजीए) व्ययों समेत सभी संगत कारकों को ध्यान रखते हुए किया गया है । निवेश तथा क्षमता उपयोग जैसे कारकों की लागत विश्लेषण में भी जांच की गई । उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए लेखांकन एवं उत्पादन की आधारित पुस्तकों तथा भागीदार कंपनियों के वित्तीय विवरणों का संदर्भ लेते हुए इन सभी कारकों पर विचार किया गया । घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण लगाई गई पूंजी पर 22% की दर से तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़ते हुए

उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है (लगाई गई पूंजी का निर्धारण निवल स्थायी परिसंपत्तियों और विचाराधीन उत्पाद की कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है)। आय को ब्याज जमा लाभ अर्थात् उत्पादन लागत में ब्याज व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है और तर्कसंगत लाभ के निर्धारणार्थ इसे घटाया गया है। प्रकटन विवरण की टिप्पणियों के संबंध में निर्यातक तथा टाईपेई कल्चर सेंटर ने यह तर्क दिया है कि इस उद्योग के लिए लगाई गई पूंजी पर 22% आय तर्कसंगत नहीं है और इस घरेलू उद्योग को हुई क्षति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और प्राधिकारी ने मूल या पूर्ववर्ती जांचों में केवल 16% आय की अनुमति दी है। इस मुद्दे की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस उत्पाद से संबंधित पूर्ववर्ती जांचों में आय की समान दर पर विचार किया था। यह भी नोट किया जाता है कि लगाई गई पूंजी पर 22% आय लाभ का तत्व नहीं है बल्कि इसका निर्धारण आय में से ब्याज घटाकर किया जाता है और प्राधिकारी ने अल्प शुल्क कानून का प्रयोग किया है और इस मामले में परिणामी शुल्क निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक नहीं है।

19. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कॉस्टिक सोडा लाई एवं फ्लेक विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद नहीं हैं क्योंकि इनका प्रयोग प्रयोक्ता उद्योग द्वारा भिन्न-भिन्न अंतिम उपयोगों में किया जाता है। हितबद्ध पक्षकार के तर्क की जांच विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र तथा समान वस्तु की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए की गई थी। विचाराधीन उत्पाद में कॉस्टिक सोडा लाई और ठोस रूप दोनों शामिल हैं। यह नोट किया जाता है कि ठोस रूप लम्प, प्रिल, चिप्स, फ्लेक्स आदि के रूप में हो सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि कॉस्टिक सोडा के दोनों रूप एक उत्पाद हैं और ये आवश्यक उत्पाद विशेषताओं, कार्य एवं प्रयोगों, उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रिया, संयंत्र तथा उपकरण, कीमत निर्धारण की दृष्टि से समान हैं। कीमत निर्धारण में भिन्नता जैसा कि पहले बताया गया है वृद्धिशील उत्पादन प्रक्रिया तथा परिवहन लागतों में भिन्नता के कारण से है। प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क से सहमत हैं कि कुछ उपभोक्ता कॉस्टिक सोडा का केवल लाई रूप में प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी सुविधा और उनके द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुकूल है लेकिन प्राधिकारी यह मानते हैं कि इसका यह अर्थ नहीं है कि भिन्न-भिन्न रूपों में उत्पाद अलग-अलग उत्पाद हो जाते हैं और उसकी आवश्यक विशेषताएं, कार्य एवं प्रयोग समाप्त हो जाते हैं और इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अन्य रूपों का समान कार्यचालनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विभिन्न उत्पादकों के परिसर में किए गए सत्यापन दौरों के दौरान यह भली भांति प्रदर्शित हुआ है। विशिष्ट अंतिम अनुप्रयोगों पर विचार न करते हुए उत्पाद आवश्यक रूप से समान रहता है। तथापि, परिणामी कीमतों में दिए गए अंतरों को देखते हुए पाटन मार्जिन, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ लाई और फ्लेक्स के लिए कीमत मानदंडों पर पृथक-पृथक विचार किया गया है।

20. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ईसीयू प्राप्ति पर आवंटन के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान प्रकटन विवरण घरेलू उद्योग के वास्तविक ईसीयू प्राप्ति पर आधारित है और या तो क्लोरीन से प्राप्ति को उत्पादन लागत से घटा दिया गया है या क्लोरीन को सह-उत्पाद माना गया है तथा तदनुसार उत्पादन लागत का निर्धारण किया गया है और इस प्रकार हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं का निवारण किया गया है। यह नोट किया जाता है कि यदि कंपनी ने क्लोरीन को उप उत्पाद माना होता और

यदि संगत अवधि के दौरान क्लोरीन से प्राप्तियां अपेक्षाकृत अधिक होतीं तो इस लेखा में अपेक्षाकृत अधिक कटौती की जाती । घरेलू उद्योग ने हिंदुस्तान लीवर के हितबद्ध पक्षकार होने के अधिकार को जोरदार ढंग से विवादास्पद ठहराया है । यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों की परिभाषा एक सम्मिलित परिभाषा है और प्राधिकारी को किसी पक्षकार को हितबद्ध पक्षकार मानने का अधिकार है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हिंदुस्तान लीवर को हितबद्ध पक्षकार माना है और इन्हें आवेदन करने और वर्तमान जांच की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उचित समझा है । हिंदुस्तान लीवर को वर्तमान जांच से संगत सूचना उपलब्ध कराने और एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अनुरोध करने की अनुमति दी गई है । नाल्को ने बार-बार यह तर्क दिया है कि उपभोक्ता के रूप में उनके हितों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने इस संबंध में इसी के कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के बड़े उपभोक्ता के रूप में नाल्को के अधिकार को वर्तमान प्रक्रियाओं में पूर्णतः मान्यता दी गई है और कंपनी को संगत सूचना उपलब्ध कराने और अनुरोध करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है । नाल्को द्वारा किए गए अनुरोधों पर इन जांच परिणामों में विधिवत ढंग से विचार किया गया है । कुछेक निर्यातकों/उत्पादकों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय रखा गया है जिससे विरोधी हितबद्ध पक्षकार सूचना को चुनौती देने तथा प्राधिकारी को सार्थक अनुरोध प्रस्तुत करने से वंचित हो गए हैं । अधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में इसमें दी गई शर्तों के अधीन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था है । नियमावली में यह व्यवस्था है कि सही कारण के आधार पर उपलब्ध कराई गई कतिपय सूचना जो या तो व्यावसायिक स्वामित्व सूचना होती है या कोई ऐसी सूचना जिसकी प्रवृत्ति गोपनीय हो (उदाहरणार्थ क्योंकि इसका प्रकटन किसी प्रतिस्पर्धी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ वाला होगा या इसका प्रकटन सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति जिससे यह सूचना ली गई है, के लिए महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव वाला होगा), या जो पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना हो, को प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाएगा । नियमावली में आगे यह भी व्यवस्था है कि ऐसी सूचना, इस सूचना को प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी । इस समीक्षा जांच में कतिपय व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना को गोपनीय रखा गया है जिसमें संबद्ध वस्तु के लागत निर्धारण तथा कीमतों से संबंधित सूचना और अन्य संवेदनशील सूचना शामिल है, जिनका प्रकटन किसी प्रतिस्पर्धी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ वाला होगा और जिससे कंपनी के व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना की जांच पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत गोपनीयता उपबंध के अनुसार की गई है और ऐसी सूचना को प्राधिकारी द्वारा इस बात से संतुष्ट होते हुए गोपनीय माना गया था कि गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना वास्तव में गोपनीय है । गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय सारांश सार्वजनिक फाइल में रखा गया था जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा गया था ।

ड पाटन एवं पाटन मार्जिन**ड 1 घरेलू उद्योग के विचार**

22. घरेलू उद्योग में यह अनुरोध किया है कि जांच अवधि के दौरान सभी संबद्ध देशों से पाटन हो रहा है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि ताइवान से आयात लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण जांच अवधि के कारण नहीं हुए हैं और इसलिए पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना इस तथ्य के आधार पर बताई गई है कि संबद्ध देशों में से एक से निर्यात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद बंद हो गए हैं। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अपनी घरेलू मांग से कहीं अधिक क्षमताओं का निर्माण किया है और इनका निर्माण निर्यात बाजारों पर विचार करते हुए किया गया है। इसके अलावा ताइवान के मामले में वर्तमान पाटन की जांच अन्य बाजारों को ताइवान के निर्यातों की कीमतों पर विचार करते हुए की जा सकती है।

ड 2 निर्यातक के विचार

23. निर्यातक ने अनुरोध किया है कि मुख्यतः आस्ट्रेलिया और यूएसए को हुई निर्यात बिक्रियों के दीर्घावधि संविदाओं की गई हैं। दीर्घावधि संविदाओं के कारण ये ग्राहक प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा की खरीद करने के लिए बाध्य हैं। ऐसे संविदागत दायित्व के कारण इन ग्राहकों के लिए कीमतें स्पॉट मार्केट में प्रचलित कीमत से भिन्न निर्धारित की गई हैं जिनका निर्धारण बाजार में विद्यमान मांग और पूर्ति की स्थिति के अनुसार किया गया है। उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि तुलना मौके पर कीमत के आधार पर की जाती हैं और इसलिए यह कीमत घरेलू बाजार में बिक्रियां जांच अवधि के दौरान भारत से भिन्न तीसरे देशों को निर्यात बिक्री कीमत से तुलनीय नहीं हैं। निर्यातक ने यह सुझाव दिया है कि पाटन के आभास और पाटन की पुनरावृत्ति की जांच एक घरेलू उद्योग को हुई क्षति की संभावना का पता लगाने के प्रयोजनार्थ दक्षिण पूर्व एशिया की स्पॉट कीमतों पर विचार किया जाए। उन्होंने आगे यह सुझाव दिया है कि मात्रात्मक छूट और व्यापार स्तर को एफपीसी से भारत के लिए परिकल्पित निर्यात कीमत पर आधारित किया जाए। प्रकटन विवरण हेतु टिप्पणियों में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली ने अनुरोध किया है कि शुल्क समाप्त किए जाने पर क्षति की पुनरावृत्ति आधारहीन है। उन्होंने उल्लेख किया है कि मूल जांच की अवधि अर्थात् 1 जनवरी, 2002 से 30 सितंबर, 2002 तक के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ था और इस मध्यावधि समीक्षा जांच अवधि के दौरान भी कोई निर्यात नहीं हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए न तो मूल जांच में कोई क्षति हुई है और शुल्क समाप्त किए जाने पर न ही इस मध्यावधि समीक्षा में किसी क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। जानकारी में धारा 9 क(ख) के अनुसार उचित आधार पर निर्यात कीमत निकाली है जो बढ़ता मत है जिस पर निर्यातक ताइवान से भिन्न तीसरे देशों को बिक्री करते हैं।

24. उन्होंने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को आस्ट्रेलिया, यूएसए और सिंगापुर के लिए दीर्घावधि संविदाओं के आधार पर वास्तविक कीमत पर विचार करने की बजाए एफपीसी द्वारा सीएमएआई पत्रिका के अनुसार भारत के लिए उपलब्ध कराई गई स्पॉट मार्केट कीमत पर विचार करना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया है कि असंबद्ध पार्टियों की घरेलू बिक्री कीमत के अनुसार कारखाना स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य 231 अम.डा./डीएमटी के बजाए 207 अम.डा./डीएमटी होना चाहिए। निर्यातक द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पाटन

मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्यातक की वास्तविक सत्यापित कीमत की बजाए सीएमएआई पत्रिका में सूचित कीमत पर विचार किया जाए। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात न होने पर पाटन मार्जिन के निर्धारण में गलती की है। प्राधिकारी द्वारा विचारित व्यापार का स्तर अपर्याप्त है इसलिए व्यापार स्तर के बारे में समायोजन दीर्घावधि कीमत एवं मौके पर कीमत में अंतर के लिए किया गया है।

ड 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. पाटनरोधी जांच में "सामान्य मूल्य" का निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार प्रावधान हैं :-

(i) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित सामान्य व्यापार के दौरान तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशियत हो: या

(ii) जहां तक निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अर्थात् निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो :-

(क) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उचित तीसरे देश को निर्यात किए जाने के समय समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य: या

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में संबद्ध वस्तु की उत्पादन की लागत।

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब उद्गम के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात को देश से केवल यानान्तरण किया गया हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित हो, तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

चीनी ताइपेई

26. प्राधिकारी ने धारा 9 क (1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। मैसर्स फार्मोसा प्लास्टिक कारपोरेशन ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है और इसका सत्यापन डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों से किया गया है। प्रकटन विवरण की टिप्पणियों में टीईसीसी ने अनुरोध किया है कि न तो मूल जांच अवधि के दौरान और न ही इस मध्यावधि समीक्षा जांच अवधि के दौरान

कोई निर्यात किया गया था। यद्यपि, पूर्ववर्ती जांच में निर्यातों के तथ्य वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल जांच अवधि के दौरान निर्यात किया गया है जो उक्त जांच में निर्धारण का आधार बना था और इस मुद्दे का समाधान मूल जांच में ही किया गया था। जहां तक वर्तमान जांच का संबंध है प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम और डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुसार कार्रवाई की है।

27. पाटनरोधी नियम के नियम 23 के तहत समीक्षा का उद्देश्य शुल्क को लगातार लागू रखने की जरूरत का पता लगाना और इस बात की जांच करना होता है कि क्या शुल्क समाप्त करने का पर्याप्त औचित्य है। चूंकि जांच अवधि के दौरान चीनी ताइपेई से कोई आयात नहीं हुआ था इसलिए, इस बात का निर्धारण करना प्रासंगिक है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति हेतु यह पर्याप्त औचित्य है। चूंकि प्राधिकारी के लिए यह निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या पाटन की भरपाई के लिए शुल्क को निरंतर लागू रखना जरूरी है इसलिए इस बात का निर्धारण अपेक्षित है कि क्या कोई निर्यात न होने का तथ्य यह मानने के लिए पर्याप्त है कि पाटन की भरपाई के लिए शुल्क को लगातार लागू रखना अनावश्यक है। प्राधिकारी के लिए वर्तमान में कोई पाटन न होने की स्थिति में शुल्क समाप्त करने से पाटन की संभावना का पता लगाना अपेक्षित है और इस संबंध में निर्यातक के सामान्य मूल्य तथा तीसरे देश के संबंध में निर्यातक की वर्तमान कीमत प्रासंगिक है। अतः प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु की बिक्री की गई थी अथवा नहीं। यह निर्धारण किया गया है कि उपाय को समाप्त किए जाने की स्थिति में ताइवान के निर्यातकों द्वारा उसी कीमत पर भारतीय बाजार में पाटन पुनः शुरू करने की संभावना है। आगे यह निर्धारण किया गया था कि यदि निर्यातक भारत में निर्यात पुनः शुरू कर देता है तो क्या उसका पाटन किए जाने की संभावना है। यह भी स्मरण किया जाता है कि मूल जांच में अलग-अलग पाटन मार्जिन काफी अधिक था।

तीसरे देशों को निर्यात के आधार पर पाटन मार्जिन

28. एफपीसी ने संबद्ध वस्तु की बिक्री घरेलू बाजार में संबद्ध एवं असंबद्ध दोनों कंपनियों की है और जांच अवधि के दौरान भारत से भिन्न अनेक देशों को निर्यात किया है। इन खंडों के लिए बिक्री, मात्रा तथा औसत कीमत की तुलना से निम्नानुसार पता चलता है :-

एफपीसी के उत्तर के अनुसार सूचीकृत सूचना :

	संबद्ध घरेलू बाजार		असंबद्ध घरेलू बाजार		तीसरे देशों को निर्यात	
	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर
जनवरी-04	100.00	100.00	198.91	104.71	205.09	62.54
फरवरी-04	100.00	100.00	125.29	108.78	78.24	60.81
मार्च-04	100.00	100.00	137.44	112.61	277.42	74.66
अप्रैल-04	100.00	100.00	137.40	110.40	80.46	66.12

मई-04	100.00	100.00	137.27	109.44	373.00	68.82
जून-04	100.00	100.00	130.98	110.19	199.16	65.76
जुलाई-04	100.00	100.00	121.95	107.33	69.43	68.44
अगस्त-04	100.00	100.00	116.74	106.80	193.55	62.72
सितंबर-04	100.00	100.00	117.23	107.57	98.65	67.20
अक्टूबर-04	100.00	100.00	148.39	110.29	174.18	76.09
नवंबर-04	100.00	100.00	130.81	108.23	32.68	84.26
दिसंबर-04	100.00	100.00	70.11	121.39	147.13	77.38
जांच अवधि	100.00	100.00	124.42	109.32	156.62	67.61

29. निर्यातक ने भारत से भिन्न देशों को पर्याप्त निर्यात बिक्री की है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसी निर्यात बिक्री दीर्घावधि संविदाओं के तहत की गई है और बिक्री मात्रा घरेलू बाजार में बेची गई मात्रा की तुलना में काफी अधिक है और इसलिए निर्यात बिक्री की कीमत में अंतर है। निर्यातक ने निर्यात कीमत की तुलना घरेलू कीमत के साथ करते समय छूट का भी दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने अपनी खुद की संबद्ध कंपनी की पर्याप्त घरेलू बिक्री की। अपनी संबद्ध कंपनी को बेची गई वस्तु की मात्रा निर्यात बिक्री में शामिल मात्रा से तुलनीय है। तथापि, यह पाया गया है कि तीसरे देशों के लिए निर्यात कीमत उसकी संबद्ध कंपनियों के लिए कीमत की तुलना में काफी अधिक है। घरेलू बिक्री की जांच करने पर यह पाया गया था कि उच्च मात्रा की स्थिति में कीमत अधिक है और कम मात्रा के मामले में कीमत कम हो सकती है। निर्यातक बिक्री का विश्लेषण किया गया था और जांच अवधि के लिए औसत आधार पर तुलना की गई थी और उसके बाद जांच अवधि के दौरान माह-दर-माह आधार पर तुलना की गई है। तथापि, ऐसी किसी सुसंगत पद्धति का निर्धारण नहीं किया जा सकता जिससे यह पता चल सके कि घरेलू बाजार में कीमत निर्यातक के दावे के अनुसार मात्रा के केवल अंतर होने की स्थिति में निर्यात कीमत से भिन्न है। अतः यह नोट किया जाता है कि कीमत समायोजन के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता और ऐसे मानदंडों के आधार पर निर्यात कीमत की तुलना सामान्य मूल्य के साथ करते समय इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि निर्यातक द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि दो अलग-अलग बाजारों में निर्यातक की कीमत मात्राओं में केवल अंतर होने से भिन्न हैं।

30. निर्यातक ने जांच अवधि के प्रत्येक माह के लिए सीएमए आई द्वारा जारी क्लोर अल्कली मार्केट मार्केट रिपोर्ट, 2004 की प्रतियां उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए संबद्ध वस्तु की मौके पर कीमत 214 अम.डॉ.-डीएमटी थी। इसी रिपोर्ट से साधारण औसत के आधार पर ताइवान के लिए मौके पर वार्षिक कीमत 179 अम.डॉ.-डीएमटी होने का पता चलता है। घरेलू उद्योग ने मैसर्स हरिमैन कैमसल्ट लिमिटेड (क्लोर अल्कली के नाम से) द्वारा प्रकाशित जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु का माहवार कीमत सारांश उपलब्ध कराया है। इस प्रकाशन में एशियाई देशों (सुदूर पूर्व) और खासकर ताइवान में प्रचलित कीमतें उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ताइवान में औसत घरेलू कीमत 207 अम.डॉ. प्रति डीएमटी हैं जबकि सुदूर पूर्व में सामान्य औसत कीमत 197 अम.डॉ. प्रति डीएमटी है। निर्यातक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इस स्रोत की कीमतों पर विचार करने का अनुरोध किया है। निर्यातक ने दावा किया है कि वह तीसरे देशों को दीर्घावधि संविदाओं पर बिक्री कर रहा है। लेकिन यह पाया गया था कि

समस्त निर्यात बिक्रियां दीर्घावधि संविदाओं पर नहीं की गई थीं। ऐसी पर्याप्त बिक्रियां थीं जिनके लिए संविदा बिक्री का कोई दावा नहीं किया गया था। किसी भी हालत में निर्यातक का यह तर्क भले ही उसे स्वीकार कर लिया जाए पर यह सिद्ध नहीं कर पाता कि मात्रा के साथ कीमत भिन्न थी और संविदा कीमत और निर्यात कीमत में अंतर दावा किए गए कीमत समायोजन की मात्रा तक थी। यह तर्क दिया गया है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू ग्राहक से प्राप्त प्रत्येक क्रय आदेश के अनुसार खरीदी गई औसत मात्रा लगभग 183 मी.टन थी। यद्यपि, जांच अवधि के दौरान निर्यातक ग्राहकों (तीसरे देशों के) से प्राप्त प्रत्येक आदेश के अनुसार औसत खरीद मात्रा 6429 डीएमटी अथवा घरेलू आदेश की मात्रा से 35 गुणा अधिक रही थी। तदनुसार, औसत घरेलू बिक्री की मात्रा और औसत निर्यात बिक्री की मात्रा के बीच समान अंतर के लिए परिकल्पित निर्यात कीमत के साथ तुलना करने पर घरेलू कीमत हेतु 35 अम.डॉ./डीएमटी के एक कारक पर विचार किया जाए।

31. निर्यातक के इस दावे को पाटनरोधी नियम तथा धारा 9 क(1)ग जिसमें सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति दी गई है, को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण सीएमएआई के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब निर्यातक के पास अत्यंत व्यवहार्य प्रतिनिधिक घरेलू बिक्री हो, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर की जाती है और सीएमएआई या क्लोर अल्कली कीमतें मिसाल के रूप में नहीं ली जा सकती। प्राधिकारी ने औसत घरेलू मात्रा और औसत निर्यात मात्रा के बीच किसी प्रकार के अंतर के आधार पर छूट प्रदान करने के तर्क की जांच की है। यह देखा गया है कि निर्यातक ने भारत से भिन्न देशों में दीर्घावधि संविदा के आधार पर बिक्री की तुलना में घरेलू बाजार में काफी अधिक कीमत पर संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। भारत औसत घरेलू कीमत में से 35 अम.डॉ./डीएमटी की छूट प्रदान करने के बाद भी तीसरे देशों तथा आस्ट्रेलिया, यूएसए तथा सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से पर्याप्त कम पाई गई थी।

32. निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुबंध-1 में घरेलू बिक्री के सौदे उपलब्ध कराए हैं। घरेलू बिक्री के नमूना बीजकों का सत्यापन किया गया था और उनकी प्रतियां सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई थीं। घरेलू बिक्री जांच अवधि के दौरान संबद्ध और असंबद्ध दानों पार्टियों को की गई थी जिसे सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अलग कर दिया गया है। केवल असंबद्ध कंपनियों को हुई बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा किया गया है। निर्यातक ने परिशिष्ट 8 के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं और उनका सत्यापन किया गया है। निर्यातक ने क्लोरीन के लिए मूल्य प्राप्ति को प्रति मी. टन कॉस्टिक सोडा की लागत से घटा दिया है और उसे स्वीकार कर लिया है क्योंकि इसका दावा कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों पर आधारित होने के संबंध में किया गया है। वित्तीय व्यय का विशिष्ट उत्पाद कारोबार आधार पर अनुपातिक रूप में बांटा गया है जिसके लिए निर्यातक ने स्पष्टीकरण दिए हैं। यह देखा जाता है कि पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के दौरान यथा आवंटित वित्तीय व्यय के लिए ऐसी ही प्रति यूनिट लागत आवंटित करने और उचित लाभ मार्जिन, 80/20 जांच करने के बाद व्यापार की सामान प्रक्रिया में असंबद्ध पार्टियों के लिए भारित औसत घरेलू बिक्री कीमत की अनुमति देने के बाद भी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समस्त लाभकारी सौदों पर विचार किया गया था। सर्वप्रथम यह निर्धारित किया गया था कि क्या घरेलू बाजार और निर्यात बाजार में बेची गई वस्तु का स्वरूप एक जैसा था।

यह पाया गया था कि घरेलू और निर्यात दोनों बिक्रियों में केवल द्रव्य रूप में कॉस्टिक सोडा की बिक्री शामिल थी। तत्पश्चात यह निर्धारित किया गया था कि क्या संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री की कुल मात्रा निर्यात बिक्री के संबंध में प्रतिनिधिक थी। यह पाया गया था कि घरेलू बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा तीसरे देशों को निर्यात मात्रा से काफी अधिक थी। घरेलू बाजार में बिक्री को इस प्रकार प्रतिनिधिक माना गया था। बाद में यह निर्धारित किया गया था कि क्या घरेलू बिक्री व्यापार की समान प्रक्रिया में की गई थी। यह पाया गया था कि सभी घरेलू बिक्रियां उत्पादन लागत से अधिक पर की गई थीं और इसलिए घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को की गई सभी बिक्रियों को व्यापार की सामान प्रक्रिया में हुई बिक्रियों के रूप में माना गया था। इसलिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण, वास्तविक प्रदत्त कीमतों या संबद्ध वस्तु की सभी बिक्रियों की देय राशि, यदि यह लाभप्रद है या नहीं, के आधार पर किया गया था। उपरोक्त के संदर्भ में, निर्यातक के लिए सामान्य कीमत का निर्धारण घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को हुई सभी घरेलू बिक्रियों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने खर्चों की जांच की और उनको दावा किए हुए के रूप में देने की अनुमति दी। इस प्रकार, सामान्य मूल्य कारखाना स्तर पर निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

33. निर्यातक ने सभी तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यातों के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराया है और आस्ट्रेलिया, अमरीका और सिंगापुर को की जाने वाली बिक्रियां उनके निर्यातों की एक बड़ी मात्रा बनती हैं। प्राधिकारी का विचार है कि निर्यातक ने तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यातों के बारे में पर्याप्त ब्यौरा उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को की गई निर्यात बिक्रियों पर विचार करना उपयुक्त समझा और उन्होंने भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर किया। दावा किए गए कीमत समायोजनों का सत्यापन किया गया था और कारखाना द्वार स्तर पर पहुंचने की अनुमति दी गई थी। सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत के साथ तुलना करने के लिए प्राधिकारी ने निर्यातक के विभिन्न तर्कों पर विचार किया। निर्यातक ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि सामान्य मूल्य निर्यात कीमत के साथ इन कारणों से तुलनीय नहीं था कि निर्यात दीर्घावधि संविदा के अधीन थे और निर्यातों में शामिल बिक्री मात्रा घरेलू बिक्रियों से बहुत अधिक थी। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि यह तथ्य कि निर्यात दीर्घावधि संविदा के अंतर्गत किए गए थे, निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अप्रासंगिक है। यह तथ्य कि कीमतें मात्रा से भिन्न थीं एक सच्ची बात है जिसके लिए निर्यातक इसको स्थापित करने के पश्चात एक कीमत समायोजन का दावा कर सकता था। तथापि, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, निर्यातक यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि घरेलू बाजार में उसकी कीमतें मात्राओं से भिन्न थीं। वास्तव में यह पाया गया था कि कीमतें कम मात्राओं के लिए कम और अधिक मात्राओं के लिए अधिक हो सकती थीं। भारत औसत घरेलू कीमत से 35 अमरीकी डॉलर/डीएमटी की छूट प्रदान करने के पश्चात भी तीसरे देशों अर्थात् आस्ट्रेलिया, अमरीका और सिंगापुर को निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से काफी कम पाई गई थी।

प्रकटीकरण विवरण के बारे में की गई टिप्पणियों के संबंध में निर्यातक ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा उनके घरेलू बाजार में वास्तविक बिक्री कीमत पर विचार करने के बजाय

सीएमएआई पत्रिका के अनुसार ताइवान में मौके पर बाजार कीमत पर विचार किया जाना चाहिए था ।

34. निर्यातक के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य की एक भारित औसत दर भारित औसत आधार पर निर्यात कीमत के साथ तुलना की गई थी और यह पाया गया था कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक था । तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यातों की मात्रा पर विचार करके भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था जिसे इस बात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपनाया गया है कि क्या पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है । तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उपायों को हटाने से पाटन की संभावना को निष्प्रभावी बनाने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है । इस बात की और अधिक पुष्टि करने के लिए कि क्या पाटन को निष्प्रभावी बनाने के लिए शुल्क को लागू रखना आवश्यक है, प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना की कि क्या सामान्य मूल्य से कम कीमत पर और अनुशंसा किए जा रहे उपायों से कम उपायों पर भारत को किए जाने वाले निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है । प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या भारत को किए जाने वाले निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए जाने की संभावना है और इसलिए इनके परिणामस्वरूप पाटन और क्षति होगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या भारत को किए जाने वाले ऐसे निर्यात घरेलू उद्योग हेतु संशोधित क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर किए जाने की संभावना है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है । भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए ताइवान के निर्यातकों को घरेलू उद्योग की कीमतों से मेल बैठाना पड़ेगा जो घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से पहले ही कम है । जांच के दौरान यह पाया गया है कि ताइवान के निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा एफपीसी हेतु स्थापित सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर निर्यात करना होगा । तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि एफपीसी को भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और इस प्रकार पहले से लागू उपायों को हटाने की स्थिति में पाटन के पुनः होने की संभावना प्रमाणित होगी ।

35. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि एफपीसी 4,66,000 मी.टन का अत्यधिक विस्तार कर रहा है (एक पी सी की वेबसाइट से देखा गया) । यह नोट किया जाता है कि यद्यपि निर्यातक ने दावा किया था कि यह विस्तार तीसरे देश के बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था तथापि, प्राधिकारी को इस बात का कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया था कि इस विस्तार की समूची मात्राएं तीसरे देशों के क्रेताओं के लिए प्रतिबद्ध थीं और अत्यधिक अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं थी । जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि एफपीसी के पास भारत को निर्यातों के लिए अत्यधिक अतिरिक्त मात्राएं उत्पादित करने की क्षमता है और ये अतिरिक्त मात्राएं अत्यधिक स्तरों तक या मूल जांच की अवधि के दौरान पाए गए स्तरों से उच्च स्तरों तक पहुंच सकती थीं । यदि इन निर्यातों का पहुंच मूल्य अनुसंधित किए जा रहे बेंचमार्क से कम होता तो ये पाटित कीमतों पर किए गए निर्यात होते । उन कीमतों पर विचार करते हुए जिन पर तीसरे देशों को निर्यात किए गए हैं, इन निर्यातों की किसी भी स्थिति में पाटित कीमतों पर होने की संभावना है । यदि निर्यात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों के लगभग अथवा उनसे कम कीमतों पर किए जाएं तो यह स्पष्ट है कि निर्यात पाटित कीमतों पर होंगे यदि ऐसे निर्यातों की पहुंच कीमत सिफारिश किए जा रहे बेंचमार्क से कम है ।

ताइवान के उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार तीसरे देश के बाजारों की तुलना में अधिक आकर्षक होगा जो विशाल और बढ़ती हुई मांग और भौगोलिक निकटता प्रदान करते हैं। वस्तुतः जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि (क)-आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अमरीका में कौस्टिक सोडा की कीमतें भारतीय बाजार में कीमतों से काफी कम थीं और विगत में निर्यातक ने भारतीय ग्राहकों को अंतिम आपूर्तियों के लिए विभिन्न तथा व्यापारियों को 15,000 मी.टन सामग्री की आपूर्ति करने की वचनबद्धता की थी और वास्तव में एक वर्ष से कम में खेपों हेतु 86,000 मी.टन की आपूर्ति की थी और ताइवान द्वारा किए गए असहयोग में अनेक अन्य उत्पादक हैं।

36. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह नोट किया जाता है कि ताइवान के निर्यात करने वाले उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि शुल्क को लागू रखना अनावश्यक है। इसके विपरीत, जांच से यह पता चला है कि पाटन को निष्प्रभावी बनाने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में जवाब नहीं दिया है। एफपीसी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना से यह संकेत मिलता है कि ताइवान के उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताएं प्रत्यक्ष खपत से काफी अधिक हैं। यह भी देखा गया है कि व्यापार पत्रिका और एकमात्र जवाब देने वाले निर्यातक हेतु स्थापित सामान्य मूल्य के अनुसार ताइवान से अन्य देशों को निर्यात कीमत भी सामान्य मूल्य से काफी कम है। इस आंकड़े से यह प्रदर्शित होता है कि ताइवान के अन्य उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले संभावित पाटन को निष्प्रभावी बनाने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है। चूंकि किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने इस मध्यावधि समीक्षा जांच में सहयोग नहीं किया था और संभावित पाटन की पुष्टि एफपीसी जिसने जांच अवधि के दौरान 90% उत्पादन किया और संबद्ध वस्तु की बिक्री की, द्वारा दाखिल की गई सूचना के आधार पर की गई है, इसलिए चीनी ताईपेई के सभी निर्यातकों/उत्पादकों हेतु समान पाटन मार्जिन को जारी रखने का प्रस्ताव है।

इंडोनेशिया

सामान्य मूल्य

37. प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं। इंडोनेशिया के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने विनिर्दिष्ट विधि और ढंग से निवेदन और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए। करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित समयावधि के भीतर पहुंच देने से या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच, अत्यधिक बाधा पहुंचाता है तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक या अंतिम निर्धारण चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक किए जा सकते हैं। चूंकि इंडोनेशिया के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ निवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसने इंडोनेशिया के प्रचालित घरेलू कीमतों का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम उपाय किए हैं लेकिन जांच अवधि के लिए वास्तविक सौदागत कीमतें प्राप्त नहीं कर सके। चूंकि वास्तविक सौदागत सूचना उपलब्ध नहीं है, घरेलू

उद्योग ने निवेदन किया है कि क्लोर अल्कली द्वारा प्रस्तुत सूचना को समुचित समायोजनों के साथ सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ एक उचित और पर्याप्त आधार माना जा सकता है। ताइवान के संबंध में की गई जांच से पता चला कि क्लोर अल्कली में प्रकाशित कीमतें वास्तविक सौदागत कीमतों के बिल्कुल निकट हैं। वास्तव में ताइवान से संबंधित जांच से यह प्रदर्शित हुआ है। क्लोर अल्कली में बतायी गई कीमतें एफ पी सी द्वारा दावा की गई वास्तविक कीमतों से कुछ कम थीं, अतः प्राधिकारी विचार करते हैं कि क्लोर अल्कली में बतायी गई कीमतें बिल्कुल प्रतिनिधि कीमतें हैं और इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का उचित साक्ष्य हैं। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण क्लोर अल्कली में प्रकाशित कीमतों के आधार पर किया गया है। इन कीमतों को वितरित कीमतें माना गया था और कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए संभावित अंतर्देशीय भाड़े हेतु एक समायोजन किया गया था। तदनुसार इंडोनेशिया के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अम.डालर/मी.टन के रूप में किया गया है।

निर्यात कीमत

38. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है जिसमें प्रविष्टि बिल सं. तारीख, देश का कोड, उत्पाद की मात्रा, मूल्य, विवरण और आयातक का नाम आदि शामिल थे। आयात आंकड़ों की जांच करने पर यह पाया गया था कि डीजीसीआईएंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आंकड़ों में अन्य उत्पादों से संबंधित आंकड़े भी थे। इसलिए विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़ों का विश्लेषण और उन्हें अलग किया गया था जिनको कॉस्टिक सोडा लाई और फ्लेक/ठोस रूपों के लिए आगे पृथक किया गया था। डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया ने जांच अवधि के दौरान 3745 मी.टन कॉस्टिक सोडा का निर्यात किया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत निकालने के लिए इंडोनेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किसी जवाब और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से किसी सूचना के अभाव में समायोजनों पर विचार किया गया है जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इंडोनेशिया के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण अम.डालर/मी.टन के रूप में किया गया है।

यूरोपीय संघ फ्रांस (फ्रांस को छोड़कर)

सामान्य मूल्य

39. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं। ई सी (फ्रांस को छोड़कर) से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने विनिर्दिष्ट विधि और ढंग से निवेदन और प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित समयावधि के भीतर सूचना की पहुंच देने से मना करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्रारंभिक और अंतिम निर्धारण, चाहे सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जा सकते हैं। चूंकि फ्रांस को छोड़कर ईयू के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ निवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए सभी निर्यातकों/उत्पादकों हेतु सामान्य मूल्य

का निर्धारण करने की नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। चूंकि संबद्ध राज्य क्षेत्र से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरों की नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उन्होंने इंडोनेशिया में प्रचलित घरेलू कीमतों का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए हैं लेकिन वे जांच अवधि के लिए वास्तविक सौदागत कीमतें प्राप्त नहीं कर सके। चूंकि वास्तविक सौदागत सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग ने निवेदन किया कि क्लोर अल्काली द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को समुचित समायोजनों के साथ सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ उचित और पर्याप्त आधार माना जा सकता है। बेहतर सूचना के अभाव में घरेलू उद्योग द्वारा द्वितीयक स्रोतों अर्थात् क्लोर अल्काली से उपलब्ध कराई गई सूचना को मौजूदा पाटन की मात्रा के आकलन के प्रयोजनार्थ खर्चों के उपयुक्त समायोजनों के साथ सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ आधार के रूप में माना गया है। ताइवान के संबंध में की गई जांच से यह खुलासा हुआ कि क्लोर अल्काली में प्रकाशित कीमतें वास्तविक सौदागत कीमतों के बिल्कुल निकट हैं। वास्तव में, ताइवान से संबंधित जांच से यह प्रदर्शित हुआ कि क्लोर अल्काली में बतायी गई कीमतें एफपीसी द्वारा दावा की गई वास्तविक कीमतों से कुछ कम थीं, अतः प्राधिकारी विचार करते हैं कि क्लोर अल्काली में बताई गई कीमतें संबद्ध राज्य क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का बिल्कुल प्रतिनिधि और उचित साक्ष्य हैं। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण क्लोर अल्काली में प्रकाशित कीमतों के आधार पर किया गया है। कीमतों को संवितरित कीमतें माना गया था और कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए संभावित अंतर्देशीय भाड़े हेतु एक समायोजन किया गया था। तदनुसार यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण **** अम.डॉलर/मी.टन के रूप में किया गया है।

इसलिए फ्रांस को छोड़कर ईयू के सभी निर्यातकों/उत्पादकों हेतु सामान्य मूल्य का परिकलन **** अम.डॉलर/मी.टन के रूप में किया गया है।

निर्यात कीमत:

40. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है जिनमें प्रविष्टि सं. तारीख, देश का कोड, उत्पाद की मात्रा, मूल्य और विवरण और आयात आंकड़ों की जांच करने पर यह पाया गया था कि डीजीसीआई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आंकड़ों में अन्य उत्पादों के आयात आंकड़े भी थे। अतः विचाराधीन उत्पाद हेतु आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था और उन्हें अलग किया गया था जिन्हें कॉस्टिक सोडा लाई और कॉस्टिक सोडा फ्लेक, ठोस रूपों हेतु और उनसे अलग किया गया था। डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों के अनुसार संबद्ध राज्य क्षेत्र ने जांच अवधि के दौरान 165 मी.टन कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स का निर्यात किया था। कारखाना द्वार निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए समायोजनों पर विचार किए गए हैं जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। फ्रांस को छोड़कर ईयू के सभी निर्यातकों/उत्पादकों हेतु कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण **** अम.डॉलर/मी.टन के रूप में किया गया है।

ड 5 पटसन मार्जिन

41. संबद्ध वस्तु हेतु सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, के आधार पर प्राधिकारी ने पटसन मार्जिन का आकलन निम्नानुसार किया है :-

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम.डॉलर/मी टन)	निर्यात कीमत (अम.डॉलर/मी टन)	निर्यात कीमत के % के रूप में पाटन मार्जिन
चीनी लाइपेई के सभी उत्पादक/निर्यातक	****	****	68.93
इंडोनेशिया के सभी उत्पादक/निर्यातक	****	****	165
यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) के सभी उत्पादक/निर्यातक	****	****	56.53

42. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटन को निष्प्रभावी बनाने के लिए शुल्क को लागू रखना आवश्यक है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया :-

1. मूल जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन;
2. वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन-इस उद्देश्य के लिए कि जहां जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों की विद्यमानता थी, इन पर विचार किया गया था और पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया था। जहां जांच अवधि के दौरान भारत से कोई निर्यात नहीं किए गए थे, प्राधिकारी ने स्थापित सामान्य मूल्य और अनुशंसा के लिए जा रहे बेंचमार्क पर विचार करते हुए तीसरे देशों को किए गए निर्यातों और पाटन की संभावना के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया।
3. विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए ज्ञात विस्तारों, भारत में प्रचलित कीमतें विगत में किए गए निर्यातों की वास्तविक और संभावित मात्रा पर विचार करते हुए मौजूदा और संभावित अधिशेष अप्रयुक्त क्षमताएं।

इन कारकों की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि

- (क) तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन बहुत अधिक है;
- (ख) अनुसंशित किए जाने वाले प्रस्तावित बेंच मार्क पर विचार करते हुए क्या निर्यातकों को इस बेंच मार्क से नीचे रखा जाना चाहिए जोकि पाटित कीमतों के बराबर होगा। क्या निर्यात सामान्य मूल्य पर किया जाए जिन पर पाटनरोधी शुल्क देय नहीं है। इसलिए निर्यात पाटित कीमतों पर किए जाने की संभावना है यदि आयात अनुसंशित करने के लिए बेंच मार्क से कम हो।

- (ग) तीसरे देशों को निर्यात मूल्य की कारखाना बाह्य वसूली ऐसी कीमतों पर है की क्या निर्यात इन कीमतों पर किए गए आयातों की परिणामस्वरूप पहुंच कीमत भारत में बिक्री कीमतों और गैर-क्षतिकारक कीमतों से काफी कम होगी।
- (घ) एक ताईवानी निर्यातक में अकेली निविदा के लिए अत्यधिक 1.5 लाख मीट्रिक टन आपूर्ति करने का वचन दिया था जो उसकी अधिशेष क्षमता और निर्यात संभावना का पूर्णरूपेण सूचक है।
- (ङ) ताईवान से निर्यात कीमत तीसरे देश से न केवल सामान्य मूल्य से बहुत कम है बल्कि भारत में मौजूदा कीमत और गैर क्षतिकारक कीमत से भी बहुत कम है।
- (च) निर्यातकों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को लेने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति की संभावना नहीं होगी और शुल्क को नियंत्रण लगाए रखने का कार्य पाटन को समाप्त करने के लिए अनावश्यक था।
- (छ) ताईवान में उत्पादक तीसरे देश के उत्पादकों/निर्यातकों को दिए गए आर्डरों पर विगत में माल का लदान करते हुए पाए गए हैं।
- (ज) क्षति की अवधि में विगत में तीसरे निर्यातक देशों में उत्पादकों द्वारा प्राप्त क्षमता उपयोग और जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग के स्तर को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारी ने ताईवान, इंडोनेशिया और यूरोप में बिना प्रयोग की हुई क्षमताओं का निर्धारण किया है। यह नोट किया गया है कि इंडोनेशिया के उत्पादकों के पास उपर्युक्त क्षमताएं 87 हजार मीट्रिक टन थी जबकि यूरोपीय उत्पादकों के मामले में यह क्षमता 2 लाख छत्तीस हजार मीट्रिक टन थी। अन्य शब्दों में इन देशों के उत्पादक इन मात्राओं में सामग्री की तुरंत पेशकश कर सकते हैं।
- (झ) क्लोक अलकली द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार:-

ताईवान की फालतू क्षमता	54,000
ताईवान विस्तार योजना	466,666
ताईवान का कुल संभावित अधिशेष	520,666
इंडोनेशिया की फालतू क्षमता	327,000
यूरोप की फालतू क्षमता	1,886,000
कुल अधिशेष	2,733,666
भारतीय भाग	
➤ आबद्ध खपत को छोड़कर	18,74,596
➤ आबद्ध खपत सहित	21,22,251

- (य) सीएमएआई की रिपोर्टों के अनुसार विश्व में इस समय मांग आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार है:-

मांग	5,00,31,000
क्षमता	5,75,74,000
अधिशेष	7,543,000

क्योंकि विश्वव्यापी आधार पर अधिशेष क्षमता है इसलिए यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में निर्यातों के दिशा परिवर्तन की संभावना है। रिकार्ड में क्षमता, उत्पादन, बिक्री और मांग के बारे में साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को इस मामले में शुल्क वापस लेने से पाटन किया जाएगा इसलिए पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लगाए रखना आवश्यक है।

च. क्षति निर्धारण और कारणात्मक संबंध की जांच की पद्धति

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

43. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि:

(क) ए.डी. के अनुच्छेद 11.1 में यह व्यवस्था है कि कोई पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक और उस मात्रा में जो पाटन को रोकने के लिए आवश्यक हो जिससे क्षति हो रही है, जिससे लागू रहेगा यदि परिवर्तित परिस्थितियों में यह तो पाटन अथवा घरेलू उद्योग को क्षति होनी बंद हो गई हो तो कोई हितबध पक्षधर किसी मध्यम समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है। किसी पक्षकार के अनुरोध पर ऐसी समीक्षा की शुरुआत करने के लिए एकत्रित शर्त यह होनी चाहिए की न्यूनतम एक वर्ष की उचित अवधि निश्चयात्मक उपायों को लागू करने के समय से अवश्य ही व्यतीत हो।

प्राधिकारी के लिए समीक्षा की आवश्यकता को साबित करने के लिए किसी हितबद्ध कि पक्षकार को सकारात्मक सूचना के आधार पर समीक्षा की आवश्यकता अपेक्षित है बशर्त निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से एक उचित समय अवधि व्यतीत हो गई हो चाहे पाटनरोधी समाप्त करने के लिए शुल्क को लगातार लगाए रखना आवश्यक हो, अथवा क्षति के निरन्तर होने की संभावना हो शुल्क को हटा लिया जाता है अथवा इसमें अंतर होता है अथवा दोनों होते हैं।

(ख) किसी जांच प्रक्रिया में वास्तविक क्षति की मौजूदगी की जांच किसी मूल पाटनरोधी जांच में उस की प्रक्रिया के समान है तो घरेलू उद्योग को वास्तविक की मौजूदगी की जांच पाटनरोधी के अनुच्छेद 3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी होती है। एक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को शुल्क समाप्त करने के प्रभाव की जांच करना अपेक्षित है घरेलू उद्योग का वर्तमान कार्यनिष्पादन केवल उस सीमा तक संगत है जहां तक यह क्षति की मौजूदगी अथवा अन्यथा जारी रहने को प्रदर्शित करता है वर्तमान कार्यनिष्पादन में सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हो सकता है और ऐसे मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरुवृत्ति की संभावना की जांच करना अपेक्षित है। कारणात्मक संबंध की जांच करना किसी समीक्षा जांच में संगत वही हो सकता है

डब्ल्यूटीओ के पैनल ने यह आदेश दिया है कि किसी अंतिम जांच समीक्षा में काराणात्मक संबंध की जांच करना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार इसी मध्यावधि जांच में भी भारतीय उत्पादक यह प्रस्तुत करते हैं कि काराणात्मक संबंध की जांच करना आवश्यक नहीं है क्योंकि काराणात्मक संबंध पहले ही मूल जांच में साबित हो चुका था। इसके होते हुए भी भारतीय उत्पादक यह निवेदन करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति को सुधारने और पाटन के बीच एक काराणात्मक संबंध है,

44. चीनी ताईपेई से कोई आयात न होने के बारे में घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि पाटन की पुनरावृत्ति होने और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने अगले तीन वर्ष में वर्तमान क्षमता और विस्तार योजना घरेलू मांग, चीनी ताईपेई से पूरे विश्व में निर्यात भारत को छोड़कर अन्य देशों को कास्टिक सोडा की निर्यात कीमत, उत्पादकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन आदि का साक्ष्य दिया है।

45. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि चीनी ताईपेई में कास्टिक सोडा के उत्पादन की पर्याप्त फालतू क्षमता है और रिकार्डों में उपलब्ध साक्ष्य से मालूम होता है कि मौजूदा उत्पादक क्षमता में और वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि चीनी ताईपेई में वर्तमान क्षमता उनकी घरेलू खपत से लगभग 50% अधिक है और इसलिए उत्पादकों के पास किसी भी कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि, चीनी ताईपेई से कोई निर्यात नहीं हो रहा है तथापि चीनी ताईपेई के उत्पादक नियमित रूप से नाल्को की निविदाओं में भाग ले रहे हैं। चीनी ताईपेई से अन्य देशों को जिस नियत पर निर्यात किया जा रहा है वह पर्याप्त रूप से उस कीमत से कम है जिसपर घरेलू बाजार में सामग्री बेची जा रही है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 में चीनी ताईपेई उत्पादक ने नाल्को की निविदा में भाग लिया और विभिन्न एजेंटों के जरिए 150000 मी.ट. और 6200 मी.टन की पेशकश की। इसके अलावा फोर्मासा प्लास्टिक अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि कर रहा है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उक्त स्थिति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता है और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाए तो निर्यातक भारत में सामग्री की बाढ़ ला देंगे और भारतीय बाजार के लिए अपनी अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग करेंगे।

46. घरेलू उद्योग में काराणात्मक संबंध साबित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड प्रस्तुत किए हैं:-

- (क) उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता।
- (ख) पर्याप्त मूल्य कटौती की संभावना और मौजूदगी।
- (ग) उपभोक्ता आयातों को प्राप्त करेंगे।
- (घ) घरेलू कीमतें कम करने के लिए बाध्य होगा अथवा घरेलू उद्योग बिक्री की मात्रा कम करने के लिए बाध्य होगा।
- (ङ) उचित कीमत वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योग की अस्थिरता।
- (च) कम इष्टतम लाभ

- i) जांच का वर्तमान प्रारंभ परिवर्तित परिस्थितियों में किसी ठोस साक्ष्य के बगैर पर्याप्त कारण और औचित्य के बिना किया गया है।

- ii) जांच अवधि में पाटन न होने के बारे में याचिकाकर्ता का दावा संबद्ध देशों में याचिकाकर्ताओं अथवा निर्यातकों द्वारा सिद्ध करना होगा।
- iii) वर्तमान जांच अवधि में पाटन का न होना स्वयं शुल्क समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है।
- iv) निर्यातक से संबंधित तथ्य और परिस्थितियां ऐसी हैं कि निर्यातक द्वारा अपनी गतिविधियां बढ़ाने की संभावना है तो क्या ऐसी परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्कों को वापस लिया जाना चाहिए।
- v) "कोई पाटन नहीं" और "पाटन की कोई संभावना नहीं" साबित करने की जिम्मेदारी घरेलू उद्योग की नहीं बल्कि आवेदक की है।
- vi) क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच के लिए क्या संगत है, 2005 में योजनागत क्षमताओं तक सीमित नहीं है बल्कि उसके बाद भी योजनागत क्षमताओं तक भी है। हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि निर्यातक ने दीर्घकालिक ठेके लिए हैं, परंतु ऐसे ठेके समग्र अतिरिक्त क्षमताओं के लिए नहीं हैं।
- vii) नाल्को ने लाई और ठोस कास्टिक सोडा के लिए अलग बैंच आदि की सिफारिश की है। भारतीय उत्पादकों की लाई और ठोस कास्टिक सोडा के लिए अलग बैंच मार्क नियत करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि लाई और ठोस समान वस्तु नहीं है। ठोस कास्टिक सोडा लाई कास्टिक सोडा को उत्तरोत्तर प्रसंस्करण (शुष्कन) द्वारा बनाया जाता है।
- viii) घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि यह मानते हुए कि संचयन नहीं किया जा सकता इसलिए रिकार्ड में साक्ष्य से प्रत्येक अलग-अलग संबद्ध देशों से क्षति का जारी रहना अथवा पुनरावृत्ति होना स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है।

च-2. आवेदक, निर्यातक/आयातक/अन्यहितबद्ध पक्षकारों के विचार

47. हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया कि

- (क) घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति के अपने तर्क समर्थन किसी वास्तविक साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ख) रिलायंस ने जी.सी.एण्ड आईएस, आईवीआईएस आयात बीजकों से आपात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं भारतीय उत्पादकों का यह दावा कि इंडोनेशियाई कीमतें जो डीजीसीआई एंड एस में सूचित की गई है कि प्राधिकारियों से सौदेवार आंकड़ों को प्राप्त करके यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि वे ठीक हैं।
- (ग) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मूल याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग से क्षति की सूचना और लागत मांगनी चाहिए और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के सामने प्रकट करना चाहिए।
- (घ) एडीए के अनुच्छेद 3.4 के अंतर्गत सभी सूचीबद्ध घटकों की भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रपत्र IV-A में जांच नहीं की गई है। कथित पाटन और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। कुछ मानदंड जैसे क्षमता का उपयोग माल सूचियां, वेतन और निर्यात आदि केवल कास्टिक सोडा लाई के लिए ही तैयार किए गए हैं न कि कास्टिक सोडा कि ठोस अवस्था अथवा फलैक अवस्था के लिए।
- (ङ) चीनी टाईपेई के लिए कम मूल्य पर बिक्री और कीमत कटौतियों की गणना की पद्धति किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। घरेलू उद्योग की कीमतें आयात कीमत की तुलना

- में पर्याप्त रूप से अधिक थी इसलिए कोई कारणात्मक संबद्ध अथवा क्षति नहीं हुई है चीनी तार्इपेई से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग की क्षति का कोई खतरा मौजूद नहीं है।
- (च) घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर 12% से अधिक लाभ जीएफए पर 8.5 प्रतिशत और एनएफए आधार पर 15.5 प्रतिशत के क्षेत्र में पहले से है लगभग 22 प्रतिशत-30 प्रतिशत की आरओसीई तर्क करने योग्य नहीं है। आरओसीई के मुद्दे पर भारतीय स्पीर्नस एसोसिएशन बनाम डीए 2004(170) ईएलटी 144 (टरार्ड-डल) में कार्रवाई की गई है और इस मामले को इस मुद्दे में एक दिशा निर्देश के रूप में दिया जाना चाहिए। क्षति विश्लेषण से यथा मूल्यांकित समीक्षा अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और इस प्रकार यह अनुच्छेद 3.1 और नियम 11 (2 तथा अनुबंध का उल्लंघन है)। एडीए के अनुच्छेद 3.4 के अंतर्गत आदेशित सूचीबद्ध घटकों की जांच नहीं की गई है।
- (छ) लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना अपूर्ण और कमीयुक्त, क्षति आरोपों से बचाव के लिए हितबद्ध पक्षकारों को रोकने वाली है कथित पालन और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबद्ध नहीं है। सूचना अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात 4.75 प्रतिशत जबकि अन्य देशों से बिक्रिया सकल भारतीय आयातों 95.25 प्रतिशत के बराबर।
- (ज) घरेलू उद्योग किया गया क्षति विश्लेषण अधूरा है कुछ मानदंड जैसे क्षमता उपयोग मालसूचियां, वेतन तथा निर्यात आदि केवल कास्टिक सोडा लाई के लिए किए गए हैं न कि ठोस रूप में अथवा फलैक रूप में कास्टिक सोडे के लिए। निर्यातक चीनी तार्इपेई से पाटन के आरोपों की जांच अथवा टिप्पणी करने में असमर्थ क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा साक्ष्य नहीं बताया गया है कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती की गणना के लिए चीनी तार्इपेई हेतु पद्धति को सकारात्मक बनाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- (झ) घरेलू बाजार में कीमतें आयात कीमत से पर्याप्त रूप से अधिक थी इसलिए क्षति अथवा कारणात्मक संबद्ध नहीं रहा है चीनी तार्इपेई से संबद्ध वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योगों की क्षति का कोई खतरा विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां जांच अवधि के दौरान कोई पाटित आयात नहीं हुए हैं शुल्क लगाने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त पूरी नहीं होती है समीक्षा अवधि में पाटित आयात अवश्य होने चाहिए और सूचना अवधि में बिना पाटन में वास्तविक क्षति के खतरे के लिए कोई मामला मान्य योग्य नहीं हो सकता।
- (ट) भारतीय उत्पादक निर्यातकों द्वारा योजनाबद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के मुद्दों पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटन के खतरे गुमरहा नहीं कर सकते। निर्यातकों द्वारा 2005 के लिए क्षमताओं बढ़ाने अथवा उत्पादन मात्राओं की वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है क्षमताओं में वृद्धि की योजना आस्ट्रेलिया और अन्य दक्षिणी अमेरिकी बाजारों के लिए बनाई गई है।
- (ठ) जहां तक कीमत कटौती और कम कीमत पर कटौती का संबद्ध है। प्राधिकारी को ऐसे कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जिनके आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकें इसे प्रकट करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के निवेदन पर शुरू की गई थी। यह नोट करना समीक्षाधीन है कि तार्इवान में पाटन रोधी शुल्क

लगाने के पश्चात् संबंध वस्तुओं का निर्यात बन्द कर दिया है इसलिए कटौती और कम कीमत पर बिक्री के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

- (ड) उन्होंने निवेदन किया है कि अधिकांश क्षति मानदंडों में जांच अवधि के दौरान सकारात्मक अवधि दर्शाई गई है। इसलिए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती। यह भी बताया गया है कि संबंध देशों से पाटित आयातों में जांच अवधि के दौरान कमी आई है, विशेष रूप से इंडोनेशिया और ईयू के आयात अत्यधिक कम हो गए और चीनी ताईपेई से कोई निर्यात नहीं हुआ है।

च-3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 में यह व्यवस्था है कि कोई पाटनरोधी शुल्क जब तक लागू रहेगा और उस सीमा तक लागू रहेगा जहां तक पाटन का प्रति संतुलन आवश्यक है जिससे क्षति उत्पन्न होती है। मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी यह जांच करते हैं कि क्या पाटन और क्षति से संबंधित परिस्थितियां पर्याप्त रूप से बदल गई हैं अथवा क्या मौजूदा उपाय पहले साबित हुई क्षति का निराकरण करने के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी को समीक्षा के लिए जरूरत को सिद्ध करने वाली किसी हितबद्ध प्रस्तुत पक्षकारक सकारात्मक सूचना के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने के बाद एक उचित समयावधि व्यतीत हो गई है, क्या पाटन को समाप्त करने के लिए निरंतर शुल्क लगाया जाना आवश्यक है, क्या यदि शुल्क को हटा लिया जाए अथवा परिवर्तित कर दिया जाए अथवा दोनों कार्य हो जाएं तो क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना होगी। वर्तमान मध्यावधि समीक्षा मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा दायर सकारात्मक सूचना के आधार पर शुरू की गई है।

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होती रहने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है और उनकी प्राधिकारी के समक्ष दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए जांच की गई है यह नोट किया जाता है कि शुल्क संबंध देशों से संबंध वस्तुओं के सभी आयातों पर संदर्भ कीमत के आधार पर मूल रूप से लगाया गया था। यह भी नोट किया गया है कि पाटन रोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार की समीक्षा शुरू की गई है जिसमें प्राधिकारियों के लिए ये अपेक्षित है कि क्या शुल्क लगातार लगाए रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है और पाटन की मात्रा तथा सीमा और क्षति तथा जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और प्रस्तुत किए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए शुल्क को वापस लेने की आवश्यकता की जांच करना शामिल है इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के लिए यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग के संबंधित अवधि में लगातार क्षति हुई है तत्पश्चात्, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारण करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की दशा में क्षति जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है।

50. वर्तमान क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबंध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच की है। पाटित मार्जिन ईयू (फ्रांस को छोड़कर) और इंडोनेशिया के निर्यातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है और पाटन की संभावना को चीनी ताईपेई, ईयू तथा इंडोनेशिया से निर्धारित किया गया है ईयू

(फ्रांस को छोड़कर) और इंडोनेशिया से समस्त निर्यातों को क्षति विश्लेषण और कारणात्मक संबद्ध की जांच के के प्रयोजनार्थ पाटित आयातों के रूप में माना गया है।

क्षति का संचिय मूल्यांकन

51. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीनी ताईपेई, इंडोनेशिया और फ्रांस को छोड़कर यूरोपीय सांघ है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंधों में यह व्यवस्था है कि यदि पाटनरोधी जांच में एक साथ एक से अधिक देश अंतर्ग्रस्त है तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी संचिय रूप ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा जब वह केवल यह निर्धारित करता हो कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबद्ध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयातों की निर्यात कीमत और मात्रा तीन प्रतिशत से अधिक हो, आयात एकत्रित रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक हो (ख) आयातों के संचिय मूल्यांकन का प्रभाव आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के अनुसार सूचित हो। वर्तमान जांच नियमावली के नियम तेईस के अंतर्गत शुरू की गई मध्यावधि समीक्षा जांच है इसलिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संचिय मूल्यांकन की विभिन्न शर्तें केवल कुछ संशोधनों के आधार पर इस जांच में लागू होगी। तदनुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना अथवा पुनरावृत्ति तथा उसको हुई हानि का मूल्यांकन किया है।

52. सूचना की जांच के बाद प्राधिकारी को यह मालूम हुआ कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कीमत तुलनीय है और उनमें अधिक अंतर नहीं है उनका निर्यात उसी टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत किया गया है आयातित उत्पादों और घरेलू उत्पाद के लिए प्रयोक्ता उद्योग एक ही है इसलिए प्राधिकारी आयातित उत्पादों और आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की सूचियों तथा घरेलू समान उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की दृष्टि से घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तु के संबद्ध वस्तुओं के आयातों के प्रभाव का संचिय रूप से मूल्यांकन करना उचित समझता है। इस जांच में घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा क्षति के प्रभाव की संचिय रूप से जांच करना उचित है।

मात्रा का प्रभाव

53. पाटित आयातों की मात्रा के बारे में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समुचित मात्रा के अनुसार अथवा उत्पादन अथवा खपत की सापेक्षता के अनुसार पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है पाटनरोधी नियमावली अनुबंध II(ii) में यह व्यवस्था है कि:

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उपप्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा की क्या भारत में वास्तविक मात्रा अथवा उत्पादन अथवा खपत की सापेक्षता में पाटित आयातों में काफी बढ़ोतरी हुई है।"

मांग और बाजार के हिस्से का मूल्यांकन ...

54. भारत में उत्पाद की मांग और प्रत्यक्ष खपत की गणना घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों के योग, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों और विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के योग से की गई है इस प्रकार से मूल्यांकित मांग को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

	2001-02	2002-03	2003-04	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	****	****	****	****
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	****	****	****	****
आयात:				
ई.यू. (फ्रांस को छोड़कर)	22	30,982	86	165
इंडोनेशिया	4,972	42,372	18,398	3,745
चीनी ताईपेई	327	13,428	-	-
संबद्ध देशों से आयात	5,321	86,783	18,484	3,910
अन्य स्त्रोतों से आयात	33,650	27,902	52,145	76,100
कुल आयात	38,971	114,685	70,629	80,010
मांग	1,623,806	1,792,411	1,811,779	1,874,596
सूचीबद्ध	100.00	110.38	111.58	115.44

55. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग क्षति की अवधि के दौरान सकारात्मक परीवर्ती में रही है। घरेलू उद्योग की बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान सुधारा हुआ है जिससे मालूम होता है कि घरेलू उद्योग विगत पाटन से बहाल हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया और ईयू (फ्रांस को छोड़कर) से कास्टिक सोडे का निरंतर आयात हुआ है। जांच में यह भी मालूम हुआ है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों निर्यात जारी रखने अथवा दोबारा शुरू करने की संभावना है इसलिए क्या इस स्थिति में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने चाहिए।

56. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान आयातों की कम मात्रा से पाटनरोधी शुल्कों को हटाने की स्थिति में क्षति की कोई संभावना सिद्ध नहीं होती है। बल्कि रिकार्ड में दिए गए साक्ष्य से ये सुझाव मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाने की स्थिति में आयातों की पर्याप्त रूप से बढ़ने की संभावना है जैसा कि पाटन से संबंधित पैराग्राफ में विस्तारित रूप से नोट किया गया है। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि हितबद्ध पक्षकार से साबित नहीं कर सके हैं कि पाटनरोधी शुल्क को हटाने की स्थिति में आयात मात्राएं बढ़ने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत जांच से यह मालूम हुआ है कि पाटनरोधी शुल्क हटाने की स्थिति में आयात मात्राओं की बढ़ने की संभावना है।

कीमत प्रभाव

57. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में नियमावली के अनुबंध II(ii) में निम्न प्रकार से निर्धारण है नियम 18 में उप-नियम (2) में उल्लिखित कीमतों के संबंध में पाटित आयातों के प्रभावों के बारे में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या भारत में वाहन

उत्पादित कि कीमत के साथ तुलना के रूप में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में अत्याधिक कटौती की गई है अथवा क्या पर्याप्त मात्रा में कीमतों का कम करने के लिए अन्य प्रकार से ऐसे आयातों का प्रभाव हुआ है अथवा कीमतों की वृद्धि करने में रोका गया है जिससे अन्य प्रकार की पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

58. किसी समीक्षा जांच में यह जांच करना आवश्यक है क्या भारत में समान उत्पाद कि तुलना में पाटित आयातों की तुलना में पर्याप्त कीमत प्रभाव हुआ है, अथवा क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाने के बाद कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है ये देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारक कीमत से बहुत अधिक कम है। आयातों से पाटनरोधी शुल्कों के हटाने के मामले में घरेलू कीमतों को काफी सीमा तक कम करने की पर्याप्त संभावना है इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग पर पर्याप्त कीमत कम करने का प्रभाव होने की संभावना है। इसलिए यह नोट किया जाता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने की स्थिति में प्रतिकूल कीमत प्रभाव होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

59. नियमों के अनुबंध 11 में यह आवश्यक है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की जांच करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, नियमों के अनुबंध 11(iv) में निम्नलिखित निर्धारित है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्रियों में प्राकृतिक और संभावित गिरावट, लाभ, निष्पादन बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ अथवा क्षमता का उपयोग घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक पाटन के मार्जिन की मात्रा नकदी प्रवाह माल सूचियों पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजीनिवेशों को जुटाने की क्षमता सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव रखने वाले संबंधित आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन करना शामिल है।"

वास्तविक और संभावित उत्पादन और क्षमता और क्षमता उपयोग, बिक्रियां

60. घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राओं से संबंधित सूचना इस प्रकार है:-

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-पीओआई
घरेलू उद्योग की क्षमता	910,098	910,098	910,098	910,098
घरेलू उद्योग का उत्पादन	819,011	846,998	883,927	911,244
सूच्यवृद्धि	100.00	103.42	107.93	111.26
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग	89.99	93.07	97.12	100.13
घरेलू उद्योग	756,219	784,438	837,535	861,367
सूच्यवृद्धि	100.00	103.73	110.75	113.90

यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों से समस्त क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। घरेलू उद्योग का उत्पादन विभिन्न स्रोतों से कास्टिक सोडे के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से बिक्रियों की वृद्धि की प्रतिक्रिया में घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है जिसमें संबद्ध देश शामिल हैं। तथापि, यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक नियमित रूप से अन्य देशों को पर्याप्त मात्रा पर निर्यात कर रहे हैं और जांच से यह मालूम हुआ है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है।

उत्पादकता में वास्तविक और संभावित गिरावट

	2001-02	2002-03	2003-04	जनवरी-दिसंबर 04
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	****	****	****	****
उत्पादकता प्रवृत्ति-सूचीबद्ध	100.00	107.65	116.55	129.10

61. घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति की अवधि के दौरान सुधरी है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने पिछली चार जांचों में बहुत से स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पर जांच अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन और उत्पादकता में सुधार किया है।

क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट

62. घरेलू उद्योग की क्षमता का वर्तमान उपयोग इस प्रकार रहा है:-

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-पीओआई
घरेलू उद्योग की क्षमता	910098	910098	910098	910098
घरेलू उद्योग का उत्पादन	819011	846998	883927	911244
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग	89.99	93.07	97.12	100.13

उपर्युक्त के आधार पर यह नोटिस किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग सुधरा है। घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग पूर्ववर्ती जांचों में विभिन्न स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि होने के कारण बढ़ोत्तरी हुई है। यह नोट किया जाता है कि पूरी क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है तथापि वर्ष 2001-02 के दौरान 100 से बढ़कर जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग 115 बड़ी और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई।

बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट

63. घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री की स्थिति इस प्रकार रही है:-

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	103.73	110.75	113.90

घरेलू उद्योग की बिक्रिया समस्त अवधि के दौरान बढ़ी है। यह भी देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटन आयातों का हिस्सा वर्ष 2001-2002 के दौरान 13.65 प्रतिशत से घटकर जांच अवधि के दौरान 5.08 प्रतिशत हो गया है जबकि, अन्य देशों से आयात वर्ष 2001-2002 के दौरान 86.35 प्रतिशत से बढ़कर 94.92 प्रतिशत जांच अवधि के दौरान हो गए थे। संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा मोटे तौर पर आधारवर्ष 2001-2002 की तुलना में जांच अवधि के दौरान लगभग 100 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

निवेश पर लाभ, प्राप्तियां और नकदी प्रवाह

64. घरेलू उद्योग के वर्तमान और संभावित लाभों की स्थिति, निवेश पर लाभ और नकदी प्रवाह की जांच की गई है। घरेलू उद्योग के इन मानदंडों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

लाख में	2001-02	2002-03	2003-04	2004-पीओआई
कर पूर्व लाभ	****	****	****	****
सूचीबद्ध	(100.00)	(339.62)	(150.63)	14.12
ब्याज और कर पूर्व लाभ	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	(3.24)	74.32	179.64
निवेश पर लाभ	5.62	(0.50)	1.84	0.04
सूचीबद्ध	100.00	(8.94)	32.75	0.69
नकद लाभ	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	(91.77)	9.51	37.56

65. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के घाटे 2002-03 के दौरान बढ़े हैं जबकि उनकी तुलना आधार वर्ष और 2003-04 के साथ की जाए और घरेलू उद्योग के घाटे वर्ष 2002-03 की तुलना में कम हुए हैं। वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच की मूल जांच संबद्ध वस्तुओं की चौथी जांच थी और इस जांच की महत्वपूर्ण तारीखें तथा घटनाएं निम्न प्रकार हैं:-

क्रम सं.	घटना	तारीख
1	अमरीका, जापान, साउदी अरब, इरान और फ्रांस के विरुद्ध पहली जांच (जांच की अवधि अप्रैल 1998-सितम्बर 1999 तक)	
	➤ जांच की प्रारंभ	26.05.2000
	➤ प्रारंभिक जांच परिणाम	16.11.2000
	➤ प्रारंभिक एमओएफ	26.12.2000
	➤ अंतिम जांच परिणाम	26.12.2000
	➤ अंतिम एमओएफ	14.05.2001
2	कतर के विरुद्ध दूसरी जांच (जांच की अवधि जनवरी 2001 से सितम्बर 2001)	
	➤ जांच की प्रारंभ	08.10.2001
	➤ प्रारंभिक जांच परिणाम	18.01.2002
	➤ प्रारंभिक एमओएफ	27.03.2002

	➤ अंतिम जांच परिणाम	7.10.2002
	➤ अंतिम एमओएफ	31.10.2002
3	चीन और कोरिया के विरुद्ध तीसरी जांच (जांच की अवधि 2001-02)	
	➤ जांच की प्रारंभ	14.05.2002
	➤ प्रारंभिक जांच परिणाम	21.09.2002
	➤ प्रारंभिक एमओएफ	26.12.2002
	➤ अंतिम जांच परिणाम	04.08.2003
	➤ अंतिम एमओएफ	26.12.2003
	चीनी ताईपेई, इंडोनेशिया और फ्रांस को छोड़कर ईयू (जांच की अवधि जनवरी 2002-सितम्बर 2002 तक)	
4	➤ जांच की प्रारंभ	08.10.2002
	➤ प्रारंभिक जांच परिणाम	08.01.2003
	➤ प्रारंभिक एमओएफ	27.03.2003
	➤ अंतिम जांच परिणाम	01.10.2003
	➤ अंतिम एमओएफ	14.11.2003

66. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग आधारवर्ष के दौरान कोरिया और चीन पाटित आयातों के कारण पीड़ित रहा था और बाद में उसे इंडोनेशिया, चीनी, ताईपेई और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से पाटित आयातों के दौरान क्षति का सामना करना पड़ा था। इन स्त्रोतों पर शुल्क लगाने के पश्चात घरेलू उद्योगों का कार्यनिष्पादन सुधरा था हालांकि घरेलू उद्योगों का लाभ जांच अवधि के दौरान (पीबीटी) कम हुआ है। निवेश पर लाभ के बारे में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ जांच अवधि के दौरान घट गया है। घरेलू उद्योग के अधिकांश उत्पाद बहुउत्पाद कंपनियों के हैं और विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग नकदी प्रवाह नहीं रखते हैं इसलिए घरेलू उद्योग की नकदी प्रवाह की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। तथापि, घरेलू उद्योग का नकद लाभ भी जो जांच अवधि के दौरान घट गया है।

बाजार के हिस्से में वास्तविक और संभावित गिरावट

67. पाटित आयातों में वास्तविक और संभावित वृद्धि और घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से पर इसके प्रभाव की जांच की गई थी। संबद्ध देशों से आयातों की स्थिति और भारत में उत्पादन/खपत के संबंध में आयातों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

	2001-02	2002-03	2003-04	पीओआई
आयात-				
➤ फ्रांस को छोड़कर ई.यू.	22	30982	86	165
➤ इंडोनेशिया	4972	42372	18398	3745
➤ चीनी ताईपेई	327	13428	00	00
➤ संबद्ध देश	5321	86783	18484	3910
➤ अन्य देश	33650	27902	52145	73100
➤ कुल आयात	38971	114685	70629	77010

मांग	1623806	1792411	1811779	1871596
आयातों में बाजार का हिस्सा				
➤ फ्रांस को छोड़कर ई.यू.	0.06	27.02	0.12	0.21
➤ इंडोनेशिया	12.76	36.95	26.05	4.86
➤ चीनी ताईपेई	0.84	11.71	00	00
➤ संबद्ध देश	13.65	75.67	26.17	5.08
➤ अन्य देश	86.35	24.33	73.83	94.92
मांग में बाजार का हिस्सा				
➤ घरेलू उद्योग	46.43	43.76	46.23	46.02
➤ अन्य उत्पादक	51.17	49.84	49.87	49.86
➤ संबद्ध देश	0.33	4.84	1.02	0.21
➤ अन्य देश	2.07	1.56	2.88	4.06
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात	0.65	10.25	2.09	0.43
➤ घरेलू उद्योग की बिक्रियों के संबंध में आयात	0.70	11.06	2.21	0.45

68. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों का कुल आयातों में बाजार हिस्सा 2001-2002 में 13.65 प्रतिशत से घटकर जांच अवधि के दौरान 5.08 प्रतिशत रह गया था और मांग में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक नहीं है और इसमें जांच अवधि के दौरान गिरावट आई थी इस प्रकार वर्तमान शुल्कों की मौजूदगी से मांग में आयातों का बाजार हिस्सा घटा था जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पहले कम हुआ और बाद में इसमें सुधार आया। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के बाजार हिस्से की संभावित स्थिति की भी यह जांच की थी कि क्या वर्तमान शुल्कों को वापस ले लिया जाए। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से निर्यातों की स्थिति की जांच की थी और यह पाया था कि पाटित आयातों तथा बाजार के हिस्से में गिरावट विभिन्न स्तरों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण भी आई थी। संबंधित देशों से भारत में तथा अन्य देशों में उत्पादकों और निर्यातकों की निम्न स्तरों पर विचार करते हुए रिकार्ड में दी गई सूचियां से मालूम होता है कि उत्पादक और निर्यातक भारतीय बाजार में व्याप्त कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर अत्यधिक मात्रा का निर्यात कर रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों में निर्यातक कम कीमतों पर अन्य देशों में निर्यात कर रहे हैं और उनके पास फालतू क्षमता उपलब्ध है। यह नोट किया गया है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये उत्पादक और निर्यातक यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो भारत में अत्यधिक सामग्री का निर्यात नहीं करेंगे। पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संभावित आयातों की मात्रा के कारण यह नोट किया जाता है कि मांग में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा एक बार पुनः अत्यधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा।

रोजगार तथा वेतन

69. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के अधिकांश घटक बहु उत्पाद कंपनियां हैं इसलिए घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर पर पाटन का कोई प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता। घरेलू उद्योग की रोजगार की स्थिति के स्तरों और वेतनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-पीओआई
रोजगार	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	96.07	92.60	86.18
वेतन	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	99.62	109.98	120.66

हालांकि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में जांच अवधि के दौरान गिरावट मालूम होती है और कोई ठोस तर्क उपलब्ध नहीं कराया गया था। वेतनों में कोई गिरावट मालूम नहीं हुई बल्कि वेतनों में बढ़ोत्तरी मालूम हुई है जो वेतनों में वृद्धि प्रतिबिंबित करती है।

कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

70. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों द्वारा कीमतों में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या अन्य प्रकार से अत्यधिक मात्रा में कीमतें कम करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने में ऐसे आयातों का प्रभाव रहा है जो अन्यथा अत्यधिक मात्रा में हुआ होता। घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान आयात कीमतों का विश्लेषण किया और यह पाया कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने भारत को अपने निर्यातों के संबंध में बहुत कम कीमतें लगातार बनाई रखीं। सीमा शुल्क में गिरावट और आयातों की कीमतों में गिरावट से आयातों की पहुंच कीमत में और कमियां आई हैं। घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा के कारण लागत ढांचे में परिवर्तन प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापकों की कीमतों की जांच पाटित आयातों के अलावा अन्य घटकों का विश्लेषण करने के लिए की गई है जिनसे घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रभाव हो सकता था और यह नोट किया गया है कि इस उत्पाद का कोई कार्यक्षम प्रतिस्थापक नहीं है और कीमतों पर पाटित कीमतों के कारण प्रभाव पड़ा था।

71. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने करों और शुल्कों, छूटों, डिस्काउंट और भाड़े तथा परिवहन को छोड़कर बिक्री कीमत को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूलियों का निर्धारण किया था। घरेलू उद्योग की समस्त बिक्री मात्राएं इस प्रयोजनार्थ ध्यान में रखी गई हैं आयातों की पहुंच कीमत 1 प्रतिशत पहुंच प्रभारों और लागू मूल सीमा शुल्क के साथ सीआईएफ आयात कीमत की भारित औसत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। तुलना निवल बिक्री प्राप्ति और कार्बोनेट सोडा लाई और प्लेक्स के लिए अलग-अलग आयातों की पहुंच कीमत के बीच की जाती है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की तुलना भारित औसत पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई है। ताईवान के संबंध में वे कीमतें जिनपर तीसरे देशों को वस्तुओं का निर्यात किया गया था उन्हें यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया गया था कि क्या घरेलू उद्योग की कीमतों में निर्यातों के कारण कटौती होने की संभावना है, क्या उन्हें उसी कीमत पर निर्धारण रखना है जिसपर इन्हें तीसरे देशों को निर्यात किया गया था। ताईवान के मामले में कीमत में कटौती का निर्धारण जांच अवधि के दौरान साबित सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था और उसे पहुंच

कीमत में निर्धारण करने के लिए भी प्रयोग किया गया था जिसमें यह मालूम करना था क्या ताईवानी निर्यातों के पाटित कीमतों पर होने की उम्मीद है, क्या निर्यात सामान्य मूल्य के बराबर अथवा कम कीमतों पर किए गए थे। यह मालूम हुआ है कि संबद्ध देशों से आयात का पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूलियों से कम था जिससे यह साबित होता है कि आयातों से पाटित शुल्कों को हटाने से घरेलू उद्योगों की बिक्री कीमत में कटौती करने में संभावना है। कटौती करने के मार्जिन जांच अवधि के दौरान 10 प्रतिशत से 48 प्रतिशत के बीच थे।

72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री यह निर्धारित करने के लिए कि क्षति के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्या निर्यातों से काफी मात्रा में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी होने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत पर विचार किया और उसकी तुलना घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री की सीमा परिकलित करने के लिए पहुंच मूल्य के साथ कि जो घरेलू उद्योग की समान कीमतों के आधार पर लागू होगी। जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पादन की लागत को उचित रूप से ध्यान में रखकर घरेलू उत्पादक के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत का मूल्यांकन किया गया है जिसमें क्षमता का उपयोग और नियोजित पूंजी पर उचित लाभ का विचार करने का मानदंड रखे गए हैं। विश्लेषण से यह मालूम होता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की भारित औसत पहुंच कीमत जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत से कम है। कम बिक्री पर कीमत का मार्जिन जांच अवधि के दौरान 17 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक था।

73. ईयू (फ्रांस को छोड़कर) और इंडोनेशिया के मामले में यह मालूम हुआ था कि जांच अवधि के दौरान आयात पाटित कीमतों पर आ रहे थे और ये कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती करवा रहे थे। इसके अतिरिक्त, एफपीसी के मामले में और ताईवान से अन्य उत्पादकों की स्थिति में यह मालूम हुआ था कि ईयू (फ्रांस को छोड़कर) और इंडोनेशिया से आयातों की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह संभावना है कि वे भी उन कीमतों पर निर्यात करेंगे जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने से इन निर्यातकों को ऐसी कीमतों पर सामग्री की बिक्री करने का अवसर प्राप्त होगा कि उनसे पर्याप्त मात्रा में घरेलू उद्योग को उद्योग की कीमते कम होने की संभावना होगी अथवा कीमतों में बढ़ोत्तरी को रोक देंगे जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में हो गया होता।

माल सूचियां

74. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जो निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

	2001-02	2002-03	2003-04	जनवरी-दिसंबर 04
माल सूची	****	****	****	****
प्रवृत्ति-सूचीबद्ध	100.00	132.51	103.92	93.00

उपर्युक्त के आधार पर यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के मालसूची स्तरों से 2002-03 और 2003-04 के दौरान वृद्धि के पश्चात जांच अवधि के दौरान गिरावट मालूम हुई थी और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो माल सूची का स्तर बढ़ सकता है क्योंकि शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप आयात में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग की बिक्री मामलों में गिरावट आएगी और इसके फलस्वरूप मालसूचियों में बढ़तोंत्तरी होगी।

वृद्धि

75. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों की जांच करने पर यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के विभिन्न मात्रा मानदंड सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं जो संबद्ध देशों के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण है। जिसमें अन्य देश भी शामिल है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योगों ने लाभ के मामले में अपने कार्य-निष्पादन में सुधार किया है तथापि अब भी घरेलू उद्योग उचित लाभ प्राप्त करने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वृद्धि पाटनरोधी शुल्कों के लगाने में सकारात्मक रही है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क के हटने की स्थिति में बढ़ने वाली संभावित मात्राओं और प्रतिकूल कीमत प्रभाव के कारण यह प्रत्यक्ष है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि पर पाटनरोधी शुल्कों को हटा लेने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

पाटन मार्जिन

76. यह नोट किया गया है कि ईयू (फ्रांस को छोड़कर) और इंडोनेशिया से आयात के मामले में पर्याप्त पाटन मार्जिन है और पाटनरोधी शुल्क की वापसी के मामले में पर्याप्त पाटन साबित हुआ है। पहली जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन भी अत्यधिक पाया गया था। रिकार्ड में दिए गए साक्ष्य से यह मालूम होता है कि संभावित पर्याप्त पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

77. लागत ढांचे में परिवर्तन, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा की जांच उन पाटित आयातों को छोड़कर कारकों का विश्लेषण करने के लिए जांच की गई है जिनसे घरेलू बाजार में कीमतें प्रभावित हो सकती थीं। यह नोट किया जाता है संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अत्यधिक कम है। इससे भारतीय बाजार में गंभीर रूप से कीमत कटौती हो रही है। यह भी नोट किया गया है कि इस उत्पाद का कोई कार्य क्षेत्र प्रतिस्थापक नहीं है और घरेलू जीविकों को आयातित माल के पहुंच मूल्य के साथ-साथ परस्पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यह नोट किया गया है कि कई स्त्रोतों से पाटित आयात एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और घरेलू उत्पाद घरेलू बाजारों को प्रभावित करते हैं जिसके लिए संचयी क्षति विश्लेषण किया गया है। यह भी मालूम हुआ है कि घरेलू बाजार में उत्पाद की पर्याप्त मांग है।

पूँजी और निवेश जुटाने की योग्यता

78. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की क्षमता में जांच अवधि के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने किसी और निवेश का प्रस्ताव नहीं किया है।

क्षति की मात्रा और क्षति का मार्जिन

79. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत की तुलना अति मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की भारत औसत पहुंच कीमत और क्षति मार्जिनों को पर्याप्त पाया गया है।

च-4 क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

80. प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि संबद्ध वस्तुएं निरंतर भारतीय बाजार में आ रही हैं और पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर निर्यात होने की संभावना है। यह जांच करना सुनिश्चित है कि क्या यदि शुल्क को हटा लिया जाए अथवा परिवर्तित कर दिया जाए तो इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह पहले ही साबित हो चुका है कि पाटनरोधी शुल्क के बगैर संबद्ध देशों से आयातों का वास्तविक पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर अतिकारक कीमत से काफी कम था।

81. लगातार अति, घरेलू उद्योग को निरंतर अथवा दुबारा अति होने की संभावना के अतिरिक्त प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और सूचना द्वारा घरेलू उद्योग की भी जांच की है। प्राधिकारी ने नियमों के अनुबंध-11(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए निरंतर होने अथवा दुबारा होने की जांच, जो इस प्रकार है:-

"वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण आरोप, आसन्न अथवा बाढ़ की संभावना के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित होगा। परिस्थितियों में परिवर्तन इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें डंपिंग से क्षति होगी, का अनुमान स्पष्ट रूप से और तुरंत लगाया जाना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के बारे में निर्धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेगा और:-

क) "आयात की पर्याप्त वृद्धि की संभावना का उल्लेख करते हुए भारत में पाटित आयातों की बढ़ोत्तरी की अत्यधिक दर।

(ख) किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में काफी अधिक पाटित निर्यात होने की संभावना का

उल्लेख करते हुए निर्यात की क्षमता में अत्यधिक मुख्य रूप से निपटान योग्य अथवा कोई आसन्न अत्यधिक बढ़ोत्तरी।

ग) क्या आयात उन कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर कम करने अथवा कटौती करने का प्रभाव पड़ेगा और उससे और अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी; और

घ) जांच की जा रही वस्तु की माल सूचियां।"

82. हितबद्ध पक्षकारों ने निर्यातक देशों की क्षमता उत्पादन और संबद्ध वस्तु की मांग के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है। यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में वर्तमान मामले में आयातों की मात्रा गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों का स्तर, अन्य देशों के सहयोगी निर्यातक की निर्यात कीमत, निर्यातकों के पास उपलब्ध फालतू क्षमताओं से यह सुझाव मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाने से संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना होगी। ऐसी स्थिति में जहां, लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया गया है वहां वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना होगी।

83. कुछ संबंधित देशों के उत्पादक नाल्को निर्यातक भारत में औद्योगिक ग्राहकों को पर्याप्त मात्राओं में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करते रहे हैं। यह नोट किया जाता है कि विगत में संबद्ध वस्तु के मुख्य आयातकों में से एक नाल्को पिछले तीन वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त आर्डर प्राप्त हुए हैं, जो निम्नलिखित से स्पष्ट हैं:-

नाल्को की निविदाओं की स्थिति	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
निविदा के अनुसार मी.ट. में मात्रा	100000	115000	120000	120000	120000
प्राप्त विदेशी प्रस्ताव	352000	262000	86000	38000	118000
प्राप्त भारतीय प्रस्ताव	83000	122000	134000	127400	147000
विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए आर्डर	100000	86000	32000	18000	0
भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए आर्डर	0	29000	88000	102000	120000

84. यह नोट किया जाता है कि भारतीय उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात क्षति की अवधि के दौरान नाल्को को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति के हिस्से में सुधार किया है और 2005-2006 के दौरान उन्होंने आपूर्तियों की समस्त मात्रा प्राप्त कर ली है। तथापि, नाल्को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए अपनी आवश्यकता निरंतर पूरी कर रहा है और पूरी करते रहने की संभावना है। वर्तमान स्थिति में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाने से गहन प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की संभावना है और विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों की पेशकश करने की संभावना है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को दुबारा क्षति होगी। संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त संचयी क्षमता भारत में समस्त खपत से अधिक है और विगत में की गई जांच से यह मालूम हुआ कि कास्टिक सोडे के लिए बाजार अत्यधिक अस्थिर है और संभावित पाटित कीमतों पर भारत को किए गए निर्यात की किसी अत्यधिक मात्रा से कीमत में कटौती करने की संभावना है और उसके बाद घरेलू उद्योग को क्षति होने

की उम्मीद है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस बात का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है कि संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं को भारतीय बाजार में आपूर्ति करने के लिए क्यों न प्रयोग किया जाए न ही इस बात को कोई ठोस कारण बताया गया है कि संभावित कीमतें भारत अथवा तीसरे देशों को वर्तमान निर्यात कीमतें तथा निर्यातक देशों में सामान्य मूल्य से क्यों अधिक होंगी।

85. ताइवान के मामले में चीनी ताईपेई से केवल एक निर्यातक ने सहयोग किया है और अन्य देशों को उत्पादन, बिक्री, क्षमता और निर्यातों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। इस कंपनी ने चीनी ताईपेई से अन्य देशों को निर्यात, उत्पादन और मांग के बारे में भी सूचना प्रदान की है। जहां तक एफपीसी का संबंध है यह नोट किया गया है कि केवल सत्यापित आकड़े पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए ध्यान में रखे गए हैं। पूरे देश के बारे में सूचना भी चीनी ताईपेई में एफपीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। एफपीसी की निर्यात कीमत से यह मालूम हुआ है कि एफपीसी भारत में घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमतों पर विभिन्न देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहा था और क्या एफपीसी को भारत में सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात करना चाहिए। आयातों की पहुंच कीमत भारत में घरेलू कीमत से अधिक और घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत से कम होगी। इस प्रकार, इससे भारतीय बाजार में पाटित आयातों की वृद्धि होने की संभावना प्रदर्शित होती है। इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना बनती है। क्या ताइवानी उत्पादक साबित सामान्य मूल्यों पर बिक्री करेंगे तो आयातों की पहुंच कीमत भारत में घरेलू कीमतों से बहुत अधिक होगी जिससे यह साबित होता है कि ताइवानी उत्पादकों को सामान्य मूल्य से बहुत कम कीमतों पर निर्यात करना होगा। तथापि, सामान्य मूल्य पर अथवा उससे कम पर कोई निर्यात घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत से पर्याप्त रूप से कम होगा।

86. लागू उपायों की समाप्ति का संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए यह नोट किया गया है कि यह स्पष्ट संकेत है कि संबद्ध देशों के पास अपने उत्पादन और निर्यात मात्राएं बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। पाटन जांच में निर्धारित निर्यात कीमत के आधार पर यह संभावना है कि उपायों की अनुपस्थिति में संबद्ध देशों के उत्पादक पाटित कीमतों की नीति अपना सकते हैं जिससे घरेलू उद्योग को और क्षति होगी जिसमें सुधार हुआ है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण प्रगति मालूम हुई है। पाटन की दृष्टि से अपनी कीमतों को कम करने के लिए इन देशों के निर्यातक उत्पादों की संभावना और संभावित पाटन की अनदेखी और इंकार नहीं किया जा सकता। संबद्ध देशों के उत्पादकों को कीमतों का ऐसा व्यवहार तथा संबद्ध वस्तु की अत्यधिक मात्राएं भेजने की उनकी योग्यता से बहुत की संवेदनशील वस्तु बाजार पर सामान्य कीमतें कम करने की पूरी संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष है कि क्या उपायों को समाप्त किया जाए तो घरेलू उद्योग को दुबारा क्षति होने की संभावना होगी।

87. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिए हैं क्योंकि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षतिकारक पाटन का साक्ष्य नहीं दिया है। इसलिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या क्षति दुबारा होने की संभावना है, क्या उपायों को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने शुल्क समाप्त करने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों की संभावित मात्रा के बारे में तथा ऐसी संभावित कीमतों पर

जिनपर आयात किए जाएंगे तथा ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। आवदेक ने यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ने अपना दावा विदेशी उत्पादकों के पास पर्याप्त निपटान क्षमता तथा भविष्य में संभावित पाटन को साबित किए बगैर किया है। अकेले निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि उनके उत्पादन पूरे तरह से उपयोग किए जाते हैं और उसके पास न तो निर्यातक के लिए पर्याप्त निपटान क्षमता है और न ही संबद्ध वस्तुओं की कोई असामान्य मालसूची है। इन बेकार आरोपों से क्षतिकारक पाटन की भावी संभावनाओं की किसी आंशका का कोई आधार नहीं बन सकता। उन्होंने तर्क दिया है कि एफपीसी के विरुद्ध कोई पाटनरोधी उपाय नहीं है। इसलिए इसके फलस्वरूप ऐसे देश से भारत के बाजारों में संबद्ध वस्तुओं को भेजा जाए।

88. घरेलू उद्योग में यह तर्क दिया था कि ईयू (फ्रांस को छोड़कर) और इंडोनेशिया से निर्यातक भारतीय बाजारों में लगातार पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करते रहे और संबद्ध देशों में उत्पादकों को भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के पाटन का सहारा लेने की संभावना है। संबद्ध देशों में क्षमताएं उनकी अपनी संबंधित घरेलू बिक्रियों/मांग की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। चीनी ताईपेई के मामले में वर्तमान अधिशेष उपलब्ध होने के अतिरिक्त एफपीसी द्वारा अत्यधिक विस्तार किया जा रहा है जो मूलतः अगस्त 2005 में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए देय है और जिसके ब्यौरे स्वयं एफपीसी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, को क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है। (यह दोहराया गया है कि एफपीसी ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि समस्त विस्तार तीसरे देशों के लिए था और कोई अधिशेष अन्य देशों को निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं होगा।)। घरेलू उद्योग ने पुनः यह जोर दिया है कि घरेलू और आयातित सामग्री के बीच कीमत अंतर इतना अधिक रहा है कि इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण न हो कि ये संबद्ध देश पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की पर्याप्त मात्रा नहीं भेजेंगे।

89. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और निवेदनों की जांच इन संबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/साक्ष्य तथा तीसरे देशों और भारत को किए गए निर्यातों और वर्तमान तथा संभावित क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों, आयातों, निर्यातों, घरेलू मांग और घरेलू बिक्रियों के संबंध में कीमतों के स्तरों, संबद्ध देशों से आयातों की संभावित कीमतों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। यह निर्धारित करने के लिए क्या पाटन को रोकने के लिए निरंतर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया:-

1. मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन;
2. इस प्रयोजनार्थ वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन जब कभी भारत को निर्यात जांच अवधि के दौरान हुए हों, उन पर विचार किया गया और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया। जहां जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किए गए थे प्राधिकारी ने तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन तथा साबित सामान्य मूल्य और अनुसंशित किए जाने वाले बेंच मार्क को ध्यान में रखते हुए पाटन की संभावना का निर्धारण किया था।

3. विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए ज्ञात विस्तारों, भारत में व्याप्त कीमतों विगत निर्यातों की वास्तविक और संभावित मात्रा पर विचार करने हुए वर्तमान और संभावित अप्रयुक्त अधिशेष क्षमताएं।

इन कारकों की जांच करने पर यह नोट किया गया है कि;

- (क) तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी अधिक है;
- (ख) अनुसंसा के लिए प्रस्तावित बैच मार्क पर विचार करते हुए क्या निर्यात इस बैच मार्क से कम किए गए थे, और क्या वे पाटित कीमतों पर किए गए थे। क्या सामान्य मूल्य से अधिक कीमत पर निर्यात किए जाएं। इसलिए पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होगा। अतः निर्यातों के पाटित मूल्यों पर किए जाने की संभावना है यदि आयात अनुसंशित किए जाने वाले प्रस्तावित बैच मार्क से कम हों।
- (ग) तीसरे देशों को निर्यात कीमत की कारखाना बाह्य वसूली ऐसी कीमतों पर हुई है कि इन कीमतों पर निर्यात किए जाने चाहिए, इसके फलस्वरूप आयातों की पहुंच कीमत भारत में बिक्री कीमतों और गैर-क्षतिकारक कीमत से बहुत कम होगी;
- (घ) एक ताईवानी निर्यातक ने अकेली निविदा पर 1.5 लाख मी.ट. आपूर्ति करने को स्वीकार किया है जो इसकी अतिरिक्त क्षमता और निर्यात संभावना का पूरा सूचक है;
- (ङ) ताईवान से तीसरे देशों को निर्यात कीमत न केवल सामान्य मूल्य से बहुत कम है बल्कि भारत में मौजूद कीमतों और गैर-क्षतिकारक कीमत से भी बहुत कम है;
- (च) निर्यातकों द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना नहीं होगी और पाटन को रोकने के लिए निरंतर शुल्क लगाना अनावश्यक था;
- (छ) ताईवान के उत्पादक तीसरे देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को दिए गए आर्डरों पर माल को लगान करते हुए पाए गए हैं;
- (ज) क्षति की अवधि में विगत में निर्यातक देशों में उत्पादकों द्वारा प्राप्त क्षमता उपयोग के स्तर तथा जांच अवधि के दौरान किए गए क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने ताईवान, इंडोनेशिया और यूरोप में अप्रयुक्त क्षमताओं को निर्धारण किया था। यह नोट किया गया है कि इंडोनेशिया में उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमता 87000 मी.ट. तक थी जबकि वह यूरोपीय उत्पादकों के मामले में 236000 मी.ट. की सीमा तक थी। दूसरे शब्दों में इन देशों के उत्पादक इन सीमाओं तक सामग्री को तुरन्त प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (झ) क्लोर अलकली द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार:-

ताईवान की फलातू क्षमता	54,000
ताईवान का विस्तार नियोजित	466,666
ताईवान का कुल संभावित अधिशेष	520,666
इंडोनेशिया की अधिशेष क्षमता	327,000
यूरोप की अधिशेष क्षमता	1,886,000
कुल अधिशेष	2,733,666
भारतीय मांग	

➤ आबद्ध क्षमता को छोड़कर	18,74,596
➤ आबद्ध क्षमता सहित	21,22,251

(ट) सीएमएआई की रिपोर्ट के अनुसार इस समय विश्व में मांग व आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है :-

मांग	5,00,31,000
क्षमता	5,75,74,000
अतिशेष	7,543,000

(ठ) यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उपाय वापस लेने की स्थिति में क्षति फिर नहीं होगी। क्षमता, उत्पादन, बिक्री एवं मांग से संबंधित साक्ष्य को देखते हुए यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लेने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा फिर होगी। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से यह स्थापित हो जाता है कि उपाय वापस ले लेने की स्थिति में क्षति फिर होगी।

निष्कर्ष

90. उपर्युक्त पर विचार करते हुए और हितबद्ध पक्षों के विचार एवं प्रस्तुत जानकारी/साक्ष्य के मद्देनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि

(क) पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार प्रदर्शित हुआ है। तथापि यह किसी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंचा है। घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

(ख) यदि वर्तमान उपाय वापस ले लिए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा फिर होगी।

कारणात्मक संबंध

91. हितबद्ध पक्षों द्वारा कारणात्मक संबंधों के बारे में दी गई प्रस्तुतियों की जांच की गई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधी मुद्दों तथा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और पाटित आयातों के कारणात्मक संबंधों के बारे में विस्तृत जांच की गई। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैराग्राफ (v) में यह उल्लेख है कि:

"यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि पाटन के प्रभाव के माध्यम से, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है, पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सुसंगत साक्ष्य पर आधारित होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों से इतर ज्ञात कारणों की भी जांच की जाएगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है

और इन अन्य कारकों से हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को न बताया जाए । इस संबंध में सुसंगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा मूल्य, मांग में आई कमी अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधक पद्धतियां एवं प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में हुए विकास तथा घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन एवं उत्पादकता शामिल है ।"

अन्य ज्ञात तथ्य

92. प्राधिकारी द्वारा जांच की गई कि क्या अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा होने की संभावना है ।

अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा एवं कीमतें

विभिन्न देशों से किए गए आयातों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

एम टी	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
संबद्ध देश	5321	86783	18484	39130
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देश	29805	16304	29688	33463
पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले देश	3845	11598	22457	42637
कुल आयात	38971	114685	70629	80010
आयातों में हिस्सा				
संबद्ध देश (%)	13.65	75.67	26.17	4.89
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देश	76.48	14.22	42.03	43.45
पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले देश	9.87	10.11	31.80	55.37

93. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के अलावा अन्य अनेक देशों से भी आयात किए गए । अन्य स्रोतों से कुल आयात 2001-02 के दौरान 33650 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 76100 मी.टन हो गया । यह भी नोट किया गया कि पाटनरोधी शुल्क न लगाने वाले स्रोतों से भारित औसत आयात कीमत पाटित कीमत से अधिक है अथवा संबद्ध देशों में संभावित कीमतों से अधिक है । अतः यह नोट किया गया कि मात्रा तथा मूल्य, दोनों के रूप में अन्य स्रोतों से किए गए आयात का घरेलू उद्योग पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होगा ।

मांग में कमी एवं/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
मांग	1623806	1792411	1811779	1874596
सूचकांकित	100	110	112	115

94. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग 2001-2002 में 1623806 मी.टन से बढ़कर जांच अवधि में 1874596 मी.टन हो गई । यह नोट किया जाता है कि क्षति की सम्भावना

अवधि के दौरान मांग लगातार बढ़ती रही है। अतः मांग में संभावित कमी वह कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधक पद्धतियां एवं उनके बीच प्रतिस्पर्धा

95. संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां नहीं हैं। देश में कॉस्टिक सोडा के 37 उत्पादकों में से घरेलू उद्योग में संबद्ध वस्तु के 10 उत्पादक हैं। भारतीय उत्पादक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से प्रभावित होती हैं। घरेलू उद्योग को संभावित क्षति की वर्तमान स्थिति का कारण व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियों अथवा विदेशी व घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को नहीं माना जा सकता।

प्रौद्योगिक विकास तथा निर्यात कार्य निष्पादन

96. सहकारी विदेशी उत्पादक तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधाएं एक ही प्रौद्योगिकी पर आधारित पाई गईं। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की तीन प्रौद्योगिकियां हैं और तीनों रूपों का प्रयोग जारी है। यद्यपि अनेक कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी को मरकरी से मेम्ब्रेन में उन्नयित कर रही हैं, तथापि यह पाया गया कि परिवर्तन की यह प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है; न ही जांच से यह पाया गया कि नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले उत्पादक की पूर्ण उत्पादन लागत कम है अथवा गैर क्षति कीमत वाली है। प्रौद्योगिकी अथवा प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों को किसी भी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग को क्षति के संभावित कारण के रूप में नहीं उठाया है। यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का अल्प मात्रा में निर्यात किया है और इससे कंपनी के प्रचालन पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि घरेलू उद्योग की कुल बिक्री से तुलना की जाए तो घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन नगण्य है; अतः निर्यात कारोबार से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

97. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान श्रम उत्पादन तथा दैनिक उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादकता वृद्धि प्रदर्शित करती है। यह भी नोट किया गया है कि क्षति की समस्त अवधि में उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

98. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2002-03 में पहले गिरावट आई और फिर यह बढ़कर लगभग 2001-02 के स्तर पर पहुंच गया। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य निवल बिक्री, आय तथा घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित गैर क्षति मूल्य से बहुत कम था और इस प्रकार घरेलू बिक्री कीमतों से उल्लेखनीय रूप से कम था। यदि निर्यात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम होता है, तो मात्रा एवं/अथवा मूल्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह पाटित कीमतों पर भी पड़ेगा। यह भी नोट किया गया कि यदि निर्यात सामान्य मूल्य या इससे अधिक मूल्य पर किया जाए, तो आयातों का पहुंच

मूल्य घरेलू उद्योग के वर्तमान बिक्री मूल्य से उल्लेखनीय रूप से अधिक होगा । भारत को किया गया कोई भी निर्यात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य के निकट अथवा इससे नीचे की कीमत पर संभावित होगा, जो स्पष्टतः पाटित कीमतों पर ही होगा ।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग को संभावित क्षति पाटित आयातों के कारण होगी ।

ज. अंतिम जांच रिपोर्ट

99. हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रदत्त जानकारी तथा दी गई प्रस्तुतियों के मद्देनजर और हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुतियों द्वारा अथवा अन्यथा उपलब्ध तथ्यों एवं उपर्युक्त जांच निष्कर्षों में अभिलेखबद्ध तथ्यों और वर्तमान व संभावित पाटन की स्थिति तथा क्षति एवं पाटन व क्षति के जारी रहने तथा निरंतरता की संभावना के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

(i) संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं और ईयू (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया तथा चीन ताइपेई की संबद्ध वस्तुओं की पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और डी-मिनिमस से अधिक है । यदि वर्तमान उपाय वापस ले लिए जाएं तो संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में प्रवेश पाटित कीमतों पर संभावित है । अतः यह स्थापित नहीं होता कि शुल्क को लगातार लगाए रखना पाटन के प्रभाव को दूर करने के लिए अनावश्यक है ।

(ii) यद्यपि क्षति अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग ने कार्य निष्पादन में सुधार किया है, तथापि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है । इसके अलावा यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा निरंतर होगी । अतः यह स्थापित नहीं होता कि वर्तमान उपाय वापस ले लेने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा निरंतर होगी ।

100. यह निष्कर्ष निकालकर कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीन ताइपेई से आयातों के कारण पाटन व क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है, यदि शुल्क वापस ले लिया जाए। प्राधिकारी का यह अभिमत है कि इन देशों से आयातों के विरुद्ध उपाय जारी रखना आवश्यक है । तथापि यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीन ताइपेई से पाटन के वर्तमान स्तर तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को देखते हुए लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की आवश्यकता है । अतः प्राधिकारी इसे जरूरी मानते हैं और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) इंडोनेशिया और चीन ताइपेई से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं ।

101. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीन ताइपेई से कौस्टिक सोडा के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं । प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करते हैं जो पाटन मार्जिन के बराबर अथवा कम हो, जिसके लगाए जाने पर घरेलू उद्योग की क्षति दूर

हो । क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के दौरान निर्धारित घरेलू उद्योग के भारित औसत गैर क्षति मूल्य से की गई है ।

102. तदनुसार प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के तहत यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया तथा चीन ताइपेई के उद्गम के अथवा वहां से निर्यातित कॉस्टिक सोडा के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क निम्नानुसार लगाया जाए । पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई सारणी के कालम 9 तथा सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28 के तहत आने वाले नीचे उल्लिखित संबद्ध क्षेत्रों/देशों के उद्गम की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर प्रति मीट्रिक टन आयात के पहुंच मूल्य के अंतर के बराबर होगा :-

क्र. सं.	उप-शीर्ष	माल का वर्णन	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राश (अम. डालर)	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	281.27	डीएमटी	अम.डॉ.
2	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	इंडोनेशिया व ईयू के अतिरिक्त कोई भी देश (फ्रांस को छोड़कर)	चीनी ताइपेई	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	281.27	डीएमटी	अम.डॉ.
3	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीनी ताइपेई	इंडोनेशिया व ईयू के अतिरिक्त कोई भी देश (फ्रांस को छोड़कर)	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	281.27	डीएमटी	अम.डॉ.
4	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	256.88	डीएमटी	अम.डॉ.
5	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीनी ताइपेई व ईयू के अतिरिक्त कोई भी देश (फ्रांस को छोड़कर)	इंडोनेशिया	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	256.88	डीएमटी	अम.डॉ.
6	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	इंडोनेशिया	चीनी ताइपेई व ईयू के अतिरिक्त कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	256.88	डीएमटी	अम.डॉ.
7	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	ईयू (फ्रांस को छोड़कर)	ईयू (फ्रांस को छोड़कर)	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	295.46	डीएमटी	अम.डॉ.

8	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीनी ताइपेई व इंडोनेशिया के अतिरिक्त कोई भी देश	ई यू (फ्रांस को छोड़कर)	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	295.46	डीएमटी	अम.डॉ.
9	2815.11 तथा 2815.12	कॉस्टिक सोडा	कोई ग्रेड	ई यू (फ्रांस को छोड़कर)	चीनी ताइपेई व इंडोनेशिया के अतिरिक्त कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	295.46	डीएमटी	अम.डॉ.

103. सभी प्रयोजनों के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित निर्धारण योग्य मूल्य होगा तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9 क के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क होंगे ।

104. प्राधिकारी अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार यहां संस्तुत निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, संशोधन करने अथवा समाप्त करने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करेंगे । ऐसी समीक्षा के किसी भी अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, जब तक इसे किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत न किया जाए ।

105. इस आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथा संशोधित) के अनुसरण में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है ।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2006

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-dumping (Mid-Term Review) investigation concerning import of Caustic Soda originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU(excluding France)

No. 15/5/2005-DGAD – WHEREAS, the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after also referred to as Rules), recommended imposition of provisional anti dumping duty on imports of Caustic Soda (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and European Union (excluding France) (hereinafter referred to as subject countries). The preliminary findings were published vide Notification no. 14/39/2002-DGAD dated 8th January 2003 and provisional duties were imposed on the subject goods vide Customs Notification dated 27.03.2003. The Designated Authority notified the final findings on 01.10.2003 and definitive antidumping duty were imposed vide Customs Notification dated 14.11.2003.

2. **AND WHEREAS**, the Designated Authority, received an application from M/s. Hindustan Lever Limited, requested for a changed circumstances review since conditions of dumping and injury have changed. The Authority, on the basis of a request made on behalf of importer, issued a public notice dated 03.06.2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping mid term review investigation in respect of the duty in force against the above countries as above, to determine whether the continued imposition of duty notified vide Custom Notification dated 27.03.2003 would be necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty is removed or varied or both.

A. BACK GROUND OF THE CASE

3. On the basis of an application filed by the M/s Indian Producer through Alkali Manufacturers Association of India, the Designated Authority conducted an investigation into existence of Dumping, Injury and Causal link of imports of Caustic Soda from Chinese Taipei,

Indonesia and European Union (excluding France) and on the basis of positive determination of Dumping, Injury and Causal link, notified its final findings vide Notification No: 14/39/2002-DGAD dated 1st October 2003. Acting Upon the findings of the Authority, the Central Government imposed antidumping duty on imports of the subject goods from the subject countries vide Customs notification dated 14.11.2003. The present investigation to review the need for continued imposition of duty has been initiated on 03/06/2005 on the basis of an application filed by M/s Hindustan Lever Limited, Mumbai.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received an application from M/s. Hindustan Lever Ltd., alleging changed circumstances and requesting initiation of midterm review investigation concerning imports of Caustic Soda (hereinafter referred as subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and European Union (excluding France) (hereinafter referred to as subject countries).

ii) The information provided by the applicant showed sufficient prima facie justification that there was a need for review of anti dumping duties earlier imposed. On being satisfied, the Authority issued a public notice dated 03.06.2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping midterm review investigations concerning imports of the subject goods classified under chapter 28 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975, originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and European Union – Excluding France in order to determine whether there is no justification for continued imposition of existing duties and whether the same can be withdrawn.

iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject countries and gave them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2):

iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

v) Requests were made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) and Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata to arrange details of imports of subject goods made in India for the period of investigation and preceding three years.

vi) The Authority provided copies of the non confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassy/territory of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also provided to other interested parties, wherever requested.

vii) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject countries including known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4). One of the exporters from Chinese Taipei M/s. Formosa Plastics Corporation, Taiwan (hereinafter referred to as FPC) filed response in the prescribed exporters questionnaire within duly granted extended time period.

viii) Questionnaire was sent to the known importers/user and associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4). Following parties filed response to the questionnaire:-

a. M/s. National Aluminium Company Ltd.,

The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, and to the known representative consumer organizations, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.

ix) The Authority held a public hearing on 29th November 2005 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally, which was attended by petitioner, representatives of the domestic industry, Formosa Plastics and other interested parties. The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of views and information presented orally. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments on the views/information presented orally by other interested parties. Designated Authority has considered these written submissions received from various interested parties.

x) Arguments raised and information/evidence provided by various interested parties during the course of the investigation, to that extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in the present findings, .

xi) The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by various interested parties upon which these findings are based. For the purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the foreign producer, the domestic producers and consumers to the extent considered relevant and necessary. Additional details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.

xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xiii) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the domestic industry so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xiv) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed on 2/05/2006 to known interested parties and comments received have been duly considered in these findings;

xv) Investigation was carried out for the period starting from 1st January 2004 to 31st December 2004 (12 months) and has been referred to as the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from April 2001 - March 2002, April 2002 - March 2003 and April 2003 - March 2004 and the POI.

xvi) ****In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits. Information provided by various interested parties on confidential basis were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided, necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

B.1 VIEWS OF THE INTERESTED PARTIES:

5. Domestic industry has submitted that;

a. The present review investigation is a midterm review investigation. The product involved in the original investigation and in the present investigation is Sodium Hydroxide generally known as Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NaOH. It is an Inorganic Chemical classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odorless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. It is mainly used in the manufacture of pulp & paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet & laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs & pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms - lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form. All forms of caustic soda are the subject matter of the present petition. Issues related with product under consideration and like article were examined in detail by the Designated Authority in the original investigations and is required to be confirmed.

b. The Designated Authority has recently held that there is no necessity of reviewing the scope of product under consideration and like article in a review case. Such being the case, Indian Producers submit that the scope of the product under consideration and like article is not required to be examined at this stage. Imports of product under consideration are made both in lye and solid form. The lye form imports would normally be in shipment size of minimum 500 MT or multiple thereof. Indian Producers submit that the lye and solid differ in associated costs and

prices. Since there have been imports of both the forms of caustic soda in the investigation period, the Designated Authority may kindly ascertain normal value, export price and dumping margin accordingly.

B.2 VIEWS OF THE APPLICANT, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES:

6. The applicant, importers, consumers and other interested parties has submitted that:

a. M/s. NALCO has submitted that the Caustic Soda lye and solids/flakes are different products and cannot be treated as like product for the present investigation. They have submitted that Caustic Soda lye form is used world over in the production of alumina in the aluminum industry, thus solids/flakes is not commercially substitutable for lye Caustic Soda. The difference between lye and solids arises on account of the former having a lower concentration of Caustic Soda than the later which has a greater concentration of Caustic Soda. Therefore, it is submitted that solids/flakes and lye Caustic Soda cannot be treated as like product. Hence, Caustic Soda lye should be considered as product under consideration. Their end use is different along with the market value, handling, storage and transportation etc.

B.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

7. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda (referred to as caustic soda in the present findings) originating in or exported from Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France). The product under consideration is the same as was considered in the original investigation. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technological processes, i.e., mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics. Caustic soda is classified under chapter 28 of the customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200. The classification, is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

8. It is noted that Caustic Soda is produced and sold primarily in lye form. Since it is used in huge quantities, transportation in lye form even after paying higher transportation cost due to low concentration results in lower effective cost to the consumer, whereas conversion of flake leads to additional cost to the user. Caustic Soda solid form can be used for similar functions & uses wherever lye form is required. It is noted that the difference in prices is due to the differences in concentration, cost of transportation, and incremental conversion cost required for solid form. The differences in caustic soda in two different forms do not render these a different product, the product continues to be essentially caustic soda, with the same product characteristics. However, in view of differences in prices, for the purpose of comparison of normal value with export price

and landed price of imports with non injurious price, the Authority has considered the difference in physical forms and have compared the two forms separately. Separate normal values and non-injurious prices have been determined for determining dumping margin and injury margin for lye and solid form. However, keeping in view the Rules, the Designated Authority has relied upon weighted averages of dumping margin and injury margin, after ensuring fair comparison.

9. In order to determine whether goods produced by the domestic industry can be considered like article to the goods produced and/or exported from the subject countries, the Authority considered various relevant parameters such as physical & technical characteristics, production technology, manufacturing process, functions & uses, pricing, customer perception, etc. The goods manufactured by domestic industry are like article to the goods produced and/or exported from the subject countries. Both are technically and commercially substitutable and the consumers are using and can use the domestically produced and imported goods interchangeably. Considering the submissions made by various interested parties and keeping in view the essential product characteristics, substitutability and interchangeability of the goods exported from subject countries by goods produced by the domestic industry, the Authority holds that subject goods produced by the domestic industry are like articles, as per Rule 2(d) of rules Supra, to the product under consideration. It is further noted that the Hon'ble CESTAT has upheld the determination of the Authority with regard to like article and the interested parties in the present investigations have brought no new facts/evidence in this regard.

C. DOMESTIC INDUSTRY:

C.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY:

10. The domestic industry has submitted that;

a. The present submissions are being filed by and on behalf of Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI). All Producers of Caustic Soda in India are members of AMAI. A number of manufacturers of subject goods in India have provided information relevant to injury, including costing information. There is no legal and factual basis for the argument that the composition of domestic industry should remain the same as it was in the original investigations and all subsequent investigations.

C.2 VIEWS OF THE APPLICANT, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES:

11. The interested parties have submitted that the composition of the domestic industry has changed in this sunset review without any legal or factual reasons for such change. Thus, participating companies are posing as domestic industry when the majority of them are incapable of filing injury information.

C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

12. As per Rule 2(b) of the AD Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in manufacture of like article and any activity connected therewith or those

whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry.”

13. The Authority notes that the following domestic producers has provided sufficient information relevant to determination of injury (and extent thereof) to the domestic industry,

- a. M/s. Bihar Caustics & Chemicals Ltd.,
- b. M/s. DCW
- c. M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., (Baroda and Dahej)
- d. M/s. Indian Petrochemical Corporation Ltd.,
- e. M/s. Jayshree Chemicals Ltd.,
- f. M/s. Punjab Alkalies & Chemicals Ltd.,
- g. M/s. Shriram Alkalies & Chemicals,
- h. M/s. Standard Alkalies
- i. M/s. SIEL Chemical Complex,
- j. M/s. Solaris Chemtech Ltd.,

14. The total production of the industry was 1794587 during the POI and the production of the participating producers was 911244 MT during the period of investigation in this MTR. The production of the participating companies thus constitutes more than 50% of the production by the Indian industries. The Authority, therefore, holds that these companies constitute domestic industry within the meaning of the Rules. During the course of the investigations and in comments to the disclosure statement, interested parties have argued that the composition of the domestic industry has been changed in the present mid-term review investigation without giving any legal or factual reasons for effecting such a change. The Authority notes that no legal and factual basis has been provided by these interested parties why constitution/scope of the domestic industry in a review investigation would remain the same as the original investigations. It is also noted that there is no legal requirement that the scope and constitution of the domestic industry in MTR investigation and in the original investigations should be the same.

D. OTHER ISSUES

D.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY:

15. The domestic industry has submitted that

- a) The Designated Authority should consider relevant provisions of the Cost Accounting Records Rules as well as the earlier determination of the Designated Authority while coming to a conclusion whether chlorine is a joint product or by-product of caustic soda.
- b) In the present midterm review investigation the economic condition of the domestic industry has shown positive trend in most of its economic parameters in the period of review.

- c) The claim that the duty should be terminated if the industry has experienced improvement cannot be regarded as reconciling with purpose behind midterm reviews as contemplated in Article 11.3 of the ADA and Section 9A(5) and Rule 23 of the Indian Anti dumping Laws.
- d) The purpose for initiating a midterm review is to examine whether dumping and injury is likely to continue or recur if the duty is removed or varied.
- e) The domestic industry has provided information relating to dumping and injury in the prescribed formats. Analysis of different parameters relating to injury to the domestic industry establish that domestic industry was yet to achieve financial stability and reasonable returns considering huge investments made in Caustic Soda Industry.
- f) The anti-dumping duties in force on subject countries should not be revoked since likelihood of continuation or recurrence of the dumping and injury to the domestic industry if anti dumping duty is revoked.
- g) Severe imports of Caustic Soda from various sources continue for the last several years and this establishes that anti-dumping duties in force were never against imports per se but to restrict dumped imports. India is not the only country who has imposed ADD on dumped imports of Caustic Soda.
- h) Worldwide production capacity of caustic soda in 2004 was assessed as 65.41 Million MT whereas the world demand of caustic soda was only 52.8 Million MT. Thus, there existed a surplus of 12.52 Million MT which amounts to nearly around 20% of capacity. The producers in subject countries are having significant surplus production capacity, whereas demands of product in their respective countries are significantly lower.
- i) Likelihood of recurrence of dumping is established from the fact that exports from one of the subject countries stopped after imposition of anti dumping. Producers in subject countries have built capacities far in excess of their domestic demand and the same have been created considering export markets.
- j) The price at which the product is being sold in the Indian Market is higher than price at which material is being exported to other countries. Prices prevailing in the Indian market are higher than some of the other markets where the Foreign Producers are selling significant volumes.
- k) Causal link has no relevance in a review investigation and not required to be examined, as held by the WTO. Nevertheless, the information clearly shows that revocation of anti dumping duties is likely to lead to continuance or recurrence of injury.
- l) HLL has full information with regard to the volume and price at which the company has purchased material from the Indian Producers, why did company suppress the information and resorted to prices mentioned in the AMAI bulletin

- m) If industrial users were to be recognized as and included in the definition of interested party, there would not have been the necessity of a separate provision defining industrial user.
- n) Domestic industry has never said that HLL can not participate in the investigation, however, participating in an investigation and making petition for review investigation by a industrial users are two different issues.
- o) Costing information being confidential in nature cannot be filed on non-confidential basis. The product under consideration is caustic soda and not chlorine and therefore neither the Indian Producers nor the Designated Authority has any obligation to disclose basis of apportionment of expenses between caustic and chlorine. Costing information of domestic industry contains business sensitive information not amenable of summarization and, therefore, has not been provided alongwith the non-confidential version.
- p) Caustic soda lye and solids are like articles. Injury analysis is required to be done for "like product" and not separately for each form of the product.
- q) Indian Producers are not the petitioners before the Designated Authority. Indian Producers have not sought the present mid term review of anti dumping duties in force. The principle laid down in legal procedures is that one who asserts has to establish his assertion. Indian Producers have referred to published information provided by Chlor Alkali. The company is required to establish based on their data that their exports are not at dumping prices (whether made to India or third countries) and dumping is unlikely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

D.2 VIEWS OF THE APPLICANT, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

16. The applicant, importer and other interested parties have submitted that

- a) The production of Caustic Soda results in an Electro Chemical Unit (ECU) which comprises of two products of equal economic importance, namely caustic soda and chlorine. While determining the cost of production, for the purpose of injury determination, the Authority should apportion cost between the two at the point of split on a reasonable and equitable basis. The Hon'ble Authority has already determined in the past in the case of imports of caustic soda from Korea and China that net sales realization based method is not appropriate for such cases and a volume based apportionment should be resorted to.
- b) The international price of Liquid Caustic Soda as derived from Chlor-Alkali Report shows wide upward variation to the extent of 200% increase in the period of investigation. In addition to this the Chlorine price under the spot market was showing over 100% increase in prices.
- c) The ECU realization in the market has drastically gone up over the period of investigation to the extent of 100% - 200%. The Hon'ble Authority has fixed the ROCE without proper application of mind and the determination of the ROCE has no factual basis. ROCE is

keeping in view the Drug Price Control Order (DPCO), but the DPCO has no application to the facts of the present industry and is unsustainable in law and on facts.

d) The imposition of the anti dumping duty on the import of caustic soda, which is the main raw material in the production of alumina, is making NALCO incompetent in the global market. The EC has held in certain large electronic aluminum capacitors from Japan and DRAMS from Korea that the interests of the down stream industry due to anti dumping duty are an important element to be considered. In the past among the Indian Producers who are supporting the present petition, only two producers have offered or supplied against NALCO's requirement. Majority of the domestic industry has not participated in the tenders of NALCO due to cost logistics arising from their geographical location.

e) The non-confidential version of the initiation petition shows that the domestic industry is experiencing historic profits, despite the reduction in customs duty to 20%. The Annual Reports of the AMAI reflects that the domestic industry is not suffering any effective injury due to the alleged imports of caustic soda. Production of caustic soda consumes large amounts of electricity and AMAI in annual report admitted that in India the high cost of power as compared to other parts of the world.

f) NALCO only procured the Lye Caustic Soda under the tender, therefore, the consideration of the solid forms of caustic soda has the effect of distorting the determination for the issue of like product. Liquid form of caustic soda has lesser concentration than the solid form, which results in different end uses and market perception and the marketing patterns. The imports of caustic soda into India comprise around 85% of liquid caustic including the caustic soda imported by NALCO.

g) Hindustan Lever has cited a number of investigations by the EC and the Designated Authority in order to establish that Hindustan Lever is an interested party and the present investigations were rightly initiated. Interested parties clearly have a right to furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causal link. Indian Producers have not given any materials supporting its arguments that the interested parties has no right to furnish information which is relevant to the investigation.

h) Applicant has furnished positive information and thereafter onus shifts to the domestic industry to provide information. It is further stated that no record of the Indian Producers is available in the Public Folder except an unsigned and undated submission. The non-confidential of the costing information is yet to be filed and to be made available in the Public file. Thus, claim of performance improvement is insufficient and is to be provided by the Indian Producers.

i) For import data reliance has been placed upon the data of the DGCI&S, IBIS and the import invoices. The claim of the Indian Producers that the Indonesian prices reported in DGCI&S are correct needs to be verified by sourcing the transaction wise data from the Authorities. Petitioner has relied upon the monthly news published by AMAI to ascertain the selling prices of the Domestic industry in India. Monthly news bulletin published by AMAI is an authentic document of Indian industry.

j) The domestic industry has kept the treatment of chlorine as confidential. Costing information in the indexed form has not been provided to the exporter to determine the basis of NIP. Also the treatment of the by-product chlorine is not assessed. Worldwide caustic soda and chlorine are treated as co-products. The costing/pricing of caustic soda and chlorine are intimately linked and measured in the concept of an ECU. Only one case of the Mexican industry ADD on Caustic Soda in 1995 exists. The claim that there have been duties on the subject goods against 11 countries raises a question as to why India is singled out for dumping by the global manufacturers.

k) The Taipei Economic and Cultural Center has argued that non injurious price for the domestic industry has been determined by adding a reasonable profit margin on the capital employed at the rate of 22% returned on capital employed which is very high as suggested by the alkali industry of Chinese Taipei. It is also argued that the profit margin for the non-injurious price in the original investigation was 16% which was itself unreasonable for this kind of industry.

l) They have recalled that this case is covered by consultation held under the WTO framework and the conclusion of the dispute settlement is entirely depends on the outcome of this review. It has been suggested to reconsider the findings of the review with a view to find a mutually satisfactorily resolution to the anti dumping case as well as the pending disputes settlement.

m) Ministry of Trade, Republic of Indonesia has submitted M/s. P.T. Kiani Kertas, M/s. P.T. Musi Pulp Mills and M/s. Asahimas Subentra Chemical did not produce and export to India. They have further stated that the imports from Indonesia has declined during the POI whereas the imports other sources has increased during the same period. In view of the examination of injury parameters in the disclosure statement, the Indonesian Government submits that most of the parameters are showing negative trend except return on investment and employment. They have requested to terminate the investigation and exclude the above mentioned exporters/producers in view of no exports.

n) The exporter has submitted that the domestic industry did not disclose the treatment of Chlorine and fell to provide a non-confidential version of the costing information with index data. In absence of the information we are not in a position to file comments on the determination of non-injurious price determined for the domestic industry.

o) The exporter has submitted that world wide the caustic soda manufacturers treat caustic soda and chlorine as co-products. It is a matter of chemical reaction which necessarily produce caustic soda and chlorine and the costing/pricing of caustic soda and chlorine intimately linked and measured in the concept of ECU.

p) The exporter has submitted that 22% of return on capital employed based on the determination made under Drug Price Control Order (DPCO) is not relevant to the present industry and at the same time it is very high. The determination of ROCE will have a material bearing on the finding of injury to the domestic industry, therefore, the ROCE may be recalculated for this industry and accordingly injury parameters may be assessed.

q) M/s. P. I. Asahimas Chemical has submitted that they have not exported liquid caustic soda to India since 2003, therefore they may be exempted for filing the exporters questionnaire and duty did not be imposed on them.

r) ICMA (Indian Chemical Manufacturing Association) has submitted that the prices of caustic soda has gone up by 60% between January to June 2005, therefore, the period of investigation the purpose of review should be considered as May 2004 to June 2005. They have also submitted that the current benchmark of US\$ 258.46 to US\$ 271.46 DMT is redundant as the current import price is between the range US\$ 325 to US\$ 375/DMT, therefore there is no need to continue with AD duty. It is state that caustic soda is an important commodity both from its wide spread use and capital intense in nature and looking at the profit margin of industry, the Authority may look into the concern of user industry.

s) M/s. Supreme Paper Mills Ltd., has submitted that due to the protection of anti dumping duty to the domestic industry prices of caustic soda has been increased from 14000 to 26000, which has resulted into suspension of production by many agro based paper mills.

D.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

17. It was argued by the interested party that Chlorine should be treated as joint product in the production of Caustic Soda since the majority of the producers worldwide treats Chlorine as a joint product in Chlor industry. The Authority examined the arguments raised by the interested party keeping in view the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Cost Accounting Record Rules (as amended from time to time and as applicable during the investigation period) and Annexure I to AD Rules and WTO Agreement on Anti Dumping requiring determination of costs on the basis of records kept by the company under investigation provided such records are in accordance with the GAAP and such records reasonably reflect the cost associated with the production and sales of the product under consideration. The Authority also considered the available evidence on proper allocation of costs, which was made available by the participating domestic and foreign producers. The Authority notes that the decision whether to treat chlorine as a co-product or a by-product can not be universal decision, applicable and relevant for all times. It is a determination to be made by the Authority in every case, keeping in mind facts and circumstances of that particular case. It is noted that it would not be appropriate to consider Chlorine either as a joint product or a by-product in respect of the entire Chlor Alkali industry, it would be rather reasonable and appropriate to determine the cost of production of caustic soda after adopting the treatment of Chlorine as adopted by the company and cost auditors concerned in its accounting books, including cost records. The Authority considers it appropriate to accept and adopt the basis adopted by the companies in their records, duly verified/certified by the cost auditors. In this mid-term review investigation the Authority has considered and treated Chlorine in respect of domestic industry accordingly. It is also noted that there is no adverse qualification by the cost auditors against the treatment accorded by the companies concerned.

18. The actual cost of production of the subject goods has been determined taking into account the optimum cost of production on the basis of GAAP as per the consistent approach followed by the Designated Authority. The non injurious price for the domestic industry has

been determined after taking into account all the relevant factors including cost of raw materials used in the production of the subject goods, the consumption thereof, the cost of utilities i.e., power, steam, water etc., interest cost, cost of labour, depreciation cost and selling, general and administrative (SGA) expenses. The factors such as investments and the capacity utilization have also been examined in the cost analysis. All these factors have been considered with reference to the basic books of accounts and production and financial statements of the participating companies to determine the cost of production. Non injurious price for the domestic industry has been determined by adding a reasonable profit margin @22% return on the capital employed, on the cost of production (capital employed is determined as the sum of net fixed assets and working capital for the product under consideration). Return is defined as interest plus profit, i.e., interest expense in the cost of production has been deducted to determine reasonable profit. On comments to the disclosure statement, the exporter and Taipei Culture Centre has argued that 22% return on capital employed is unreasonable to this industry, has a bearing on the injury to the domestic industry and the Authority had allowed only 16% return in the original or earlier investigations. On examination of this issue, it is noted that the Authority had considered the same rate of return in the previous investigations relating to this product. It is also noted that 22% return on capital employed is not the profit element rather it is determined after deducting interest from the return so determined and the Authority has applied lesser duty law and in any case, the resultant duties have not exceeded dumping margins determined.

19. The interested parties have argued that caustic soda lye and flakes are not like article to the product under consideration, since these two are used for different end applications by the user industry. The argument of the interested party was examined, keeping in view the scope of the product under consideration and definition of like article. Product under consideration includes both caustic soda lye and solid forms. It is noted that the solid forms can be in the form of lumps, prills, chips, flakes etc. It is further noted that both the forms of caustic soda are one product and are similar in terms of essential product properties, function and uses, production technology and process, plant and equipment, pricing. The difference in pricing is only due to, as stated before, incremental production process and differences in transportation costs. The Authority agrees with the argument made by the interested parties that some consumers may be using caustic soda only in lye form because of their convenience and technology adopted by them, but the Authority holds that this does not mean that the product in different form becomes different product and loses its essential features, functions & uses, nor does this mean that other forms cannot be used for similar functions. This has been well demonstrated during the verification visits to various producers. The product remains essentially the same regardless of specific end applications. However, given differences in the resultant prices, price parameters have been considered separately for lye and flakes for the purpose of determination of dumping margin; price undercutting, price underselling, price suppression, and price depression and injury margin.

20. The interested parties have argued that ECU realization may be considered for the purpose of allocation. It is noted that the present findings are based on actual ECU realization of the domestic industry, in as much as realization from chlorine has been either reduced from the cost of production or chlorine treated co-product and cost of production determined accordingly and therefore, the concern of the interested parties have been addressed. It is noted that if a

company has treated chlorine as a by-product and if chlorine realization has been higher during the relevant period, higher deduction on this account has been made.

Domestic industry vehemently disputed the right of Hindustan Lever as an interested party. It is noted that the definition of interested parties is an inclusive definition and the Authority has a right to consider any party as an interested party. The Designated Authority has considered Hindustan Lever as an interested party and has considered it appropriate to proceed with the application and the present investigations. Hindustan Lever has been allowed them to provide information relevant to the present investigations and make submissions as an interested party.

NALCO has repeatedly argued that their interests as consumers should not be ignored and referred to some decisions of the EC also in this regard. It is clarified that right of NALCO as a large consumers of the subject goods have been well recognized in the present proceedings and the company has been provided full opportunities to provide relevant information and make submissions. Submissions made by NALCO have been duly considered in these findings.

Some of the exporters/producers have submitted that they have not exported during the POI, it is noted that they may apply for new shipper review under Rule 22 of AD Rules.

21. It is argued by the interested parties that the vital information has been kept confidential depriving the opposing interested parties of the right to challenge the information and make meaningful submissions to the Authority. The Authority notes that Rule 7 of the AD Rules provides for submission of information by the interested parties on confidential basis subject to the condition laid down therein. The Rules provide that certain information which are either business proprietary information or any other information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. The Rules further provide that such information shall not be disclosed to other interested parties without specific permission of the party submitting it. In this review investigation certain business sensitive information has been kept as confidential, which includes information pertaining to costing and prices of the subject goods and other sensitive information, disclosure of which would be of significant competitive advantage to a competitor and would adversely affect the business interests of the company. The information claimed confidential by the interested parties was examined as per confidentiality provision under AD Rules and such information was considered confidential by the Authority on being satisfied that the information claimed confidential is indeed confidential. The non-confidential summary of the information submitted on a confidential basis was placed in the public file, which was made available for the inspection, by all the interested parties in terms of Rule 6 (7) of the AD Rules.

E. DUMPING & DUMPING MARGIN:**E.1. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY:**

22. The domestic industry has submitted that dumping is taking place from all the subject countries during the period of investigation. However it is noted that imports from Taiwan has ceased during the POI due to the anti dumping duty in place therefore, likelihood of recurrence of dumping is established from the fact that exports from one of the subject countries stopped after imposition of anti dumping. Producers in subject countries have built capacities far in excess of their domestic demand and the same have been created considering export markets. Further the current dumping in case of Taiwan may also be examined in view of prices available of Taiwanese exports to other markets.

E.2 VIEWS OF THE EXPORTER:

23. The Exporter has submitted that most of the export sales, mainly to Australia and the USA, long term contracts have been formalized. With the long term contracts these customers are committed to purchase a significant quantity every year. Due to such contractual obligation the prices for these customers have been separately fixed from the price prevailing in the spot market, which have been determined as per the demand and supply situation prevailing in the market. They have further submitted that the sales in the domestic market are made on a spot price basis therefore it is incomparable to the export sales prices to the third countries other than India during the period of investigation. The exporter has suggested to consider spot prices of South East Asia for the purpose of looking into the phenomena of dumping and likelihood examination of recurrence of dumping and injury to the domestic industry. They have further suggested the quantity discounts and the level of trade based on the constructed export price from FPC to India. In the comments to the disclosure statement Taipei Economic and Cultural Center, New Delhi has submitted that recurrence of injury in case of revocation of duty is groundless. They have stated that there were no exports during the period of investigation i.e., 1st January 2002 to 30th September 2002 of the original investigation and again there is no exports during the period of investigation of this mid term review investigation. In view of this there was no injury either in the original investigation nor any injury is likely to recur in this mid term review investigation in case of revocation of duty. The Authority has constructed the export price on a reasonable basis as per Section 9A (b) as being the price at which the exporters sell to third countries other than Taiwan.

24. They have submitted that the Authority should have considered the spot market price to India as per CMAI journal provided by FPC instead of considering actual price based on long term contracts to Australia, USA and Singapore. They have also stated that the weighted average normal value at ex-factory level should have been US\$ 207/DMT instead of US\$ 231/DMT as per the domestic selling price of the unaffiliated parties. It has been suggested by

the exporter to consider the price reported in the CMAI journal instead of actual verified prices of the exporter for the determination of dumping margin. The Authority has erred in making a determination on dumping margin when there is no exports of subject goods during the POI. The level of trade which has been considered by the Authority is inadequate, therefore adjustments with regard to level of trade should have been given due to difference in long term prices and spot prices.

E.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

25. In anti-dumping investigations, normal value shall be determined in accordance with the Rules which provides that : -

“normal value”, in relation to an article, means-

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

CHINESE TAIPEI:

26. The Authority sent copies of the exporter questionnaire to all the known producer/exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A (1)(c). M/s. Formosa Plastics Corporation has submitted its response to the exporters' questionnaire. They have not exported the subject goods to India during the period of investigation and the same has been verified from the DGCI&S import statistics. Thus, in the absence of export price, no current dumping margin can be determined. In comments to the disclosure statement, TECC has submitted that there were no exports during the period of investigation of neither the original investigation nor any exports during the period of

investigation of this mid term review. While the fact of exports in the previous investigations is not relevant to the present investigations, it is clarified that there was exports during the period of investigation of the original investigation, which formed the basis of determination in that investigation, and this issue was addressed in the original investigation itself. As regards the present investigation, the Authority has proceeded in accordance with A D Rules and WTO Agreement on Anti Dumping.

27. Under Rule 23 of AD Rules, the purpose of review is to determine the need for continued imposition of the duty and investigate whether there is sufficient justification for withdrawal of duty. Since there were no imports of subject goods from Chinese Taipei during the period of investigation, it is pertinent to determine whether this is a sufficient justification for withdrawal of anti dumping duty. Since the Authority is required to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, it is required to be determined whether the fact of no exports is sufficient to hold that continued imposition of the duty is unnecessary to offset dumping. The Authority is required to determine, in a situation of no current dumping, likelihood of dumping with the withdrawal of duty and in this regard, the normal value of the exporter and current pricing of the exporter in respect of third country are relevant, the Authority, therefore, examined whether or not the subject goods were sold to third countries at dumped prices. It has been assessed whether, should the measures be revoked, the Taiwanese exporters are likely to resume dumping in the Indian market, following the same pricing behavior. It was further assessed, should the exporter resume exports to India, whether the same are likely to be dumped. It is also recalled that in the original investigation, the individual dumping margin was significant.

DUMPING MARGIN ON THE BASIS OF EXPORTS TO THIRD COUNTRIES

28. FPC had sold the subject goods to both affiliated and unaffiliated companies in home market and exported to a number of countries other than India during the period of investigation. Comparison of sales volumes and average prices to these segments shows as under:-

Indexed information as per the response of FPC:

	Affiliated home market		Unaffiliated home market		Exports to third countries	
	Volume	Rate	Volume	Rate	Volume	Rate
Jan-04	100.00	100.00	198.91	104.71	205.09	62.54
Feb-04	100.00	100.00	125.29	108.78	78.24	60.81
Mar-04	100.00	100.00	137.44	112.61	277.42	74.66
Apr-04	100.00	100.00	137.40	110.40	80.46	66.12
May-04	100.00	100.00	137.27	109.44	373.00	68.82
Jun-04	100.00	100.00	130.98	110.19	199.16	65.76
Jul-04	100.00	100.00	121.95	107.33	69.43	68.44
Aug-04	100.00	100.00	116.74	106.80	193.55	62.72

Sep-04	100.00	100.00	117.23	107.57	98.65	67.20
Oct-04	100.00	100.00	148.39	110.29	174.18	76.09
Nov-04	100.00	100.00	130.81	108.23	32.68	84.26
Dec-04	100.00	100.00	70.11	121.39	147.13	77.38
POI	100.00	100.00	124.42	109.32	156.62	67.61

29. The exporter has significant export sales to countries other than India. They have claimed that such export sales are made under long-term contracts and the sales volume is significantly higher compared to volumes sold in the domestic market and, therefore, there is differential in prices of export sales. The exporter has also claimed an allowance while comparing the domestic price with the export price. It is noted that the exporter has significant domestic sales to its own affiliate. The volume of goods sold to its affiliate is comparable to the volumes involved in the export sales. It is, however, found that the export price to the third countries is much lower as compared to the price to its affiliated companies. On examination of domestic sales made to unrelated customers in the home market, it was found that the price could be higher in case of higher volumes and lower in case of lower volumes. The sales of the exporter were analyzed and a comparison was made on average basis for the investigation period and thereafter on month-to-month basis during the investigation period. However, no consistent pattern could be established which would have ascertained that the prices in the home market varied with the export prices with the sole difference in volumes, as claimed by the exporter. It is thus noted that the claim of price adjustment can not be considered and allowed while comparing normal value with export price on the basis of such parameters, since it could not be established by the exporter that the prices of the exporter in two different markets varied with the sole difference in volumes.

30. The exporter has provided copies of Chlor Alkali Market Report of 2004 issued by CMAI for each month of POI. They have claimed that spot price of the subject goods were US\$214–DMT for South East Asia as per this report. The same report shows annual spot price for Taiwan as US\$ 179- DMT based on simple average. The domestic industry has provided month wise price summary of the subject goods for the POI as published by M/s. Harriman Chemsult Limited (named Chlor Alkali). In this publication, prevalent prices in Asian Countries (far east) and specifically in Taiwan are available. As per this report, the average domestic price in Taiwan is US\$ 207 per DMT, whereas simple average prices in Far East comes to US\$ 197 per DMT. The exporter has requested to consider these sources prices for the purpose of determination of normal value. The exporter claimed that it was selling to third countries under long-term contracts. It was however found that the entire export sales were not under long term contracts. There were significant sales for which no claim of contract sales was made. In any case, the argument of the exporter itself, even if accepted, that the prices varied with volumes, implies that the difference in the contract price and other price was at best to the extent of the price adjustment claimed. It has been argued that the average purchased quantity per each purchase order from domestic customer during the period of investigation was 183 MT approx. whereas the average purchase quantity per each order from exports customers (of third countries) during the POI was 6429 DMT or 35 times more than the domestic order quantity. Accordingly for a similar magnitude of difference between and average domestic sales volume and average export

sales volume, a factor of US\$ 35 per DMT may be considered to the domestic price when comparing with the constrictive export price.

31. The claim of the exporter that the normal value should be determined based on CMAI is required to be rejected in view of the Section 9A(1)c and the AD Rules, which provides for the methodology for determination of normal value. In a situation where the exporter has significant viable representative domestic sales, normal value has been determined on the basis of domestic selling price and CMAI or Chlor Alkali prices can not get precedence. The Authority has examined the argument of providing an allowance on the basis of a differential of a similar magnitude of difference between average domestic quantity and average export quantity. It is seen that the exporter has sold the subject goods at much higher price in the domestic market in comparison to the sales based on long term contract in countries other than India. Even after granting an allowance of US\$ 35 per DMT from the weighted average domestic price, the export price to third Countries, namely Australia, USA and Singapore were found to be significantly below the normal value.

32. The exporter has provided the domestic sales transactions in Appendix 1 of the exporter questionnaire response. The sample invoices of the domestic sales were verified and copies of the same were obtained during verification. The domestic sales were made both to the affiliated and non affiliated parties during the period of investigation, which has been segregated for the purpose of determination of normal value. Only sales to unaffiliated companies have been relied for determination of normal value. The exporter has provided details of its cost of production for the subject goods as per Appendix 8 and same were verified. The exporter has reduced the realization on account of Chlorine from the cost per MT of Caustic Soda, which has been accepted, as the same was claimed to be on the basis of records maintained by the company. The financial expenses have not been apportioned on specific product on turnover basis, for which the exporter has gave clarifications. It is seen that even after allocating the similar cost per unit on account of financial expenses as allocated during the previous accounting year and allowing a reasonable profit margin, the weighted average domestic selling prices to unaffiliated parties is in the ordinary course of trade after conducting the 80/20 test and all the profitable transaction were considered for the purpose of determination of normal value. It was first determined whether the form of the goods sold in the domestic market and export market was similar. It was found that both domestic and export sales considered involved sales of caustic soda in lye form only. It was then determined whether the total volume of domestic sales of subject goods was representative in relation to the export sales. It was found that the volume of the subject goods sold in the domestic market was much higher than the volume exported to third countries. Sales in the home market were therefore considered representative. It was then determined whether the domestic sales were in the ordinary course of trade. It was found that all the domestic sales were made above cost of production and therefore all sales to unrelated customers in home market were considered as sales in the ordinary course of trade. Therefore, normal value was assessed on the basis of prices actually paid or payable for all sales of the subject goods, whether or not profitable. In view of the above, the normal value for the exporter has been determined based on all domestic sales to unrelated customers in the home market. The Authority verified the expenses and allowed the same, as claimed. The normal value is thus determined at ex-factory level.

EXPORT PRICE

33. The exporter has provided details regarding exports to all third countries and sales to Australia, USA and Singapore constitute the major volume of their exports. The Authority considers that the exporter has provided adequate details with regard to exports to third countries. The Authority considered it appropriate to consider all exports sales made by the exporter to the third countries and determined weighted average export price at ex-factory level. The price adjustments claimed were verified and allowed to arrive at ex-factory level. In order to compare the normal value with the export price, the Authority considered various arguments of the exporter. The exporter primarily argued that the normal value was not comparable with the export price for the reasons that the exports were under long term contract and the sales volume involved in exports were significantly higher than the domestic sales. The Authority notes in this regard that the fact that exports were made under long term contract is irrelevant to determination of export price. The fact that the prices varied with volume is a matter of fact, for which the exporter could have claimed a price adjustment, after establishing the same. However, as noted above, the exporter has not been able to demonstrate that its prices varied with volumes in the home market. Indeed it was found that the prices could have been lower for lower volumes and higher for higher volumes. Even after granting an allowance of US\$ 35 per DMT from the weighted average domestic price, the export price to third Countries, namely Australia, USA and Singapore were found to be significantly below the normal value. On comments to the disclosure statement the exporter has argued that the Authority should have considered the spot market price in Taiwan as per CMAI journal instead of considering actual domestic selling price in their home market. It was found appropriate to reject the claim of the exporter and determine the normal value as per AD Rules and WTO Agreement on Anti Dumping.

34. Normal value determined for the exporter was compared with the export price on a weighted average to weighted average basis and it was found that the dumping margin was significant. Weighted average dumping margin was determined, considering the volume of exports to third countries, which has been adopted for the purpose of the determination whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping. It was concluded, on the basis of significant dumping margin in respect of exports to third countries that continued imposition of the duty is necessary to offset likelihood of dumping with the withdrawal of the measures. In order to further establish whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority compared the normal value determined for the exporter whether the exports to India below the normal value and below the measures being recommended are likely to cause injury to the domestic industry. The Authority considered, that whether exports to India are likely to be made below the normal value and therefore, are likely to result in dumping and injury. The DA also considered whether such exports to India likely to be below the revised non-injurious price for the domestic industry and therefore, likely to cause injury to the domestic industry. In order to be competitive in Indian market, the exporters from Taiwan would have to match the prices of domestic industry which is already below the non-injurious price determined for the domestic industry. During the course of investigation it is found that the exporter from Taiwan would have to export at price much below the normal value established by the Authority for FPC. Accordingly, it is noted that the FPC would have to compete with the Indian producers thus, substantiating the likelihood of recurrence of dumping in the event of removal of measures already in force.

35. The domestic industry has submitted that FPC was undertaking significant expansion to the tune of 4,66,000 MT (evidenced from the website of FPC). It is noted that even though the exporter claimed that the expansion was being undertaken to cater to third country market, no evidence was provided to the Authority that entire volumes of this expansion was committed to third countries buyers and significant surplus capacity was not available. The investigation established that FPC has capacity to produce significant additional volumes for exports to India and these additional volumes could well reach significant levels or beyond the levels found during the period of original investigation. Should the landed price of these exports be below the benchmark being recommended, these would be exports made at dumped prices. Considering the prices at which the exports have been made to third countries, these exports would in any case are likely to be at dumping prices. Should the exports be made prices close to or less than the selling prices of the domestic industry, it is evident that the exports would be at dumping prices, if the landed price of such imports is less than the benchmark being recommended. The Indian market would be more attractive for the Taiwanese producers than the third country markets give huge and expanding demand and geographical proximity. As a matter of fact the investigation has shown that (a) the caustic soda prices in Australia, Singapore and USA were much lower than the prices in the Indian market, and in the past, the exporter committed as high as 150,000 MT material to various traders for eventual supplies to Indian customers and was in fact awarded an order for supply of 86,000 MT material for shipments in less than a year. Finally the exporter supplied 13500 MT to NALCO against an order placed on a third country trader for shipments to be made by a producer in another third country and there are number of other producers in Taiwan preferred non cooperation.

36. On the basis of evidence on record it is noted that the Taiwanese exporting producers or other interested parties could not to demonstrate that the continued imposition of the duty is unnecessary. On the contrary, the investigation has revealed that continued imposition of duty is necessary to off-set dumping. It is also noted that none of the other producers/exporters responded in this investigation. The information provided by the FPC suggests that the surplus capacities with the Taiwanese producers are significantly higher than the apparent consumption. It is also seen that the export price from Taiwan to other countries is also significantly lower than the normal value as per the trade journal and the normal value established for the sole responding exporter. This data also shows that continued imposition of duty is necessary to off-set likely dumping by other producers in Taiwan. Since none of the other exporters/producers cooperated in this mid-term review investigation and likely dumping has been established based on the information filed by FPC, contributing 90% production and sales of the subject goods during the POI, it is proposed to continue with the same dumping margin for all the exporters/producers from Chinese Taipei.

INDONESIA

NORMAL VALUE

37. The Authority sent questionnaires to all known exporters/producers for the purpose of determination of dumping margin. None of the exporters / producers from Indonesia filed submissions and response to the questionnaire in the form and manner prescribed. Article 6.8 of

the Agreement provides that in cases an interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary or final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Since none of the exporters / producers from Indonesia has filed the submissions for determination of normal value, the normal value for all exporters / producers has been constructed based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules. The domestic industry has submitted that it made best efforts to procure evidence of the domestic prices prevailing in Indonesia but could not procure actual transaction prices for the period of investigation. Since actual transaction information is unavailable, the domestic industry submitted that information provided by Chlor Alkali price can be considered as a reasonable and sufficient basis for determination of normal value with appropriate adjustments. Investigations in respect of Taiwan revealed that the prices published in Chlor Alkali are quite close to the actual transaction prices. In fact, investigation relating to Taiwan has shown that the prices reported in Chlor Alkali were slightly lower than the actual prices claimed by FPC thus, the Authority considers that the prices reported in Chlor Alkali are quite representative and reasonable evidence of normal value of the subject goods in Indonesia. The normal value is therefore is determined on the basis of prices published in Chlor Alkali. The prices were considered as delivered prices and an adjustment for possible inland freight made to determine the normal value at ex-factory level. The normal value is accordingly determined as US\$****/MT. for all exporters / producers from Indonesia.

EXPORT PRICE:

38. The export price is determined on the basis of transaction wise import statistics provided by DGCI&S containing bill of entry no., date, country code, quantity, value, description of the product and name of the importer etc. On examination of import data, it was found that the transaction wise data provided by the DGCI&S were having data pertaining to other products also. Therefore, import data was analyzed and segregated for the product under consideration, which was further segregated for caustic soda lye and flake/solid forms. As per DGCI&S import statistics Indonesia has exported 3745 MT of caustic soda lye during the POI. To arrive at the ex-factory export price, adjustments have been considered as provided by the domestic industry, in the absence of any response from the exporters/producers from Indonesia and any information from other interested parties. The ex-factory export price was determined as US\$****/MT for all exporters/producers from Indonesia.

EUROPEAN UNION (EXCLUDING FRANCE)

NORMAL VALUE

39. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of dumping margin. None of the exporters/producers from EC (excluding France) filed submissions and response to the questionnaire in the form and manner prescribed. Article 6.8 of the Agreement provides that in cases any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Since none of the exporters / producers from EU excluding France has filed the submissions for determination of normal value, the normal value for all

exporters/producers has been determined based on facts available as per Rule 6(8) of AD Rules.. The domestic industry has submitted that it made best efforts to procure evidence of the domestic prices prevailing in Indonesia but could not procure actual transaction prices for the period of investigation. Since actual transaction information is unavailable, the domestic industry submitted that information provided by Chlor Alkali price can be considered as a reasonable and sufficient basis for determination of normal value with appropriate adjustments. In the absence of better information, the information provided by the domestic industry from the secondary sources, i.e., Chlor Alkali price has been considered as the basis for determination of normal value with appropriate adjustments of expenses for the purpose of assessment of extent of current dumping. Investigations in respect of Taiwan-revealed that the prices published in Chlor Alkali are quite close to the actual transaction prices. In fact, investigation relating to Taiwan has shown that the prices reported in Chlor Alkali were slightly lower than the actual prices claimed by FPC thus, the Authority considers that the prices reported in Chlor Alkali are quite representative and reasonable evidence of normal value of the subject goods in subject territory. The normal value is therefore determined on the basis of prices published in Chlor Alkali. The prices were considered as delivered prices and an adjustment for possible inland freight made to determine the normal value at ex-factory level. The normal value is accordingly determined as US\$****/MT. for all exporters / producers from European Union (excluding France).

The normal value is therefore, constructed as US\$****/MT. for all exporters / producers from EU excluding France.

EXPORT PRICE:

40. The export price is determined on the basis of transaction wise import statistics provided by DGCI&S containing bill of entry no., date, country code, quantity, value, description of the product and name of the importer etc. On examination of import data it was found that the transaction wise data provided by the DGCI&S were having import data of other products also. Therefore, import data was analyzed and segregated for the product under consideration, which was further segregated for caustic soda lye and flake/solid forms. As per DGCI&S import statistics, subject territory exported 165 MT of caustic soda flakes during the POI. To arrive at ex-factory export price, adjustments have been considered as provided by the domestic industry. The ex-factory export price is determined as US\$****/MT. for all exporters / producers from EU excluding France.

E.5 DUMPING- MARGIN

41. Based on the normal value and export price as determined above for the subject goods, the Authority assessed the dumping margin as under:

Exporter/Producer	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping margin as % of Export Price
All producers /exporters from Chinese Taipei	****	****	68.93

All producers /exporters from Indonesia	****	****	165
All producers /exporters from European Union(Excluding France)	****	****	56.53

42. In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority considered the following parameters:-

1. Dumping margin determined in the original investigations;
2. Dumping margin determined in the present investigations – for the purpose, wherever exports to India existed during the investigation period, the same were considered and dumping margin determined. Where there were no exports to India during the investigation period, the Authority determined dumping margin in respect of exports to third countries and likelihood of dumping considering the normal value established and the benchmark being recommended.
3. Surplus unutilized capacities, present and potential, considering known expansions undertaken by the foreign producers, prices prevailing in India, past actual and potential volume of exports.

On examination of these factors it is noted that

- (a) Dumping margins in respect of exports to third countries are significant;
- (b) Considering the benchmark proposed to be recommended, should the exports be made below this benchmark, the same would be at dumped prices. Should the exports be made at prices above the normal value, anti dumping duty is not payable. Therefore, the exports are likely to be at dumped prices, if the imports are below the benchmark proposed to be recommended;
- (c) Ex-factory realization of export price to third countries are at such prices that should the exports be made at these prices, the resultant landed price of imports would be significantly below the selling prices in India and non injurious price;
- (d) One of the Taiwanese exporters had committed as high as 1.5 lac MT supplies against single tender, which is quite indicative of its surplus capacity and export potential;
- (e) Export price from Taiwan to third countries are significantly below not only the normal value but also the prevailing prices in India and non injurious price;
- (f) It has not been demonstrated by the exporters that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping.
- (g) Producers in Taiwan have been found to have shipped goods in the past against orders placed on third country producers/exporters.
- (h) Considering the level of capacity utilization achieved by the producers in the exporting countries in the past over the injury period and the capacity utilization achieved during the investigation period, the Authority determined unutilized capacities in Taiwan,

Indonesia and Europe. It is noted that the unutilized capacities with the Indonesia producers were to the extent of 87000 MT, while the same were to the extent of 236000 MT in case of European producers. In other words, producers in these countries can readily offer material to these extents.

(i) As per information provided by Chlor Alkali:-

Taiwan surplus capacity	54,000
Taiwan Expansion planned	466,666
Total likely surplus of Taiwan	520,666
Indonesia surplus capacity	327,000
Europe surplus capacity	1,886,000
Total Surplus	2,733,666
Indian Demand	
➤ excluding captive consumption	18,74,596
➤ including captive consumption	21,22,251

(j) As per CMAI reports, the present demand-supply situation in the world is as follows:-

Demand	5,00,31,000
Capacity	5,75,74,000
Surplus	7,543,000

As there is surplus capacity on a worldwide basis, it is noted that there is likelihood of exports from the subject countries being diverted to Indian market. Having regard to the evidence regarding capacity, production, sales and demand on record, it is noted that withdrawal of anti dumping duty would lead to dumping and on this account, the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping.

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

F.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

43. The domestic industry has submitted that;

a. Article 11.1 of AD Agreement provides that an AD duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping, which is causing injury. If there is a changed circumstance in which either dumping or injury to the domestic industry cease to exist any interested party can request for an interim review. For initiating such a review at the request of a party, there must exist an additional condition that a reasonable period of time of at least one year must have passed since the imposition of definitive measures. The Authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive antidumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset

dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both;

b. The examination of the existence of material injury in a review proceeding is similar to the process of examination in an original anti dumping investigation. The existence of material injury to the domestic industry has to be examined as laid down under Article 3 of the Anti Dumping Agreement and Annexure II to the AD Rules. In a review investigation, Designated Authority is required to examine the impact of revocation of duty. Present performance of the domestic industry is relevant only to the extent that it shows the existence or otherwise of continued injury. Improvement in the present performance may be due to anti dumping duty in force and in such a case, the Designated Authority is required to examine likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. Causal link examination may not be relevant in a review investigation. WTO Panel has ruled that causal link is not required to be examined in a sunset review investigation. Similarly in a Mid-term Review investigation also, the Indian Producers submits that the causal link is not required to be examined as the causal link had already been established in the original investigation. Notwithstanding, the Indian Producers submit that there exists a causal relationship between the recovering condition of the domestic industry and the dumping.;

44. Regarding no imports from Chinese Taipei, domestic industry has submitted that there is likelihood of recurrence of dumping and resultant injury to the domestic industry. In this regard, domestic industry has filed evidence regarding present capacity and expansion plan during next three years, domestic demand, exports from Chinese Taipei to the entire world, domestic selling price of caustic soda, export price of caustic soda exports to countries other than India, financial performance of the producers etc.

45. Domestic industry has submitted that there is significant excess capacity in Chinese Taipei for production of Caustic Soda and evidence available on records shows that the existing producers are adding further capacities. They have further stated that the present capacity in Chinese Taipei is about 50% higher than their domestic consumption and the producers, therefore, do not have any option but to sale their produce at any prices. Though, there are no exports from Chinese Taipei, however, producers from Chinese Taipei regularly participating in NALCO tenders. The price at which material is being exported by Chinese Taipei to other countries is significantly below the price at which material is being sold in the domestic market. In 20002-03 and 2003-04 Taipei's producer participated in NALCO tender and offered 150000 MT and 62000 MT to NALCO through different agents. Further, Formosa Plastics is adding significant additional capacity. The domestic industry has argued that the above situation indicates the likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if the anti dumping duty is revoked, the exporter would flood the material to India and use its additional capacity for Indian market;

46. The domestic industry has submitted the following parameters to establish causal Link;

- (a) Price sensitivity of the product:
- (b) Likely and existence of significant price undercutting
- (c) Consumers would switch over to imports

- (d) Domestic industry be forced to reduce the prices or domestic industry would be forced to loose sales volumes
 - (e) Inability of the domestic industry to affect legitimate price increases
 - (f) Sub-optimal profits
- i) The present initiation of investigations is without sufficient cause and justification with no material evidence with regard to changed circumstances;
- ii) the claim of the petitioner with regard to no dumping in the review period has to be established by the petitioner or exporters in subject countries;
- iii) no dumping in the current POI, in itself, is insufficient to revocation of duty;
- iv) facts and circumstances relating to the exporter are such that the exporter is likely to intensify its dumping activities, should the present anti dumping duties be withdrawn at this stage;
- v) onus of establishing "no dumping" and "no likelihood of dumping" is on the applicant and not on the domestic industry .
- vi) What is relevant for examination of likelihood of recurrence of injury is not limited to the planned capacities in 2005, but also the planned capacities thereafter. Even if it is admitted that the exporter has entered into long-term contracts, such contracts are not for entire additional capacities.
- vii) NALCO has pleaded for separate benchmark for lye and solid caustic soda. Indian Producers have no objection to separate benchmark being fixed for lye and solid caustic soda. There is no basis to argue that lye and solid are not one like product. Solid caustic soda is produced by further incremental processing (drying) of lye caustic soda.
- viii) The domestic industry has submitted that even assuming that cumulation cannot be done, the evidence on record clearly establishes continuance or recurrence of injury from each of the subject countries individually.

F.2 VIEWS OF THE APPLICANT, EXPORTER / IMPORTER /OTHER INTERESTED PARTIES:

47. The interested parties have submitted that
- a) Domestic industry has not provided any material evidence in support of its arguments of material injury due to dumped imports.
 - b) reliance has been placed upon the import data from DGCI&S, IBIS and the import invoices. The claim of the Indian Producers that the Indonesian prices reported in DGCI&S are correct needs to be verified by sourcing the transaction wise data from the Authorities.

- c) The Designated Authority should call costing and injury information from the original petitioner domestic industry and disclose the same to other interested parties.
- d) All the listed factors mandated under Article 3.4 of the ADA have not been examined in the Proforma IV-A by the Indian Producers. There is no causal link between alleged dumping & alleged injury. Some of the parameters like utilization of capacity, inventories, wages and exports etc. has been carried out only for the caustic soda lye and not for caustic soda in solid form and flake form.
- e) Methodology to calculate price underselling and price undercutting for Chinese Taipei as being positive has been not supported by any evidence. Prices in domestic market was significantly higher than imports price, therefore, there has been no injury and causal link. There exists no threat of injury to the domestic industry from the imports of the subject goods from Chinese Taipei.
- f) More than 12% return on capital employed by the domestic industry is already in the region of 8.5% on GFA and 15.5% on NFA basis. A ROCE of around 22%-30% is untenable. The issue of ROCE has been dealt in the Indian Spinners Association v/s. DA 2004 (170) ELT 144 (Tri -- Del) and the case should be taken as a guidance on this issue. The domestic industry has not suffered any material injury during the period of review as assessed from the injury analysis and is thus in violation of Article 3.1 and Rule 11(2) and Annexure II. All the listed factors mandated under Article 3.4 of the ADA have not been examined.
- g) ADD in force should be terminated, as the information provided by the Indian Producers is incomplete and deficient, preventing the interested parties from defending the injury allegations. There is no causal link between alleged dumping & alleged injury. Imports from the subject countries during the POR constitute 4.75% whereas the sales from the other countries correspond to 95.25% of the total Indian imports.
- h) The injury analysis carried out of the domestic industry is incomplete. Some of the parameters like utilization of capacity, inventories, wages and exports etc. has been carried out only for the caustic soda lye and not for caustic soda in solid form and flake form. The exporter is unable to verify and comment on the allegations of dumping from Chinese Taipei as evidence not disclosed by the domestic industry. Methodology to calculate price underselling and price undercutting for Chinese Taipei as being positive has been not supported by any evidence.
- i) Prices in domestic market was significantly higher than imports price, therefore, there has been no injury and causal link. There exists no threat of injury to the Domestic industry from the imports of the subject goods from Chinese Taipei. In a situation where there are no dumped imports during the POI, the essential pre-condition for levy are not satisfied. There must be dumped imports in the period of review and without dumping in the POR there can be no sustainable case for threat of material injury.
- j) The Indian Producers cannot misled the Designated Authority on the issue of increasing planned capacities by Exporters and thus threat of dumping. There is no plan for increasing the

capacities or the production quantities for 2005 by the Exporters. The increase in the capacities has been planned for the exports to Australia and other Southern American markets.

k) As regards the determination of price undercutting and price underselling, the Authority has not provided any data on the basis of which such a finding has been reached. It may be required to be disclosed since the present mid term review was initiated at the behest of the exporter. It is pertinent to note that Taiwan has stopped exporting the subject goods after the imposition of anti dumping duty therefore question of determination of undercutting and underselling does not arise.

l) They have submitted that the most of injury parameters are showing a positive trend during the period of investigation therefore there could not be any injury to the domestic industry due to imports. It has also been stated that dumped imports from subjected countries decreased in POI, especially imports from Indonesia and EU have declined drastically and there is no exports from Chinese Taipei.

F.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

48. Article 11.1 of AD Agreement provides that an AD Duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping, which causes injury. In the mid-term review the authority examines, whether the circumstances with regard to dumping and injury have changed significantly, or whether the existing measures are required to address the injury previously established. The Authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive antidumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. Present midterm review has been initiated on the basis of positive information filed by M/s Hindustan Lever Limited.

49. The Authority has taken note of the submissions made by interested parties regarding the continuation or recurrence of injury to the domestic industry and examined the same in the light of arguments made before the Authority. It is noted that duty was originally imposed on reference price basis on all imports of subject goods from subject countries. It is also noted that a review has been initiated in terms of Rule 23 of Anti Dumping Rules which requires the Authority to whether there is no justification for the continued imposition of the duty and to examine the degree and extent of dumping and injury and the need for withdrawal for duty, having regard to information provided and arguments raised by various interested parties during the course of the investigations. For the purpose, the Authority is required to first assess whether the domestic industry suffered continued injury over the relevant period. Thereafter, the Authority is required to determine whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur in the event of withdrawal of anti dumping duty.

50. For the purpose of assessing current injury, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry. The dumping margin have been established considering from EU (excluding France) and Indonesia and likelihood of dumping has been established from Chinese Taipei, EU and Indonesia. Entire

exports from EU (excluding France) and Indonesia have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination.

Cumulative Assessment of Injury

Subject countries in the present investigation are Chinese Taipei, Indonesia and European Union excluding France. Annexure II of Anti Dumping Rules provides that in case more than one country is simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles. Present investigation is a midterm review investigation initiated under Rule 23 of the Rules. The Designated Authority therefore, notes that the various conditions of cumulative assessment will apply in this investigation only on mutatis mutandis basis. Accordingly, the Authority has cumulatively assessed injury and likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

12. On examination of information, the Authority finds that the prices of the subject goods from subject countries are comparable and do not vary significantly. These have been imported under the same tariff classification. The user industry for the imported product and the domestic product is the same. The Authority has, therefore, found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article in the light of conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and domestic like product. It is appropriate to examine cumulatively the effect of injury by imports of subject goods from subject countries on the domestic industry in this investigation.

Volume Effect

13. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

Assessment of demand and market share

14. Demand or apparent consumption of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of other Indian producers and imports of the subject goods from various countries. The demand so assessed is shown in the following table.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Sales of Domestic industry	****	****	****	****
Sales of Other Indian Producers	****	****	****	****
Imports				
EU(excluding France)	22	30,982	86	165
Indonesia	4,972	42,372	18,398	3,745
Chinese Taipei	327	13,428	-	-
Imports from subject countries	5,321	86,783	18,484	3,910
Imports from other Sources	33,650	27,902	52,145	76,100
Total Imports	38,971	114,685	70,629	80,010
Demand	1,623,806	1,792,411	1,811,779	1,874,596
Indexed	100.00	110.38	111.58	115.44

55. It is seen that demand of the subject goods has shown a positive trend during the injury period. The sale of the domestic industry has improved during the injury period, which shows that the domestic industry is recovering from the effects of past dumping. It is also noted that there is continued imports of Caustic Soda from Indonesia and EU (excluding France) at dumped prices during the POI. Investigation has also shown that the exporters/producers in subject countries are likely to continue or resume export at dumped prices should the present anti dumping duties be withdrawn at this stage.

56. It is noted that low volume of imports during the POI does not establish no likelihood of injury in the event of withdrawal of anti dumping duties. Evidence on record rather suggests that the imports are likely to increase significantly in the event of withdrawal of anti-dumping duty, as noted in detail in the para relating to dumping. The Authority thus holds that the interested parties have not been able to establish that the import volumes is unlikely to increase in the event of withdrawal of anti dumping duties. On the contrary, the investigation has shown that the import volumes are likely to increase in the event of withdrawal of anti dumping duties.

Price Effect

57. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows,

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which other wise would have occurred to a significant degree."

58. In a review investigation, it is required to examine whether there has been a significant price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or

whether there is likelihood of adverse price effect after withdrawal of duty. It is observed that inspite of the imposition of the anti dumping duty, the import price of the subject goods has been significantly lower than the selling price, cost of production and non-injurious price of the domestic industry. The imports are likely to undercut the prices of the domestic industry to a significant extent in the event of withdrawal of anti dumping duties. Further, significant price undercutting is likely to have significant price depression effect on the domestic industry. It is, therefore, noted that there is likelihood of adverse price effect in the event of withdrawal of the anti dumping duties in force.

Economic parameters relating to the domestic industry

59. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an object examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

Actual and potential Production, Capacity and Capacity Utilization, Sales

60. Information on actual capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-POI
Capacity of domestic industry	910,098	910,098	910,098	910,098
Production of domestic industry	819,011	846,998	883,927	911,244
Indexed	100.00	103.42	107.93	111.26
Capacity Utilization of domestic industry	89.99	93.07	97.12	100.13
Sales of domestic industry	756,219	784,438	837,535	861,367
Indexed	100.00	103.73	110.75	113.90

It is noted that production, capacity utilization and sales of the domestic industry show positive trend during the entire injury period. Production of the domestic industry has increased in response to increase in sales with imposition of anti dumping duties on imports of Caustic Soda from various sources, including the subject countries. However, it is noted exporters from subject countries are exporting significant volume to other countries regularly, and the investigation has shown there is an excess capacity available with the producers in subject countries.

Actual and potential decline in Productivity

	2001-02	2002-03	2003-04	Jan-Dec 04
--	---------	---------	---------	------------

Productivity per employee	****	****	****	****
Productivity trend – Indexed	100.00	107.65	116.55	129.10

61. The productivity of the domestic industry improved during the injury period. It is further noted that the domestic industry has improved its performance and productivity during the POI due to anti dumping duty on imports from many sources in last four investigations.

Actual and Potential decline in Utilization of Capacity

62. Present utilization of capacity of domestic industry has been as under:

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-POI
Capacity of Domestic industry	910098	910098	910098	910098
Production of Domestic industry	819011	846998	883927	911244
Capacity Utilization of Domestic industry	89.99	93.07	97.12	100.13

Based on the above, it is noted that capacity utilization of the domestic industry has improved. Capacity utilization of the domestic industry has increased because of increase in production and sales due to antidumping duty in place on imports from various sources in earlier investigations. It is noted that the capacity of the domestic industry during the entire injury period has not increased, however, the capacity utilization has increased in the increased demand of the subject goods from 100 during 2001-2002 to 115 during the POI.

Actual and Potential decline in Sales

63. Present sales status of the Domestic industry has been as under:

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-POI
Sales of Domestic industry	****	****	****	****
Indexed	100.00	103.73	110.75	113.90

The sales of the domestic industry have increased during the entire injury period. It is also observed that the share of dumped imports from subject countries has declined from 13.65% during 2001-2002 to 5.08% during the POI, whereas the imports from other countries have increased from 86.35% during 2001-2002 to 94.92% during the POI. The volume of imports of the subject goods has increased by roughly around 100% during the POI if compared with the base year 2001-2002.

Profits, return on investment and cash flow

64. The present and likely status of Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined. Present status of these parameters of the domestic industry has been as under:

In Lacs	2001-02	2002-03	2003-04	2004-POI
Profit Before Tax	****	****	****	****
Indexed	(100.00)	(339.62)	(150.63)	14.12
Profit before interest and tax	****	****	****	****
Indexed	100.00	(3.24)	74.32	179.64
Return on Investment	5.62	(0.50)	1.84	0.04
Indexed	100.00	(8.94)	32.75	0.69
Cash Profit	****	****	****	****
Indexed	100.00	(91.77)	9.51	37.56

65. It is noted that losses to the domestic industry has increased during 2002-03, when compared with the base year and subsequently in 2003-04 and POI the losses of the domestic industry has declined when compared to 2002-03. The original investigation of the present mid term review investigation was fourth investigation of the subject goods and important dates and events of this investigation are as under:

SN	Event	Date
1	First Investigation against USA, Japan, Saudi Arabia, Iran and France (Period of investigation has been April 1998 – Sept 1999)	
	➤ Initiation of Investigation	26.05.2000
	➤ Preliminary Finding	16.11.2000
	➤ Preliminary Finding MOF	26.12.2000
	➤ Final Finding	26.12.2000
	➤ Final Finding MOF	14.05.2001
2	Second Investigation against Qatar (Period of investigation has been Jan 2001 – Sept 2001)	
	➤ Initiation of Investigation	08.10.2001
	➤ Preliminary Finding	18.01.2002
	➤ Preliminary Finding MOF	27.03.2002
	➤ Final Finding	7.10.2002
	➤ Final Finding MOF	31.10.2002
3	Third Investigation against China and Korea (Period of investigation has been 2001-02)	
	➤ Initiation of Investigation	14.05.2002
	➤ Preliminary Finding	21.09.2002
	➤ Preliminary Finding MOF	26.12.2002
	➤ Final Finding	04.08.2003
	➤ Final Finding MOF	26.12.2003
4	Fourth Investigation against Chinese Taipei, Indonesia and EU excluding France (Period of investigation has been Jan 2002 – Sept 2002)	
	➤ Initiation of Investigation	08.10.2002
	➤ Preliminary Finding	08.01.2003
	➤ Preliminary Finding MOF	27.03.2003
	➤ Final Finding	01.10.2003

➤ Final Finding MOF	14.11.2003
---------------------	------------

66. It is noted that the domestic industry was suffering due to dumped imports from Korea and China during the base year and subsequently faced injury due to dumped imports from Indonesia, Chinese Taipei and European Union (excluding France). After imposition of duty against these sources, performance of the domestic industry has improved, though, the profit of domestic industry has declined during the POI (PBT). Regarding return on investment, it is noted that the return on capital employed of the domestic industry has declined during the period of investigation. Most of the constituents of the domestic industry are multi product companies and do not maintain separate cash flow for product under consideration, therefore, the cash flow situation of the domestic industry could not be assessed. However, the cash profit of the domestic industry, which has also declined during the period of investigation.

Actual and Potential decline in market share

67. Actual and potential increase in dumped imports and its impact on market share of the domestic industry were examined. Status of imports from subject countries and share of imports in relation to production/consumption in India is given in the table below.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Imports --				
➤ EU -- Excluding France	22	30982	86	165
➤ Indonesia	4972	42372	18398	3745
➤ Chinese Taipei	327	13428	00	00
➤ Subject Countries	5321	86783	18484	3910
➤ Other Countries	33650	27902	52145	73100
➤ Total imports	38971	114685	70629	77010
Demand	1623806	1792411	1811779	1871596
Market share in imports				
➤ EU -- Excluding France	0.06	27.02	0.12	0.21
➤ Indonesia	12.76	36.95	26.05	4.86
➤ Chinese Taipei	0.84	11.71	00	00
➤ Subject Countries	13.65	75.67	26.17	5.08
➤ Other Countries	86.35	24.33	73.83	94.92
Market share in Demand				
➤ Domestic industry	46.43	43.76	46.23	46.02
➤ Other producers	51.17	49.84	49.87	49.86
➤ Subject Countries	0.33	4.84	1.02	0.21
➤ Other Countries	2.07	1.56	2.88	4.06
Imports in relation to production of domestic industry	0.65	10.25	2.09	0.43
➤ Imports in relation to sales of domestic industry	0.70	11.06	2.21	0.45

68. It is noted that market share of dumped imports from subject countries in total imports declined from 13.65% during 2001-2002 to 5.08% during the POI and the market share of

dumped imports from subject countries in demand is not significant and declined during the POI. Thus, with the existence of the present duties, market share of the imports in demand declined whereas that of the domestic industry first declined and then improved. The Authority also examined likely situation of the market share of subject countries should the present duties be withdrawn. Authority examined the status of exports from subject countries and found that the decline in dumped imports and market share is solely due to imposition of anti dumping duty on imports from various sources. Considering the price levels of the producers and exporters from subject countries to India and other countries, the information on record shows that the producers and exporters are exporting significant quantity at prices lower than prevailing prices in the Indian market. It is also noted that the exporters in subject countries are exporting to other countries at lower prices and surplus capacity is available with them. It is noted that there is no reason to believe that these producers and exporter would not be exporting significant material to India if anti-dumping duty were revoked. Given the likely volume of imports in the event of withdrawal of anti dumping duty, it is noted that the market share of the subject imports in demand is likely to once again reach significant levels.

Employment and wages

51. It is noted that most of the constituents of the domestic industry are multi product companies, therefore, there may not be direct adverse effect of dumping on employment levels of the domestic industry. Status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-POI
Employment	****	****	****	****
Indexed	100.00	96.07	92.60	86.18
Wages	****	****	****	****
Indexed	100.00	99.62	109.98	120.66

Though the employment levels of the domestic industry show a decline during the POI and no substantial argument was provided. Wages does not show any decline and rather show an increase in wages, which is reflective of the increments in wages.

Undercutting and underselling

52. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market, Designated Authority analyzed import prices over the injury period and it was found that the exporters from subject countries have continuously kept their prices at low levels in respect of their exports to India. The decline in customs duty and decline in the prices of imports have further triggered a reduction in landed price of imports. Change in cost structure if any, due to competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices

in the domestic market and it is noted that there are no viable substitute to this product and the prices were effected due to dumped prices.

71. Designated Authority determined the net sales realization of the domestic industry considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts and freight & transportation. Entire sales volumes of the domestic industry have been considered for this purpose. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The comparison is done between net sales realization and landed price of imports for caustic soda Lye and Flakes separately. A comparison for subject goods during the period under investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. With regard to Taiwan, the price at which goods were exported to third countries were used to determine whether the exports were likely to undercut the prices of the domestic industry, should the same be made at the same price at which these were made to third countries. Price undercutting in case of Taiwan was also determined considering the normal value established during the investigation period, extrapolating the same to determine landed price in order to determine whether the Taiwanese exports were expected to be at dumping prices, should the exports be made at prices equal to or less than normal value. It is found that the landed value of imports from the subject countries was lower than the net sales realization of the domestic industry for the subject goods during the POI thereby establishing that the imports are likely to undercut the selling price of the domestic industry with the withdrawal of anti dumping duties. The undercutting margins were in the range of 10% to 48% during the POI.

72. The Authority notes that price underselling is an important indicator of assessment of injury in order to determine whether the exports are likely to depress the prices of the domestic industry to a significant degree. For the purpose, the Authority considered the non injurious price determined for the domestic industry and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling the domestic industry would be forced to in case the domestic industry matches the prices. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI, normatting the capacity utilisation and providing reasonable profit on the capital employed. The analysis shows that the weighted average landed value of the subject goods from subject countries is less than the non injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margin were in the range of 17% to 56% during the POI.

73. In case of EU(excluding France) and Indonesia it was found that imports were coming at dumped prices during the POI and these prices were significantly undercutting the prices of domestic industry. Further in case of FPC and other producers from Taiwan, it was found in order to compete with the prices of imports from EU(excluding France) and Indonesia, it is likely that they too would export at prices which would undercut prices of domestic industry. The Authority notes that withdrawal of the anti dumping duty in force would provide an opportunity to the exporters to sell the material at such prices that the same is likely to depress prices of the domestic industry to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

Inventories:

74. Designated Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

	2001-02	2002-03	2003-04	Jan-Dec 04
Inventory	****	****	****	****
Trend – Indexed	100.00	132.51	103.92	93.00

Based on the above, it is noted that the inventory levels of the domestic industry showed a decline during the POI after a increase during 2002-03 and 2003-04 and the inventory level may increase in case the anti dumping duty is revoked, because revocation of duty would lead to increase in importation and decline in sales volumes of the domestic industry and consequent increase in inventories.

Growth

75. On examination of various economic parameters of the domestic industry, it is noted that various volume parameters of the domestic industry shows positive trend, which is due to anti dumping duty in force against subject countries, including other countries. It is further noted that the domestic industry has improved its performance with regard to profits, however, still the domestic industry has not been able to make reasonable profits. Thus, the Authority notes that the growth of the domestic industry has been positive with the imposition of anti dumping duties. However, given the adverse volume and price effect that the imports are likely to have in the event of withdrawal of anti dumping duties, it is evident that the growth of the domestic industry is likely to be adversely affected with the withdrawal of anti dumping duties.

Magnitude of dumping

76. It is noted that the dumping margin is substantial in the case of import from EU(excluding France) and Indonesia and likelihood of significant dumping has been established in case of withdrawal of anti dumping duties. Dumping margin determined in earlier investigation were also found to be significant. The evidence on record shows that substantial likely dumping is likely to cause injury to the domestic industry.

Factors affecting domestic prices

77. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might affecting the prices in the domestic market. It is noted that the landed value of imported material from subject country is significantly below the selling price of the domestic industry causing severe price undercutting in the Indian market. It is also noted that there is no viable substitute to this product and the domestic prices compete with one another alongwith the landed value of the imported goods. It is noted that dumped imports from several sources compete with one another and with the

domestic products are affecting the domestic markets for which cumulative injury analysis has been done. It is also found that there is a healthy demand of the product in the domestic market.

Ability to raise capital and investment

78. It is noted that the capacity of the subject goods of the domestic industry has not increased during the POI and there is no fresh investment during the POI. It is further noted that the domestic industry has not proposed any further investment.

Magnitude of injury and injury margin

79. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of exports for determination of injury margin. The weighted average landed price of the subject goods from the subject countries and the injury margins have been found to be significant.

F.4 LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY

80. The Authority has determined that the subject goods are continuing to enter the Indian market at dumped prices or are likely to be exported at dumped prices from the subject countries in the event of withdrawal of anti dumping duties. It is pertinent to examine whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed or varied. It has already been established that the actual landed value of imports from the subject countries without the antidumping duty were below the selling price of the domestic industry and the non injurious price determined for the domestic industry.

81. In addition to the examination of continued injury, likelihood of continued or recurrence of injury to the domestic industry has also been examined by the Authority on the information and evidence presented by the various interested parties during the course of the investigations. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

- (a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- (b) *Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*

- (c) *Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,*
- (d) *Inventories of the article being investigated."*

82. The interested parties have provided information regarding capacity, production and demand of subject goods of the exporting countries. It is noted that in the present case, the volume of imports over the injury period, the level of import prices of subject goods from non subject countries, the export price of the cooperative exporter to other countries, surplus capacities available with the exporters suggest that revocation of anti dumping duty would likely result in significant increase in volume of dumped imports from subject countries. In a situation where the goods have been exported to India inspite of anti dumping duty in force, the volume of dumped imports is likely to increase further, in case the present anti dumping duties are withdrawn.

83. Producers/exporters from some of the subject countries have been supplying the subject goods in significant volumes to industrial consumers in India such as NALCO. It is noted that during the last three years, domestic industry has been able to get substantial orders for supply to NALCO, one of the major importers of the subject goods in the past, which is evident from the followings:

Status of NALCO tenders:	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
Qty in MT as per tender	100000	115000	120000	120000	120000
Foreign offers received	352000	262000	86000	38000	118000
Indian offer received	83000	122000	134000	127400	147000
Order placed to foreign suppliers	100000	30000	32000	18000	0
Order placed to Indian suppliers	0	20000	88000	102000	120000

84. It is noted that Indian producers have improved their share of supply of subject goods to NALCO during the injury period after imposition of anti-dumping duty and during 2005-06 they have bagged the entire quantity of supplies. However, NALCO continues to and is likely to continue to source its requirement through international competitive bidding process. In the present situation, withdrawal of present anti-dumping duties is likely to create intense competition and the foreign producers are likely to offer dumped prices which would result in recurrence of injury to the domestic industry. The cumulative surplus capacity available with the exporters in subject countries is higher than the entire consumption in India, and the investigations in the past have shown that the market for caustic soda is highly volatile and any significant volume of exports made to India at likely dumped prices is likely to lead to price depressing and consequently injury to the domestic industry. No cogent reason has been provided by the interested parties why the surplus capacities in the subject countries would not be used to supply the material to the Indian market. Nor any cogent reason advanced why the

likely prices would be higher than the present export prices to India or third countries and normal values in the exporting countries.

85. In case of Taiwan, only one of the exporters from Chinese Taipei has cooperated and filed information with regard to production, sales, capacity and exports to other countries. The company has also provided information regarding production, demand and exports to other country from Chinese Taipei. As regards the FPC, it is noted that only verified data has been considered for determination of likelihood of dumping and injury. Information regarding the entire country was also provided by FPC in Chinese Taipei. The export price of FPC has revealed that FPC was exporting the subject good to various countries at prices below the domestic selling prices in India, and should FPC export to India at or below the normal value, the landed price of imports would be above the domestic price in India and below the non injurious price determined for the domestic industry, thus showing likelihood of increase in dumped imports in Indian market which is likely to cause injury to the domestic industry. Should Taiwanese producers sell at normal values established then the landed price of imports would be significantly higher than the domestic prices in India, thus establishing that the Taiwanese producers would have to export at prices significantly below normal value. However, any export at or below the normal value would be significantly below the non-injurious price established for the domestic industry.

86. In order to assess the likely effect of the expiry of measures in force, it is noted that there are clear indications that the subject countries have the potential to raise their production and export volumes. On the basis of export price established in dumping examination, it is likely that in absence of measures the producer from the subject countries could adopt a policy of dumped prices, will cause further injury to the domestic industry which has recovered and improvement has been shown due to the anti-dumping duty in place against dumped imports from subject countries. The possibility for the exporting producers from these countries to lower their prices in view of the dumping and likely dumping can not be overlooked and denied. Such a price behavior of subject countries producers coupled with their ability to deliver significant quantities of subject goods, would in all likelihood have a general price depressing impact on what is very price sensitive commodity market. In view of this it is concluded that should the measures be revoked, there is likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

87. The applicant and other interested parties have argued since there is no evidence of injurious dumping to the domestic industry during the period of review, the Designated Authority is required to examine whether the injury is likely to recur, should the measures are revoked. They have argued since the domestic industry did not submit evidence regarding the likely volume of imports from subject countries in a situation of revocation of duty and the likely prices at which such imports would be made and likely impact on the domestic industry due to such imports. The applicant has further submitted that the domestic industry has made their claim without substantiation regarding sufficient disposal capacity available with foreign producers and likely dumping in future. The sole responding exporter has argued that their production is fully utilised that it has neither sufficient disposable capacity for export nor any abnormal inventory of the subject goods. The wild allegations cannot form the basis of any apprehension for future likelihood of injurious dumping. They have argued that

there is no anti dumping measures against FPC that it would result in diverting the subject goods from such country to the Indian market.

88. The domestic industry contended that the exporters from EU (except France) and Indonesia continued to export the subject goods at dumped prices in the Indian market and producers in the subject countries are likely to resort to dumping of subject goods in the Indian market. The capacities in subject countries are much higher than their respective domestic sales/demand. In case of Chinese Taipei, in addition to the present surplus available, massive expansion being undertaken by FPC, which was originally due for commercial production in Aug., 2005 and details of which are available on the website of FPC itself also need be taken into account for determination of likelihood of injury [it is reiterated that FPC has not provided relevant documents in support of their claim that entire expansion was meant for third countries and no surplus would have been available for exports to other countries]. The domestic industry repeated stressed that the price difference between the domestic and imported material has been so huge that there is no reason to believe that these subject countries would not divert significant volumes of the subject goods to the Indian market in case the anti dumping duties are withdrawn.

89. The arguments and submissions made by the interested parties were examined having regard to the information/evidence made available by these interested parties and on record of the Authority about the present and potential capacity, production, sales, imports, exports, domestic demand, the price levels in respect of domestic sales, exports to third countries and India, likely prices of imports from the subject countries. In order to determine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, the Authority considered the following parameters:-

1. Dumping margin determined in the original investigations;
2. Dumping margin determined in the present investigations – for the purpose, wherever exports to India existed during the investigation period, the same were considered and dumping margin determined. Where there were no exports to India during the investigation period, the Authority determined dumping margin in respect of exports to third countries and likelihood of dumping considering the normal value established and the benchmark being recommended.
3. Surplus unutilized capacities, present and potential, considering known expansions undertaken by the foreign producers, prices prevailing in India, past actual and potential volume of exports.

On examination of these factors it is noted that;

- (a) Dumping margins in respect of exports to third countries are significant;
- (b) Considering the benchmark proposed to be recommended, should the exports be made below this benchmark, the same would be at dumped prices. Should the exports be made at prices above the normal value, anti dumping duty is not payable. Therefore, the exports are likely to be at dumped prices, if the imports are below the benchmark proposed to be recommended;

- (c) Ex-factory realization of export price to third countries are at such prices that should the exports be made at these prices, the resultant landed price of imports would be significantly below the selling prices in India and non injurious price;
- (d) One of the Taiwanese exporters had committed as high as 1.5 lac MT supplies against single tender, which is quite indicative of its surplus capacity and export potential;
- (e) Export price from Taiwan to third countries are significantly below not only the normal value but also the prevailing prices in India and non injurious price;
- (f) It has not been demonstrated by the exporters that withdrawal of anti dumping duty would not lead to likelihood of injury to the domestic industry and continued imposition of the duty was unnecessary to offset dumping.
- (g) Producers in Taiwan have been found to have shipped goods in the past against orders placed on third country producers/exporters.
- (h) Considering the level of capacity utilization achieved by the producers in the exporting countries in the past over the injury period and the capacity utilization achieved during the investigation period, the Authority determined unutilized capacities in Taiwan, Indonesia and Europe. It is noted that the unutilized capacities with the Indonesia producers were to the extent of 87000 MT, while the same were to the extent of 236000 MT in case of European producers. In other words, producers in these countries can readily offer material to these extents.
- (i) As per information provided by Chlor Alkali:-

Taiwan surplus capacity	54,000
Taiwan Expansion planned	466,666
Total likely surplus of Taiwan	520,666
Indonesia surplus capacity	327,000
Europe surplus capacity	1,886,000
Total Surplus	2,733,666
Indian Demand	
➤ excluding captive consumption	18,74,596
➤ including captive consumption	21,22,251

- (j) As per CMAI reports, the present demand-supply situation in the world is as follows:-

Demand	5,00,31,000
Capacity	5,75,74,000
Surplus	7,543,000

- (k) It is noted that the exporter has not placed any convincing evidence on record that injury will not recur in event of withdrawal of measures. Having regard to the evidence regarding capacity, production, sales and demand on record, it is noted that withdrawal of anti dumping duty would likely to continuance or recurrence of injury to the domestic industry. Therefore, it is concluded that the evidence on records clearly establishes that injury would recur in event of measures are withdrawn.

16906 I/2006-13

Conclusion

90. Considering the above and having regard to the contentions of the interested parties and information/evidence on record, the Authority holds that

- a) The performance of the domestic industry has shown an improvement with the imposition of anti dumping duties. However, the same has not reached a satisfactory level. The situation of the domestic industry continues to be fragile,
- b) Injury to the domestic industry is likely to continue or recur should the present measures be withdrawn.

CAUSAL LINK

91. Submissions made by the interested parties in respect of the issue of causal link have been examined. A detailed examination was made with regards to the issues pertaining to the injury to the domestic industry and causal link between the material injury to the domestic industry and dumped imports. Paragraph (v) of Annexure II of the Anti-dumping Rules reads as under:

"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry."

OTHERS KNOWN FACTORS

92. The Authority examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

Volume and prices of imports from other sources

Imports from various countries have been as under:-

MT	2001-2002	2002-2003	2003-2004	POI
Subject countries	5321	86783	18484	39130
Countries attracting ADD	29805	16304	29688	33463
Countries Not	3845	11598	22457	42637

attracting ADD				
Total imports	38971.	114685	70629	80010
Share in imports				
Subject countries(%)	13.65	75.67	26.17	4.89
Countries attracting ADD	76.48	14.22	42.03	43.45
Countries Not attracting anti dumping duty	9.87	10.11	31.80	55.37

93. During the POI, in addition to the subject imports, imports have taken place from a number of other countries. Total import from other sources increased from 33650 MT during 2001-2002 to 76100 MT during POI. It is also noted that the weighted average import price from sources not attracting anti dumping duty is more than the dumped price or the likely prices from the subject countries. Therefore, it is noted that the imports from the other sources did not appear to have had significant effect on the domestic industry, both in terms of volume and value.

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Demand	1623806	1792411	1811779	1874596
Indexed	100	110	112	115

94. Total domestic demand of the product under consideration has increased from 1623806 MT during 2001-2002 to 1874596 MT during the POI. It is noted that the demand has consistently increased during the entire injury period. Thus, possible contraction in demand is not a factor that could have caused injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

95. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The domestic industry consists of 10 producers of the subject goods out of 37 producers of caustic soda in the Country. The Indian Producers competes among one another and at the same time compete with the landed price of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced by the landed price of subject goods. Present situation of likely injury to the domestic industry cannot be attributed to trade restrictive practices or fair competition between foreign and domestic producers.

Developments in technology and export performance

96. The production facilities of the cooperative foreign producer and the production facility of the domestic industry were found to be of similar technology. There are three technologies for production of the subject goods and all the three forms continue to be deployed. Even though a number of companies are upgrading their technology from mercury to membrane, it is found

that this process of change is not a new phenomena, nor the investigations revealed that the producers with latest technology have lower full cost of production or non injurious price. Technology or technology related issues have not been raised by any interested party as a possible cause of injury to the domestic industry. It is noted that the domestic industry has exported small quantity of subject goods during the POI that does not substantially affect the operations of the company. The export performance of the domestic industry is thus insignificant if compared with the entire sales of the domestic industry, therefore, export turnover does not affect performance of the domestic industry.

Productivity of the Domestic Industry

97. Productivity of the domestic industry in terms of labour output and daily output has shown a growth during the POI compared to the base year. It is also noted that productivity has shown a growth during the entire injury period along with growth in production and sales.

98. It is noted that market share of the domestic industry first declined in 2002-03 and thereafter increased again to almost the level of 2001-02. The landed value of the subject goods during the period of investigation were much below the net sales realization and the non injurious price determined for the domestic industry and were thus significantly undercutting the domestic selling prices. Should the exports undercut the prices of the domestic industry, the same is likely to have adverse volume and/or price effect and would be at dumping prices. It is also noted that should the exports be made at prices on or above normal value, the landed price of imports would be significantly higher than the current selling price of the domestic industry. Any exports to India are likely at prices close to or below the selling price of the domestic industry, which would clearly be at dumping prices.

It is thus concluded that likely injury to the domestic industry in the event of withdrawal of anti dumping duty would be due to dumped imports.

H. FINAL FINDINGS:

99. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

i) the subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from EU(excluding France), Indonesia and Chinese Taipei are substantial and above de-minimis. The subject goods are likely to enter Indian market at dumped prices, should the present measures be withdrawn. Thus, it has not been established that the continued imposition of the duty to offset dumping is unwarranted,

ii) even though the domestic industry has improved its performance over the injury period, the situation of domestic industry continues to be fragile. Further, should the present anti dumping duties be withdrawn, injury to the domestic industry is likely to continue or recur. Thus, it has not been established that injury to the domestic industry is unlikely to continue or recur should the present measures be withdrawn.

100. Having concluded that the situation of the domestic industry continue to be fragile and there is likelihood of continuation or resumption of dumping and injury on account of imports from EU(excluding France), Indonesia and Chinese Taipei if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is necessary against import from these countries. However, in view of the current level of dumping from EU(excluding France), Indonesia and Chinese Taipei and injury suffered by the domestic industry the anti dumping duty in force needs to be revised. Therefore, the Authority considered it necessary and recommends continuation of anti dumping duty on imports of subject goods from EU(excluding France), Indonesia and Chinese Taipei.

101. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty on all imports of Caustic soda from EU(excluding France), Indonesia and Chinese Taipei in order to remove the injury to the domestic industry. The Authority recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the weighted average non-injurious price of the domestic industry determined for the period of investigation.

102. Accordingly, the Authority recommends that definitive anti dumping duties as set out below be imposed by the Central Government on all imports of Caustic soda falling under customs heading 2815.11 & 2815.12 originating in or exported from EU(excluding France), Indonesia and Chinese Taipei. The anti-dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column no.9 of the following table and the landed value of imports per MT on all imports of subject goods falling under chapter 28 of the Customs Tariff, originating or exported from the subject territory/countries mentioned below:-

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (US\$)	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any Producer	Any Exporter	281.27	DMT	USD
2	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Indonesia and Eu(excluding France)	Chinese Taipei	Any Producer	Any Exporter	281.27	DMT	USD
3	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Chinese Taipei	Any country other than	Any Producer	Any Exporter	281.27	DMT	USD

					Indonesia and Eu(excluding France)					
4	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Indonesia	Indonesia	Any Producer	Any Exporter	256.88	DMT	USD
5	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Chinese Taipei and Eu(excluding France)	Indonesia	Any Producer	Any Exporter	256.88	DMT	USD
6	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Indonesia	Any country other than Chinese Taipei and Eu(excluding France)	Any Producer	Any Exporter	256.88	DMT	USD
7	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	EU(excluding France)	EU(excluding France)	Any Producer	Any Exporter	295.46	DMT	USD
8	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	Any country other than Chinese Taipei and Indonesia	EU (Excluding France)	Any Producer	Any Exporter	295.46	DMT	USD
9	2815.11 & 2815.12	Caustic Soda	Any grade	EU(excluding France)	Any country other than Chinese Taipei and Indonesia	Any Producer	Any Exporter	295.46	DMT	USD

103. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

104. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall normally be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time stipulated for this purpose.

105. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (as amended).

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority